

## वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और उनका निष्पादन

2009-10 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत निष्पादन कम रहा जिसमें आस्ति गुणवत्ता के संबंध में उभरती हुई चिंताएं तथा धीमी जमा वृद्धि सम्मिलित है। सकल एनपीए जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सकल अग्रिमों के अनुपात रूप में है, 2008-09 के 2.25 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में समग्र रूप से 2.39 प्रतिशत हो गया। कमजोर हो रही आस्ति गुणवत्ता के बावजूद भारतीय बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 14.5 प्रतिशत की मजबूती पर कायम रहा जो बासेल II फ्रेमवर्क में गमन के बाद भी विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से अधिक था और बैंकों को होनेवाली हानियों के लिए पर्याप्त कुशन उपलब्ध करता था। 2009-10 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा प्राप्त भारतीय बैंकों की लाभप्रदता पिछले वर्ष के 1.13 प्रतिशत से मामूली कम अर्थात् 1.05 प्रतिशत थी। वैश्विक तुलना में वित्तीय पहुंच और समावेशन का न्यून स्तर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए चिंताजनक बना रहा। अल्पावधि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि वह आर्थिक रिकवरी की प्रक्रिया को अपना समर्थन दे जबकि मध्यम और दीर्घावधि में आवश्यक है कि वह स्वयं को बदलकर कुशल तथा सशक्त बनाए ताकि आर्थिक वृद्धि की धारणीयता तथा समावेशन स्वरूप को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके।

### 1. परिचय

4.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को कर्ज देने के माध्यम तथा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने के रूप में वाणिज्य बैंक भारतीय वित्तीय परिदृश्य का सर्वाधिक प्रमुख भाग हैं। आर्थिक सुधारों के प्रारंभ से ही वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र, जिसने अपने सार्वजनिक चरित्र को प्रमुखता से बनाए रखा है, आकार, परिचालन कुशलता और वित्तीय सुदृढ़ता के अर्थ में कई तरह के परिवर्तनों से गुजरा है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रसार के पूर्व विश्व बैंक द्वारा 2005 के लिए किए गए विश्लेषण के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की परिचालनात्मक कुशलता और वित्तीय सुदृढ़ता इसके एशियन पियर समूह देशों और साथ ही विकसित ओईसीडी देशों की तुलना में अच्छी थी।<sup>1</sup> वैश्विक वित्तीय संकट, जिसने अधिकांश विकसित और विकासशील देशों के बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर बनाया, का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में

अपेक्षाकृत रूप से सीमित प्रभाव पड़ा। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और विकास (आरटीपी) - 2008-09 रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि यद्यपि भारतीय बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर संकट के दबावों को सह गयी, किन्तु यह आशा नहीं थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस मंदी से अपने को अलग रख पाएगी जो संकट के बाद जन्मी थी। इस प्रकार 2009-10 में बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर संकट के मध्यावधि से दीर्घावधि प्रभाव की प्रकृति और उसके विस्तार को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

4.2 इस अध्याय में 81 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)<sup>2</sup> से आंकड़ों को लेते हुए तुलनापत्र, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा लाभप्रदता और बैंकिंग जगत की वित्तीय मजबूती के रुझानों को प्रकट करने के प्रयोजन से पिछले वर्ष के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकिंग जगत में हुए विकास का

<sup>1</sup> विश्व बैंक अध्ययन में उपयोग किए गए परिचालनात्मक कुशलता के प्रमुख संकेतक आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ हैं जबकि वित्तीय सुदृढ़ता मानदंडों में पूंजी पर्याप्तता और सकल एनपीए अनुपात सम्मिलित हैं। वैश्विक रूप में इन संकेतकों में से प्रत्येक की तुलना में भारत की स्थिति अन्य एशियन और ओईसीडी देशों से बेहतर थी सकल एनपीए अनुपात को छोड़कर। भारत के लिए सकल एनपीए अनुपात एशियन देशों की बराबरी में था परंतु ओईसीडी देशों की तुलना में काफी अच्छा था। देखें किएटचय सोफस्टिनफोंग एंड एनोमा कुलथुंगा (2009), *गोटिंग फाइनेन्स इन साउथ एशिया 2009 - इंडिकेटर एण्ड एनालिसिस ऑफ दि कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर*, वर्ल्ड बैंक।

<sup>2</sup> इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके छः सहयोगी, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आइडीबीआइ बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के 15 पुराने बैंक और 32 विदेशी बैंक शामिल हैं।

विस्तार से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग जगत के परिचालन से संबंधित कई पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का भी वर्णन किया गया है जैसे वित्तीय समावेशन, कर्ज का क्षेत्रवार वितरण, बैंकिंग सेवाओं का स्थानीय और क्षेत्रीय वितरण, ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी विकास तथा साथ ही अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्र के दो घटकों अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक से संबंधित रुझानों का अलग से विश्लेषण किया गया है।

## 2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

4.3 पिछले वर्ष देखे गए रुझान के अनुक्रम में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र की वृद्धि में 2009-10 में

कमी हुई (सारणी IV.1 और 2)। विशेषकर, विदेशी बैंकों की आस्ति की मात्रा में 2009-10 में 2.7 प्रतिशत कमी देखी गई (सारणी IV.2)। विदेशी बैंकों की आस्ति में इस कमी से पिछले कुछ समय पूर्व के उस रुझान पर रोक लगी जब विदेशी बैंकों की आस्तियों में अनवरत 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह शामिल हैं) और साथ ही निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के तुलनपत्र की वृद्धि में 2009-10 में कमी हुई। केवल निजी क्षेत्र के नए बैंक इसके अपवाद थे, जिन्होंने 2008-09 में अपने पुराने समकक्ष बैंकों की तुलना में कम बेहतर प्रदर्शन किया था और 2009-10 में इन्होंने त्वरित वृद्धि दिखाई।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2010 के अंत में				विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक		
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजी	13,544	4,549	1,273	3,276	30,555	48,648
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	2,27,458	1,15,435	18,898	96,537	38,584	3,81,476
3. जमा राशियां	36,91,802	8,22,801	2,29,897	5,92,904	2,37,853	47,52,456
3.1. मांग जमा	3,68,528	1,34,589	21,597	1,12,992	67,902	5,71,019
3.2. बचत बैंक जमा राशियां	8,87,267	1,86,220	43,567	1,42,653	36,427	11,09,915
3.3. सावधि जमा	24,36,006	5,01,992	1,64,733	3,37,259	1,33,524	30,71,522
4. उधार	3,13,814	1,48,803	8,127	1,40,676	62,146	5,24,764
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	1,94,497	59,221	10,783	48,438	64,080	3,17,798
<b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>	<b>44,41,114</b>	<b>11,50,809</b>	<b>2,68,977</b>	<b>8,81,831</b>	<b>4,33,219</b>	<b>60,25,141</b>
1. आरबीआइ के पास नकदी और शेष	2,70,858	75,858	16,915	58,943	1,19,097	3,65,812
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	1,24,216	38,681	5,692	32,989	20,559	1,83,455
3. निवेश	12,05,783	3,54,117	83,499	2,70,618	1,59,286	17,19,185
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	10,08,371	2,41,192	60,819	1,80,374	1,17,492	13,67,055
क) भारत में	10,00,015	2,41,028	60,819	1,80,209	1,17,492	13,58,534
ख) भारत के बाहर	8,356	165	-	165	-	8,521
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	5,015	311	289	21	4	5,330
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,92,396	1,12,614	22,391	90,223	41,790	3,46,800
4. ऋण और अग्रिम	27,01,300	6,32,494	1,54,136	4,78,358	1,63,260	34,97,054
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1,40,817	27,462	8,957	18,505	21,306	1,89,585
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि.	10,74,500	1,58,719	68,119	90,600	65,923	12,99,141
4.3 सावधि ऋण	14,85,984	4,46,313	77,060	3,69,252	76,031	20,08,328
5. अचल आस्तियां	34,466	10,239	2,357	7,882	4,859	49,564
6. अन्य आस्तियां	1,04,491	39,421	6,378	33,043	66,158	2,10,070

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

**सारणी IV.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि**

(प्रतिशत)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	3.6	0.1	-8.1	7.3	8.2	8.7	-13.1	6.7	14.5	19.8	8.3	12.4
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	20.5	16.8	10.0	21.0	14.6	15.9	9.1	22.0	27.3	12.1	17.8	17.5
3. जमा राशियां	26.9	18.6	9.1	11.7	20.3	15.4	5.4	10.4	12.0	11.1	22.4	17.0
3.1. मांग जमा	9.9	18.4	1.3	33.5	1.8	22.5	1.1	35.9	2.3	12.1	6.9	20.8
3.2. बचत बैंक जमारशियां	18.4	25.8	14.9	32.8	15.6	26.2	14.7	34.9	9.7	26.5	17.5	26.9
3.3. सावधि जमा	33.1	16.2	9.2	1.3	24.2	12.0	3.9	-3.1	18.0	7.0	27.3	13.1
4. उधार	65.3	21.4	56.6	8.1	77.4	31.8	55.7	6.9	32.9	-19.8	56.5	10.8
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	-21.4	4.4	-37.0	9.7	-7.8	15.0	-41.0	8.5	43.4	-31.6	-13.9	-4.8
<b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>	<b>24.6</b>	<b>17.9</b>	<b>9.3</b>	<b>12.0</b>	<b>19.4</b>	<b>15.8</b>	<b>6.7</b>	<b>10.9</b>	<b>22.3</b>	<b>-2.7</b>	<b>21.1</b>	<b>15.0</b>
1. आरबीआइ के पास नकदी और शेष	-2.4	20.8	-19.4	32.0	-14.6	27.7	-20.7	33.3	-28.9	22.1	-8.0	23.1
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	106.5	-5.4	32.7	13.9	46.0	-43.3	27.8	38.0	56.8	-34.2	80.1	-6.6
3. निवेश	26.6	19.1	10.0	15.5	33.9	15.3	4.3	15.6	31.8	22.2	23.1	18.6
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	30.6	19.0	12.4	10.6	27.3	13.4	8.2	9.7	20.7	17.5	25.9	17.3
क) भारत में	30.8	18.8	12.4	10.6	27.3	13.4	8.3	9.7	20.7	17.5	26.0	17.2
ख) भारत के बाहर	4.0	48.3	-32.0	72.6	-	-	-32.0	72.6	-	-	3.1	48.7
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-22.8	-36.8	-22.8	43.4	-24.3	56.2	-12.0	-31.7	-80.7	-41.7	-23.0	-34.6
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	11.9	22.2	4.7	27.6	58.8	20.5	-4.0	29.5	89.3	37.7	14.6	25.6
4. ऋण और अग्रिम	25.7	19.6	11.0	9.9	15.1	19.9	9.9	7.1	2.6	-1.3	21.1	16.6
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	18.3	10.4	-23.5	30.7	7.0	19.1	-33.9	37.2	-8.0	46.9	8.0	16.3
4.2 केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि.	29.3	20.0	11.5	9.6	15.0	20.8	9.3	2.5	7.0	-7.5	25.1	16.9
4.3 सावधि ऋण	24.0	20.2	13.4	9.0	16.2	19.3	12.9	7.0	1.1	-4.5	20.1	16.4
5. अचल आस्तियां	17.2	2.1	2.6	3.6	8.0	8.0	1.2	2.4	19.4	2.6	14.1	2.5
6. अन्य आस्तियां	2.0	-0.2	21.6	-11.5	35.1	7.8	19.8	-14.5	68.1	-32.3	25.1	-15.0

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

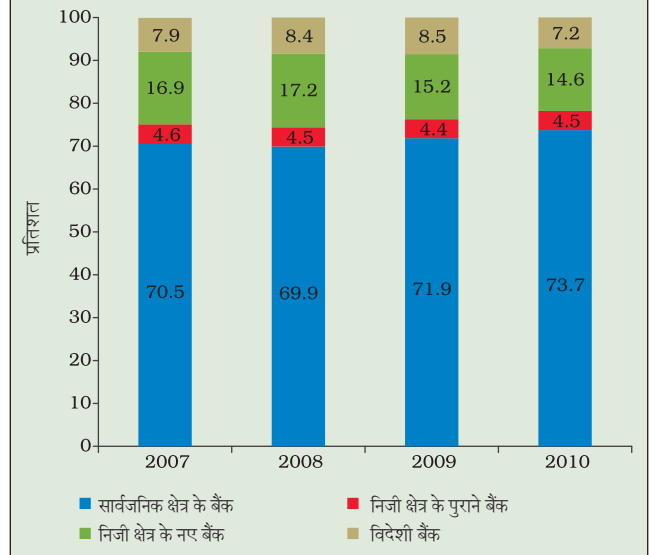
4.4 विदेशी बैंक समूह के तुलनपत्र में संकुचन के परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों की भागीदारी में गिरावट देखी गई (चार्ट IV.1)। बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों की भागीदारी में भी गिरावट हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों की कम वृद्धि के बावजूद, 2009-10 में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनके सापेक्षिक हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का हिस्सा पिछले वर्ष के स्तर से लगभग अपरिवर्तित रहा।

**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं**

**जमाराशियां**

4.5 2009-10 में तुलनपत्र की वृद्धि में कमी मोटे तौर पर जमाराशि की वजह से हुई, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं का प्रमुख घटक है, (सारणी IV.1 और IV.2)। बैंक

**चार्ट IV. 1: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा**



जमाराशियों में, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं की लगभग 78 प्रतिशत हैं, 2007-08 से लगातार तीसरे वर्ष

कम वृद्धि दर्ज हुई। 2009-10 में जमाराशि की वृद्धि में हुई गिरावट के कारकों में से एक वर्ष के दौरान अधिकांश समय कम ब्याज दर प्रचलित होना था।

4.6 तथापि, जमाराशि के घटक में 2009-10 के दौरान काफी अधिक परिवर्तन दिखे साथ ही चालू तथा बचत खाते (कासा) का प्रतिशत कुछ समय पहले हुए गिरावटी रुझान के विपरीत 2008-09 तथा 2009-10 के बीच 33.2 प्रतिशत से बढ़कर 35.4 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पहले से भिन्न, चालू एवं बचत खाते ने 2009-10 में वृद्धिशील जमाराशि के लगभग आधे भाग में अपना योगदान दिया (चार्ट IV.2)। 2009-10 में जमाराशि की कुल वृद्धि में अकेले बचत खाता जमाराशि ने लगभग 34 प्रतिशत का योगदान दिया। बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर ब्याज दर की गणना से भी बचत खाता जमाराशि में और तेजी आने की संभावना है।

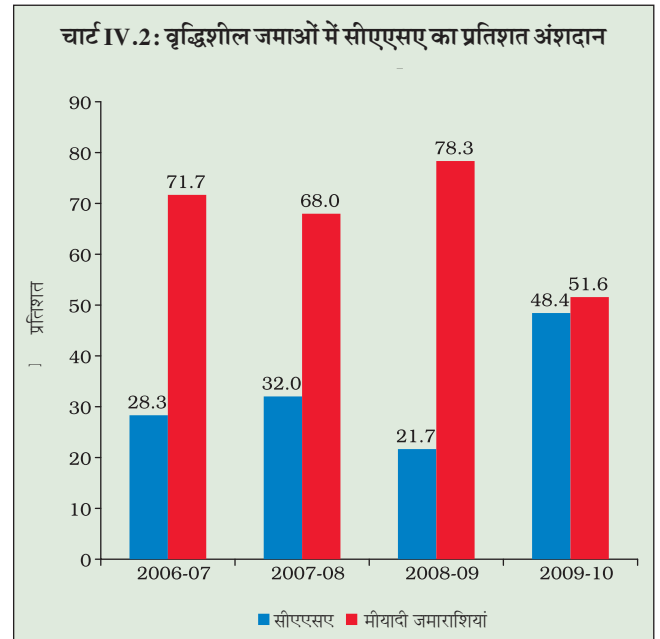
## उधार

4.7 उधार, जो बैंकों में जमाराशि से इतर प्रमुख देयता है, का 2009-10 में बैंकों की कुल देयताओं में 8.7 प्रतिशत भाग था। जमाराशि की भांति ही उधार की वृद्धि में भी तेज गिरावट देखी गई और परिणामस्वरूप 2009-10 में बैंक के तुलनपत्र में समग्र गिरावट दर्ज हुई (सारणी IV.1 तथा 2)। उधार की वृद्धि में कमी सभी बैंक समूहों में देखी जा सकती है, लेकिन विदेश बैंकों में यह कमी उल्लेखनीय थी (सारणी IV.2)।

## अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां

### बैंक कर्ज

4.8 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की भांति ही बैंक कर्ज की वृद्धि में कमी हुई। बैंक कर्ज, जो 2004-05 में 30 प्रतिशत से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया था, में बाद के वर्ष में अनवरत गिरावट हुई और 2009-10 में यह 16.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गया। चूंकि बैंकों के लिए जमाराशियां निधि का सबसे

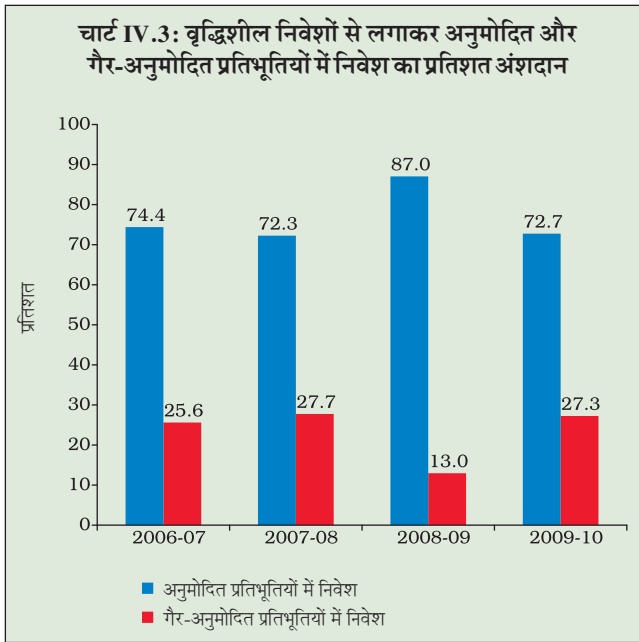


महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए इसकी वृद्धि में कमी बैंक के कर्ज वृद्धि की कमी में परिणत होने की संभावना है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत आने और बैंकों की निम्न ब्याज-दर व्यवस्था के बावजूद, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2009-10 में बैंक कर्ज वृद्धि में कमी देखी गई। तथापि, एक वर्ष के भीतर नवंबर 2009 के बाद आर्थिक रिकवरी के अधिक व्यापक होने के साथ ही बैंक कर्ज में तेजी के संकेत दिखे।<sup>3</sup>

## निवेश

4.9 2009-10 में, बैंक कर्ज की भांति ही, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश की वृद्धि में कमी देखी गई। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश के घटक में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर था, जैसाकि 2009-10 में वृद्धिशील निवेश की तुलना में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के योगदान के प्रतिशत में कमी आई, जबकि 2008-09 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जब बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप बाजार अनिश्चितता के मद्देनजर कम जोखिम निवेशों में प्राथमिकता दिखाई थी (चार्ट IV.3)।

<sup>3</sup> इस मुद्दे पर व्याख्या के लिए खंड 5 में चार्ट IV.19 देखें।



4.10 2009-10 में बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश, जिसमें म्यूच्युअल फंड, बांड/डिबेंचर, शेयर और वाणिज्यिक पत्र में निवेश शामिल है, में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। गैर-एसएलआर निवेश में यह वृद्धि मुख्यतया म्यूच्युअल फंड में निवेश की वजह से हुई जो वर्ष के दौरान 42.8 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गए, यद्यपि इसमें एक वर्ष के भीतर अस्थिरता देखी गई (सारणी IV.3)। बांड तथा डिबेंचर, जो बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश के एक बड़े भाग हैं, के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावटी रुझान देखा गया। वित्तीय संकट के बाद पूंजी बाजार में निरुत्साही दशाओं के परिणामस्वरूप 2008-09 में शेयरों के निवेश के हिस्से में तेज गिरावट देखी गई जिसमें आगे 2009-10 में और मामूली गिरावट हुई (चार्ट IV.4)। इस प्रकार, बैंक के निवेश संविभाग में बांड/डिबेंचर तथा शेयरों में निवेश के कम होते महत्व के विपरीत, हाल के वर्षों में म्यूच्युअल फंड में निवेश के हिस्से में एक समान वृद्धि हुई।<sup>4</sup>

### सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

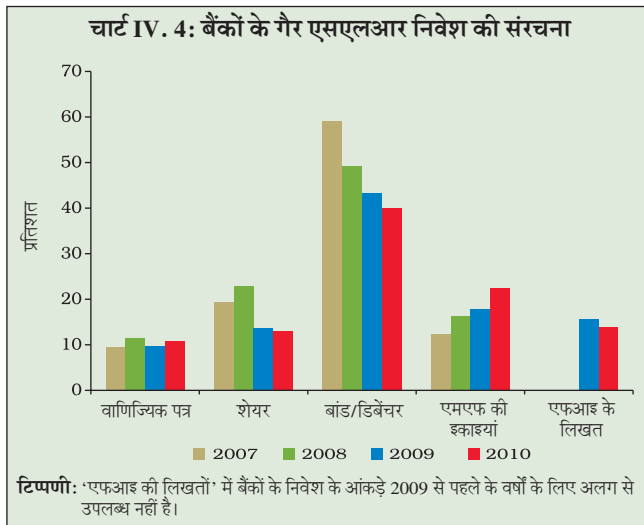
लिखत	26 मार्च 2010 को	कुल की तुलना में प्रतिशत	24 सितंबर 2010 को	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
<b>1. वाणिज्यिक पत्र</b>	<b>25,188</b>	<b>10.7</b>	<b>43,818</b>	<b>17.7</b>
	(25.9)		(195.5)	
<b>2. शेयर</b>	<b>30,192</b>	<b>12.9</b>	<b>37,703</b>	<b>15.2</b>
	(6.9)		(39.7)	
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4,625	2.0	7,070	2.9
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	25,481	10.9	27,029	10.9
<b>3. बांड / डिबेंचर</b>	<b>93,679</b>	<b>39.9</b>	<b>1,05,664</b>	<b>42.7</b>
	(4.5)		(13.3)	
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	22,710	9.7	20,153	8.1
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	40,067	17.1	50,332	20.3
<b>4. म्यूच्युअल फंड की इकाइयां</b>	<b>52,887</b>	<b>22.5</b>	<b>33,534</b>	<b>13.6</b>
	(42.8)		(-46.3)	
<b>5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखत*</b>	<b>32,597</b>	<b>13.9</b>	<b>26,725</b>	<b>10.8</b>
	(0.04)		(3.2)	
<b>कुल निवेश (1 से 5)</b>	<b>2,34,543</b>	<b>100.0</b>	<b>2,47,444</b>	<b>100.0</b>
	(13.0)		(10.8)	

**टिप्पणी:** 1) कोष्ठक के आंकड़े वर्ष पूर्व की तदनु रूप अवधि में प्रतिशत भिन्नता को दर्शाते हैं।

2) \*: 2008-09 के बाद वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखतों को अलग से दिखाया जा रहा है। पहले के वर्षों में, उन्हें डिबेंचरों और बांडों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था।

**स्रोत:** अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत खंड 42(2) की विवरणियां।

<sup>4</sup> 2008-09 से, 'बांड तथा डिबेंचर' से बैंकों के निवेश का 'वित्तीय संस्थाओं' की लिखतों में निवेश से अलगव आंशिक रूप से बांड तथा डिबेंचर के हिस्से में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। फिर भी, दो वर्गों को जोड़ने के बावजूद ताकि पूर्व आंकड़ों के साथ तुलनीय बांडों और डिबेंचरों के वर्ग में पहुंचा जा सके, 2009-10 में इस वर्ग के हिस्से में गिरावट स्पष्ट थी।



4.11 विश्व भर में, पिछले दो दशकों से बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंड में निवेश में काफी अधिक वृद्धि हुई है। बैंक म्यूच्युअल फंड

के वाहक के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपनी जमाराशियों का एक बड़ा भाग इन फंडों में निवेश किया है तथा वे इन फंडों से उधार लेते रहे हैं। तथापि, बैंकों के म्यूच्युअल फंड में बढ़ते निवेश से संबंधित प्रणालीगत स्थिरता को लेकर चिंताएं हैं जिसकी चर्चा बॉक्स IV.1 में की जा चुकी है।

### अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

4.12 वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियों दोनों में त्वरित वृद्धि देखी गई (सारणी IV.4 तथा IV.5)। बैंकों की (भारत में स्थित) अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 2009-10 में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में 7.4

### बॉक्स IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और म्यूच्युअल फंड के बीच अंतर सह-बद्धताएं

अमरीका जैसे उन्नत देशों में पिछले दो दशकों में म्यूच्युअल फंड में बैंकों की संलिप्तता बढ़ी है, ये बैंक ऐसी निधियों में निवेश के लिए परिवारों से जुटाई गयी जमाराशियों का निवेश करते हैं। म्यूच्युअल फंड में बैंकों के बढ़ते एक्सपोजर के कई प्रणालीगत निहितार्थ हैं, जो म्यूच्युअल फंड में ऐसे निवेश की मात्रा, दिशा और संकेद्रण से उद्भूत होते हैं।

ऑस्मॉस विवरणियों के अंतर्गत मासिक आंकड़ों, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) से प्राप्त मुद्रा बाजार आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, बैंकों और ऋण-उन्मुख म्यूच्युअल फंड (डीओएमएफ) के बीच अंतर-सहबद्धताओं का भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण को ऋण-उन्मुख निधियों तक सीमित रखा गया है क्योंकि इन निधियों में म्यूच्युअल फंड में बैंकों के लगभग संपूर्ण निवेश होते हैं। इस विश्लेषण में म्यूच्युअल फंड में बैंकों के निवेश तथा मुद्रा बाजार (रिपो / सीबीएलओ) और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से बैंकों में म्यूच्युअल फंड के निवेश के आंकड़े शामिल किये गये हैं। इस विश्लेषण के लिए चुनी गयी अवधि दिसंबर 2008 से नवंबर 2009 है।

इस विश्लेषण से उभरे प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: एक, विश्लेषण की अवधि के दौरान डीओएमएफ में बैंकों के निवेशों में काफी अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान डीओएमएफ में निवेशों में वृद्धि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल निवेशों और उनके कुल गैर-एसएलआर निवेशों में पाई गयी वृद्धि की तुलना में अधिक है (सारणी नीचे)। दो, बैंक 2008 से म्यूच्युअल फंड में निवल उधारकर्ता थे न कि निवल उधारदाता। नवंबर 2009 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंड से निवल उधार 1,56,317 करोड़ रुपए थे। इसकी गणना बैंकों द्वारा डीओएमएफ में निवेश और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास म्यूच्युअल फंड (जमा प्रमाणपत्रों में निवेश और बैंकों द्वारा धारित रिपो तथा सीबीएलओ में म्यूच्युअल फंडों के स्थान

सहित) के बीच अंतर को लेकर की गयी है। तीन, डीओएमएफ में निवेश करने वाले सभी बैंक देशी थे और उसमें कोई विदेशी बैंक शामिल नहीं था। जब बैंकों को म्यूच्युअल फंड से उनके निवल उधारों की राशि के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख रूप से बड़े उधारकर्ताओं के रूप में उच्च स्थान पर थे, जबकि एसबीआई सहित निजी क्षेत्र के नये बैंकों को म्यूच्युअल फंड के प्रमुख उधारदाता के रूप में देखा जा सकता है। अंत में, संकेद्रण के अर्थ में, नवंबर 2008 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा डीओएमएफ में कुल निवेशों के 90 प्रतिशत से अधिक 14 बैंकों द्वारा धारित था, जबकि नवंबर 2009 में यह 24 बैंकों द्वारा धारित था, जिससे संकेद्रण की मात्रा में गिरावट का पता चलता है।

### सारणी : ऋण उन्मुख म्यूच्युअल फंड में बैंकों के निवेश और बैंकों में म्यूच्युअल फंड निवेश की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

मद	दिसं.-08	मार्च-09	जून-09	सितं.-09	नवं.-09
1 ऋण उन्मुख म्यूच्युअल फंड में बैंकों के निवेश *	17,650	51,348	91,721	1,12,361	1,25,895
	-	(190.9)	(78.6)	(22.5)	(12.0)
2 सीडी में म्यूच्युअल फंडों का निवेश *	1,09,255	1,37,596	1,87,265	1,78,063	2,18,300
	-	(25.9)	(36.1)	(4.9)	(22.6)
3 रिपो / सीबीएलओ में म्यूच्युअल फंड स्थान	32,006	55,909	70,376	86,018	71,983
	-	(74.7)	(25.9)	(22.2)	(16.3)
3.क जिसमें से बैंकों द्वारा धारित	25,960	48,310	63,664	78,674	63,912
	-	(86.1)	(31.8)	(23.6)	(18.8)
4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास म्यूच्युअल फंड (2+3क)	1,35,215	1,85,907	2,50,929	2,56,737	2,82,212
	-	(37.5)	(35.0)	(2.3)	(9.9)
5 म्यूच्युअल फंड से बैंकों द्वारा निवल उधार (4-1)	1,17,565	1,34,558	1,59,208	1,44,377	1,56,317

**टिप्पणी:** 1) \* - मासिक आंकड़ों को तिमाही थ्रूखला बनाने के लिए औसत किया गया क्योंकि बैंकों ने परवर्ती माह की शुरुआत में लाभ कमाने और निधियों का पुनर्निवेश करने के लिए तिमाही समाप्त महीने में अपने डीओएमएफ निवेश का शोधन किया। नवंबर 2009 के आंकड़े अक्टूबर 2009 के औसत पर आधारित हैं।

2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।



**सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं -  
प्रकार से  
(मार्च के अंत में)**

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009	2010
1	2	3
<b>1. जमा और उधार</b>	<b>3,23,205</b>	<b>3,38,574</b>
	<b>(83.6)</b>	<b>(74.9)</b>
<i>जिसमें से:</i>		
विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] योजना	72,783 (18.8)	72,234 (16.0)
विदेशी मुद्रा उधार*	75,398 (19.5)	74,354 (16.4)
अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) जमा	1,24,488 (32.2)	1,22,380 (27.1)
अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया जमा	20,686 (5.4)	30,824 (6.8)
<b>2. प्रतिभूति / बांड के अपने निर्गम</b>	<b>6,864</b>	<b>5,439</b>
	<b>(1.8)</b>	<b>(1.2)</b>
<b>3. अन्य देयताएं</b>	<b>56,540</b>	<b>1,08,166</b>
	<b>(14.6)</b>	<b>(23.9)</b>
<i>जिसमें से: एडीआर / जीडीआर</i>		
अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	10,357 (2.7)	30,391 (6.7)
भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देनदारियां	18,932 (4.9)	50,313 (11.1)
	27,251 (7.0)	27,462 (6.1)
<b>कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं</b>	<b>3,86,608</b>	<b>4,52,179</b>
	<b>(100.0)</b>	<b>(100.0)</b>

**टिप्पणी:** 1) कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।  
2) \* भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार तथा बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।  
**स्रोत:** स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

**सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ -  
प्रकार से  
(मार्च के अंत में)**

(राशि करोड़ रुपये)

मद	2009	2010
1	2	3
<b>1. ऋण और जमा</b>	<b>2,19,547</b>	<b>2,37,181</b>
	<b>(95.7)</b>	<b>(96.3)</b>
<i>जिसमें से:</i>		
क) अनिवासियों को उधार*	8,341 (3.6)	10,196 (4.1)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार**	99,973 (43.6)	1,23,476 (50.1)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	44,564 (19.4)	50,496 (20.5)
घ) नोस्ट्रो शेष@	66,496 (29.0)	52,135 (21.2)
<b>2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं</b>	<b>76</b>	<b>39</b>
	<b>(0.03)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>3. अन्य आस्तियां @@</b>	<b>9,733</b>	<b>9,139</b>
	<b>(4.2)</b>	<b>(3.7)</b>
<b>कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां</b>	<b>2,29,356</b>	<b>2,46,359</b>
	<b>(100.0)</b>	<b>(100.0)</b>

**टिप्पणी:** 1) \* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार को शामिल किया गया है।  
2) \*\* : वि.मु. अनिवासी (बी) जमाराशियों से दिए गए उधार, विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा एफसी द्वारा दिए गए उधार और भारत के बैंकों में एफसी जमा राशियां आदि।  
3) @ : विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियां।  
4) @@: भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।  
5) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।  
**स्रोत :** स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

प्रतिशत वृद्धि हो गई। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतया अमरीकी/वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर/ जीडीआर) के जरिए अंतर्वाह और अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी की वजह से हुई। 2009-10 में एफसीएनआर(बी)/एनआरई के जरिए अंतर्वाह में कमी हुई। 2009-10 के दौरान बैंचमार्क लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) में एक समान गिरावट के चलते एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाओं पर देय प्रभावी ब्याज दर कम हुई जो आंशिक तौर पर 2009-10 में एफसीएनआर(बी)/ एनआरई अंतर्वाह में गिरावट को दर्शाती है। यह गिरावट आंशिक रूप

से इस अवधि के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर में अधिमूल्यन की वजह से भी हुई।

*समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे*

4.13 बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों की वृद्धि में (तात्कालिक देश-जोखिम पर आधारित) 2008-09 के 32.6 प्रतिशत से 2009-10 में 3.7 प्रतिशत की कमी हुई। 2008-09 और 2009-10 के बीच (अवशिष्ट) परिपक्वता संघटक लगभग

अपरिवर्तित रहे साथ ही अल्पावधि परिपक्वता (एक वर्ष से कम) वाले दावों में कुल अंतरराष्ट्रीय दावों का लगभग दो-तिहाई शामिल है जो भारतीय बैंकों के अल्पावधि अंतरराष्ट्रीय कर्ज और निवेश में प्राथमिकता को दर्शाता है (सारणी IV.6)।

4.14 जहां तक देश-वार संघटन की बात है, भारतीय बैंकों के कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में अमरीका का सबसे बड़ा अनुपात था जिसके बाद यू.के. का था (सारणी IV.7)। तथापि, 2009-

**सारणी IV.6 : बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार (मार्च के अंत में)**

(राशि करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	2009	2010
1	2	3
<b>कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे</b>	<b>2,24,665</b>	<b>2,33,071</b>
	<b>(100.0)</b>	<b>(100.0)</b>
<b>क) परिपक्वता - वार</b>		
1) लघु अवधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,40,289	1,44,638
	(62.4)	(62.1)
2) लंबी अवधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	79,828	81,939
	(35.5)	(35.2)
3) अनाबंटित	4,548	6,494
	(2.0)	(2.7)
<b>ख) क्षेत्रवार</b>		
1) बैंक	1,02,223	98,191
	(45.5)	(42.1)
2) गैर बैंक सार्वजनिक	656	1,442
	(0.3)	(0.6)
3) गैर बैंक निजी	1,21,786	1,33,438
	(54.2)	(57.3)

**टिप्पणी:** 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।  
 2) अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में लागू नहीं परिपक्वता (अर्थात् इन्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।  
 3) बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।  
 4) मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य/केंद्रीय सरकारों की कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र' में केवल राज्य/केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं।

**स्रोत :** समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देशगत जोखिम आधार।

**सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे (मार्च के अंत में)**

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009	2010
1	2	3
<b>कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे</b>	<b>2,24,665</b>	<b>2,33,071</b>
	<b>(100.0)</b>	<b>(100.0)</b>
<i>जिसमें से:</i>		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	55,734	53,394
	(24.8)	(22.9)
ख) यूनाइटेड किंगडम	29,753	36,141
	(13.2)	(15.5)
ग) सिंगापुर	15,762	18,437
	(7.0)	(7.9)
घ) जर्मनी	9,869	12,179
	(4.4)	(5.2)
ड) हांगकांग	19,031	18,978
	(8.5)	(8.1)
च) संयुक्त अरब अमीरात	11,309	13,536
	(5.0)	(5.8)

**टिप्पणी :** कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में प्रतिशत अंश हैं।

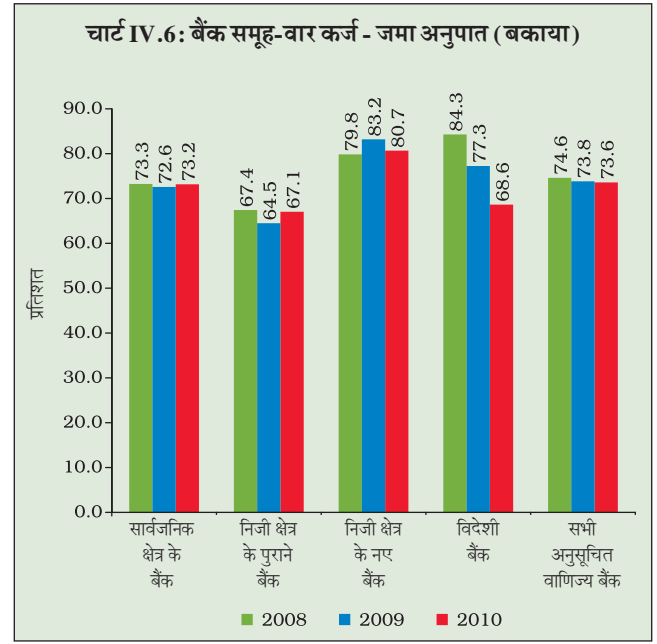
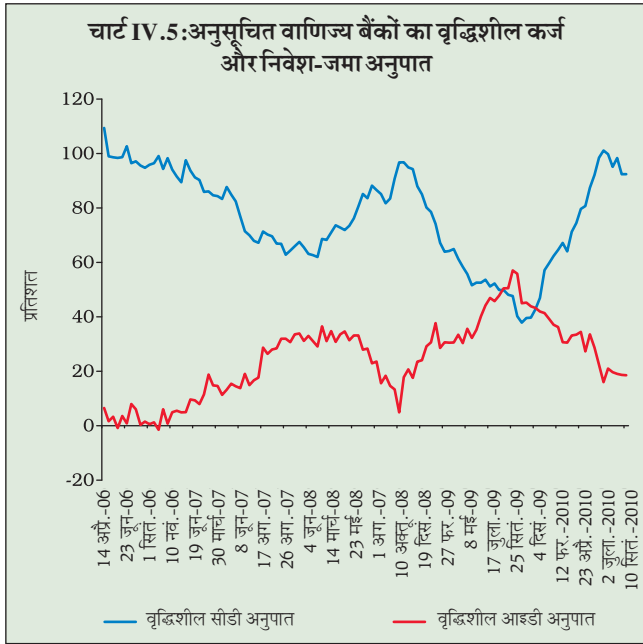
**स्रोत :** समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश जोखिम आधार।

10 में भारतीय बैंकों द्वारा यूएस पर किए गए दावों की कुल संख्या और सापेक्षिक अनुपात में गिरावट आयी। यह संकट के वित्तीय वर्ष 2008-09 के विपरीत था, जब भारतीय बैंकों के यूएस पर किए गए दावों में तीव्र वृद्धि देखी गयी जो यू.एस. बाजार में तब जारी तंग चलनिधि की स्थितियों को परिलक्षित करता है।

**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज-जमा और निवेश-जमा अनुपात**

4.15 वर्ष 2009-10 में वृद्धिशील कर्ज-जमा और निवेश-जमा अनुपात की श्रृंखला का झुकाव अक्टूबर 2009 के मध्य से एक दूसरे से अलग था जो बैंकों के निवेशों की तुलना में जमा वरीयता को परिलक्षित करता है (चार्ट IV.5)। मार्च 2010 के अंत में बकाया कर्ज-जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत के 73.8 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से कम अर्थात् 73.6 प्रतिशत था। इसके विपरीत, निवेश-जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत के 35.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में 36.2 प्रतिशत अर्थात् मामूली रूप से अधिक रहा। विदेशी बैंक जिनके पास





सर्वाधिक (बकाया) कर्ज-जमा अनुपात था, इस अनुपात में 2008 और 2009 के बीच और उसके पश्चात 2009 और 2010<sup>5</sup> में तीव्र गिरावट देखी गई। मार्च 2010 के अंत में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों सहित विदेशी बैंक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों की तुलना में कर्ज-जमा अनुपात के संबंध में, निम्नतम वर्ग में थे (चार्ट IV.6)।

### बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

4.16 बैंकों का आस्ति देयता प्रबंधन उनकी आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता अवधि पर बहुत अधिक निर्भर है। चूंकि बैंक सामान्यतः लघु से दीर्घावधि के दायरे में आनेवाली वित्त आस्तियों के वित्तीयन के लिए अल्पावधि देयताओं के माध्यम से संसाधनों को जुटाते हैं, विशेष रूप से संकट के समय चलनिधि और कर्ज जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं।

4.17 भारतीय बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप सामान्यतः अल्पावधि जमाराशियों पर अधिक भरोसे को दर्शाता है जो लघु तथा मध्यम अवधि वाले उधारों और अग्रिमों तथा आस्ति पक्ष के

दीर्घावधि निवेशों के अनुरूप है। वर्ष 2009-10 में बैंकों द्वारा संग्रहीत जमाराशियों की अल्पावधि (1 वर्ष तक) और मध्यावधि (एक से अधिक और तीन वर्ष तक) ओर अंतरण था (सारणी IV.8)। जैसा कि पहले कहा गया है वर्ष 2009-10 में सीएएसए के भाग में वृद्धि हुई। साथ ही, तीन वर्षों से अधिक की दीर्घावधि परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के भाग में गिरावट आयी। जबकि उधार और अग्रिमों का परिपक्वता वितरण 2009-10 में व्यापक तौर पर अपरिवर्तित रहा, बैंकों का लम्बी अवधि के निवेशों के पक्ष में अंतरण दिखा।

4.18 वर्ष 2009-10 के दौरान अपनी देयताओं में अंतरण के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आस्तियों और देयताओं का असंतुलन ध्यान देने योग्य था जब जमा देयताओं का अंतरण अल्पकालिक परिपक्वता की ओर था साथ ही, उनके उधारों और निवेशों का अंतरण दीर्घकालिक जमाओं की ओर था। मजे की बात यह है कि निजी क्षेत्र के नए बैंक, जो सामान्यतः अल्पावधि जमाराशियों पर बहुत अधिक भरोसा रखते थे, वर्ष 2009-10 में उनमें मध्यम और दीर्घावधि जमाराशियों के पक्ष में अंतरण दिखा जबकि उनके उधार अल्पावधि की ओर काफी करीब थे।

<sup>5</sup> बैंक स्तर पर कर्ज तथा निवेश जमा अनुपातों संबंधी आंकड़ों के लिए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां देखें (एसटीबी) 2009-10।

**सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चुनिंदा देयताओं / आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल**  
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. जमाराशियाँ</b>												
क) 1 वर्ष तक	46.6	48.9	52.5	47.7	48.3	47.6	54.0	47.7	63.8	64.1	48.6	49.4
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	27.1	27.5	36.1	38.4	38.4	36.8	35.3	39.0	23.1	26.6	28.5	29.4
ग) 3 वर्ष से अधिक	26.2	23.6	11.4	13.9	13.3	15.6	10.7	13.3	13.1	9.3	22.9	21.2
<b>II. उधार राशियाँ</b>												
क) 1 वर्ष तक	44.9	42.0	32.4	34.7	62.0	49.2	31.0	33.9	74.7	73.5	46.3	43.7
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	18.8	11.0	22.2	23.9	7.9	15.7	22.8	24.4	15.1	14.8	19.2	15.3
ग) 3 वर्ष से अधिक	36.3	46.9	45.4	41.4	30.1	35.1	46.2	41.7	10.2	11.7	34.5	41.0
<b>III. उधार और अग्रिम</b>												
क) 1 वर्ष तक	38.8	38.0	34.2	37.1	40.8	40.5	32.4	36.0	55.8	61.3	38.9	38.9
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	33.4	33.8	35.5	34.2	35.5	36.8	35.5	33.4	24.1	20.1	33.3	33.3
ग) 3 वर्ष से अधिक	27.8	28.2	30.2	28.7	23.7	22.7	32.1	30.6	20.1	18.6	27.8	27.8
<b>IV. निवेश</b>												
क) 1 वर्ष तक	22.8	18.1	44.1	38.1	37.2	24.4	46.3	42.4	69.0	76.4	31.2	27.7
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	14.5	12.3	20.7	21.6	7.1	8.8	25.0	25.6	18.9	15.6	16.1	14.5
ग) 3 वर्ष से अधिक	62.7	69.5	35.1	40.2	55.8	66.8	28.8	32.0	12.1	8.0	52.6	57.8

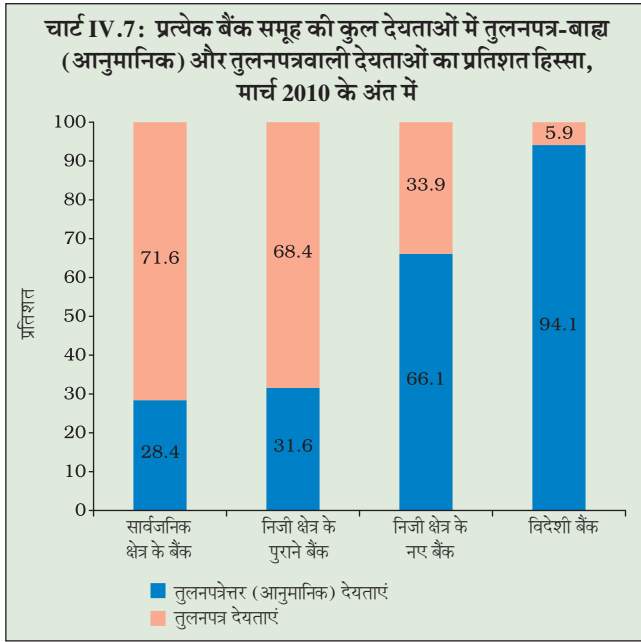
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य परिचालन**

4.19 बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र-बाह्य परिचालनों ने वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका अदा की और इस प्रकार यह विश्व भर के वित्तीय नियामकों के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। भारत में, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को कठोर बनाया जिसके बाद, 2008-09 में इसके एक्सपोजर में 23.1 प्रतिशत तक की गिरावट आयी जिसने पूर्व अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका। साथ ही, 2009-10 में बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर में और गिरावट आयी, यद्यपि गिरावट की दर पिछले वर्ष की तुलना में सापेक्षिक रूप से 5.6 प्रतिशत पर कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.1)। पिछले वर्ष की भाँति वर्ष 2009-10 में आयी गिरावट वायदा विनिमय संविदाओं के कारण

थी, ये भारत के बैंकों की तुलनपत्र-बाह्य देयताओं के सबसे बड़े हिस्सा थे।

4.20 बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों के लिए तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर सामान्यतः सबसे बड़े थे। गिरावट के बावजूद, मार्च 2010 के अंत तक विदेशी बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर सर्वाधिक बने रहे जो आनुमानिक अर्थ में अपनी तुलनपत्र-बाह्य देयताओं का लगभग 1,599 प्रतिशत थे (परिशिष्ट सारणी IV.1)। मार्च 2010 के अंत में विदेशी बैंकों की कुल (तुलनपत्र-तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक)) देयताओं में तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक) देयताओं का हिस्सा 94.1 प्रतिशत था (चार्ट IV.7)। इसके विपरीत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक) देयताओं का हिस्सा अपनी कुल देयताओं में 28.4 प्रतिशत था।



**सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान**

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09		2009-10	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
<b>1. घटबढ़</b>	<b>4,63,702</b>	<b>25.7</b>	<b>4,94,271</b>	<b>6.6</b>
क) ब्याज आय	3,88,482	25.9	4,15,752	7.0
ख) अन्य आय	75,220	24.6	78,519	4.4
<b>2. व्यय</b>	<b>4,10,952</b>	<b>26.0</b>	<b>4,37,162</b>	<b>6.4</b>
क) खर्च किया गया ब्याज	2,63,223	26.5	2,72,084	3.4
ख) परिचालन व्यय	89,581	15.9	99,769	11.4
जिसमें से : वेतन बिल	47,974	20.1	55,164	15.0
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	58,148	42.3	65,310	12.3
<b>3. परिचालन लाभ</b>	<b>1,10,897</b>	<b>32.7</b>	<b>1,22,419</b>	<b>10.4</b>
<b>4. वर्ष में निवल लाभ</b>	<b>52,750</b>	<b>23.5</b>	<b>57,109</b>	<b>8.3</b>
<b>5. निवल ब्याज आय (1क-2क)</b>	<b>1,25,258</b>	<b>24.7</b>	<b>1,43,669</b>	<b>14.7</b>

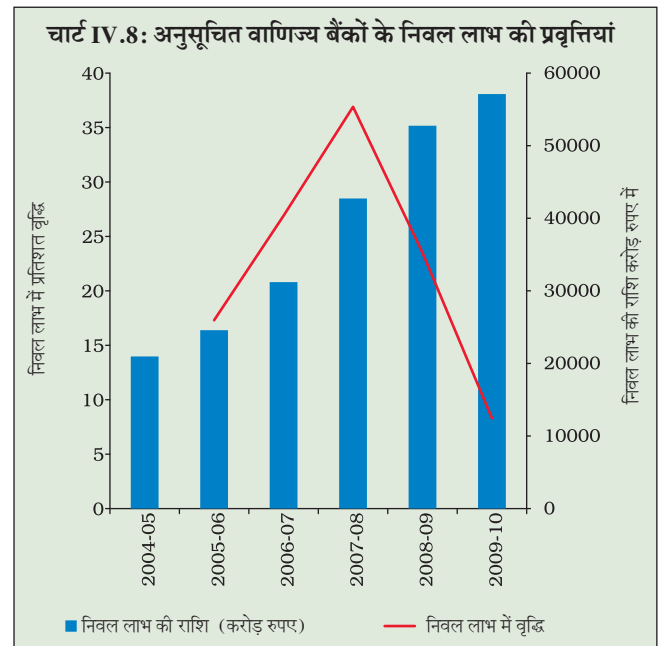
स्रोत: संबंधित बैंकों के लाभ और हानि विवरण।

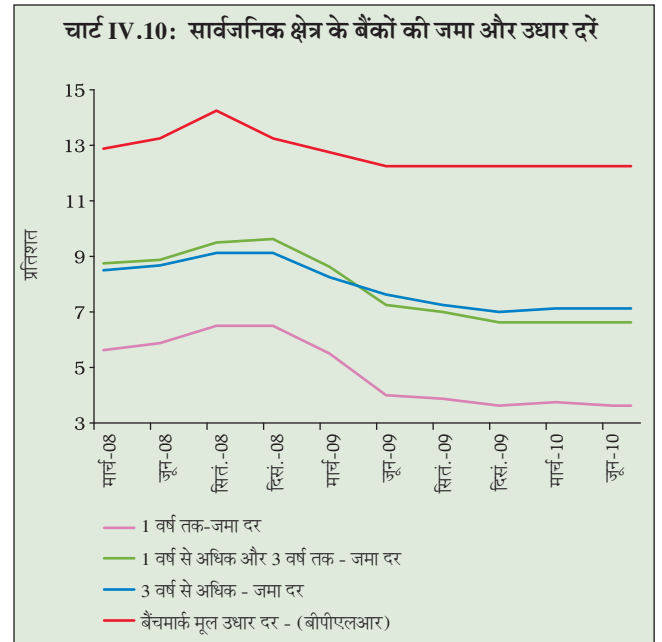
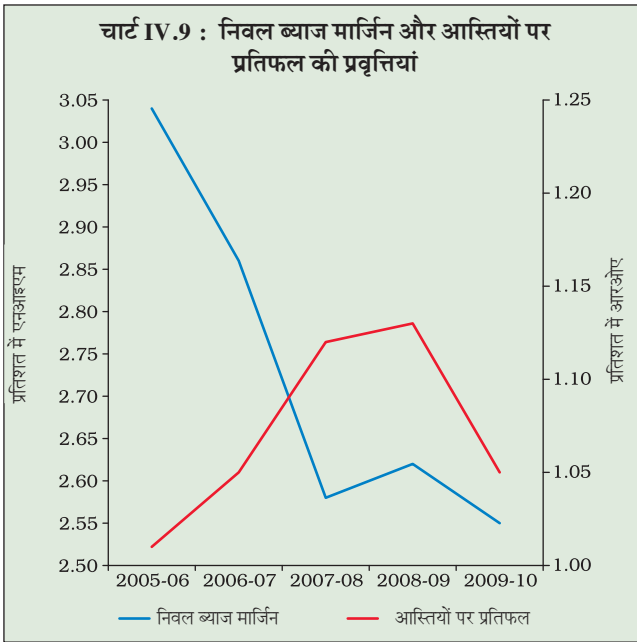
### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

4.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में मंदी की भाँति, 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय में काफी अधिक कमी के संकेत थे। कुल आय में कमी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ब्याज और ब्याज रहित आय दोनों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल व्यय की वृद्धि में कमी आयी जिसके लिए मुख्यतः ब्याज व्यय की वृद्धि में गिरावट जिम्मेदार थी (सारणी IV.9)।

4.22 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय और व्यय दोनों में तीव्र गिरावट आयी और 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन लाभों की वृद्धि में कमी आयी। परिचालन लाभों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में सापेक्षिक रूप से 12.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई। परिणामस्वरूप 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभों में 8.3 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 तक चार वर्षों के दौरान निवल लाभों में वृद्धि निरंतर रूप से बढ़ी। तथापि, निवल लाभों की वृद्धि में 2008-09 में गिरावट दर्ज हुई जो 2009-10 में और तीव्र हो गई (चार्ट IV.8)।

4.23 2005-06 से पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन 2008-09 की मामूली रिकवरी को छोड़कर कुल मिलाकर गिरावट की प्रवृत्ति पर था (चार्ट IV.9)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि और उधार दरें दोनों, जिसका प्रभाव बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन





पर पड़ा, में वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान सामान्यतः उर्ध्वगति दिखाई दी। तथापि, वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई समायोजी मौद्रिक नीति के कारण वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इन दरों में गिरावट आयी। वर्ष 2009-10 के अधिकांश भाग के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा दरों में गिरावट की प्रवृत्ति विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाराशियों पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत दरों में जारी रही जिसमें दिसंबर 2009 तक निरंतर गिरावट दिखाई दी (चार्ट IV.10)।<sup>6</sup> नपेतुले ढंग से बाहर निकलते हुए, रिजर्व बैंक ने फरवरी-सितंबर 2010 के दौरान अपने रिपो दर में 125 आधार अंक (बीपीएस), रिवर्स रिपो दर में 175 आधार अंक तथा सीआरआर में 100 आधार अंक की वृद्धि की। इन परिवर्तनों से संकेत लेते हुए, बैंकों ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न परिपक्वता अवधियों में 25-125 आधार अंकों की सीमा में अपनी जमाराशि दरें बढ़ा दी। उधार दर के संबंध में 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली ने बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली को बदल दिया (बॉक्स IV.2)। आधार दर प्रणाली में अंतरण से पहले, अनुसूचित वाणिज्य

बैंकों का बीपीएलआर जुलाई 2009 और जुलाई 2010 के बीच अपरिवर्तित रहा। वर्ष के अधिकांश भाग के लिए कम कर्ज उठाव के साथ नियंत्रित ब्याज दर वातावरण वर्ष 2009-10 में आंशिक रूप से बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन में गिरावट को दर्शाता है।

4.24 वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों की लागत और प्रतिलाभ दोनों में गिरावट दिखी विशेष रूप से, अग्रिमों पर प्रतिलाभ में गिरावट वर्ष 2008-09 के 10.50 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 9.29 प्रतिशत थी। वर्ष 2009-10 में अग्रिमों पर प्रतिफल में गिरावट विदेशी और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए काफी अधिक थी (सारणी IV.10)।

4.25 निवल ब्याज मार्जिन में गिरावट के समान, वर्ष 2009-10 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में भी गिरावट आयी, जो बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता का एक दूसरा संकेतक है तथा जिसमें लाभ की वह राशि शामिल है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र द्वारा धारित आस्तियों के एक इकाई से सृजित किया जा सकता है। आस्तियों पर प्रतिफल में (औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत

<sup>6</sup> 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही के साथ जारी मौद्रिक और समष्टि आर्थिक गतिविधियां देखें, ब्याज दरों के बैंक समूह-वार दायरे के ब्यौरों के लिए सारणी V.7।

## बॉक्स IV.2: ब्याज दरों की आधार दर प्रणाली - विशेषताएं और मुद्दे

ऐसी आशा थी कि 2003 में शुरू की गयी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की प्रणाली बैंकों के अपने उधार संबंधी उत्पादों के मूल्यन के लिए बेंचमार्क दर के रूप में कार्य करेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे वास्तविक लागत सही अर्थों में परिलक्षित हो। लेकिन, बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य से पीछे रही। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से था क्योंकि बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत बैंक बीपीएलआर के नीचे उधार दे सकते थे। इसी कारण से, बैंकों की उधार दरों में रिजर्व बैंक की नीति दरों के संचारण का मूल्यांकन कठिन हो गया।

इन चिंताओं के निराकरण के लिए, रिजर्व बैंक ने 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) बनाने की घोषणा की, जिससे बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा की जा सके और मूल्यन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदलावों के बारे में सुझाव दिया जा सके। कार्यदल ने 20 अक्टूबर 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसे उसी दिन रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया। इस समूह की सिफारिशों और विभिन्न पणधारियों के सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक ने 9 अप्रैल 2009 को आधार दर प्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किये। तदनुसार, आधार दर की प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू की गयी। आधार दर में उधार दरों के उन सभी तत्वों को शामिल किया गया है जो उधारकर्ताओं के सभी वर्गों के बीच सामान्य हैं। उधारकर्ताओं से ली जाने वाली वास्तविक उधार दरें आधार दर जमा उधारकर्ता-विशिष्ट प्रभार होंगी। आधार दर सभी उधार दरों के लिए न्यूनतम दर है तथा इस प्रकार बैंकों को कुछ विशिष्ट वर्गों जैसे (क) विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) अग्रिम; (ख) बैंकों के अपने कर्मचारियों को उधार; और (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं की जमानत पर उधार, को छोड़कर आधार दर से कम कोई उधार देने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सरकार द्वारा कृषि उधार और रुपया निर्यात कर्ज पर दी गयी ब्याज दर सहायता के मामले में, वास्तविक उधार दर आधार दर से नीचे जा सकती है। पुनःसंचित उधारों के मामले में, यदि अर्थक्षमता के प्रयोजन के लिए कार्यशील पूंजी मीयादी उधार (डब्ल्यूसीटीएल), निधिकृत ब्याज मीयादी उधार (एफआइटीएल) को आधार दर से नीचे प्रदान करने की आवश्यकता है और उनके लिए क्षतिपूर्ति खंड हैं तो ऐसे उधारों को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा, छोटे उधारकर्ताओं के लिए उचित दर पर कर्ज का प्रवाह बढ़ाने हेतु 2 लाख रुपए तक के छोटे उधारों

पर ब्याज दर को अविनियमित किया गया है। आधार दर प्रणाली सभी नये उधारों और उन पुराने उधारों पर लागू होगी, जिनका नवीकरण कराया जा रहा हो। बीपीएलआर प्रणाली पर आधारित वर्तमान उधार उनकी परिपक्वता तक चालू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 28 अप्रैल 2010 को 1 जुलाई 2010 से प्रभावी रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर को भी विनियमित किया और कहा कि रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर का मूल्यन आधार दर पर अथवा उसके ऊपर किया जाएगा। ऐसी आशा है कि आधार दर प्रणाली उधारों के बेहतर मूल्यन को सुकर बनाएगी, उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाएगी और मौद्रिक नीति के संचारण के मूल्यांकन में सुधार करेगी।

प्रणाली के लिए कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आधार दर 13 अक्टूबर 2010 को 5.50 - 9.00 प्रतिशत के दायरे में थी। सितंबर के अंत और अक्टूबर 2010 के दौरान कई बैंकों ने अपनी आधार दर को 25-50 आधार अंक बढ़ाया। बैंकों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आधार दरों का एक बढ़े स्तर पर अभिसरण हुआ है। हाल की समीक्षा में, 48 बैंकों ने, जिनका हिस्सा कुल बैंक कर्ज में 94 प्रतिशत था, अपनी आधार दरों को 7.50 - 8.50 प्रतिशत के दायरे में रखा। जुलाई 2010 में कुल बैंक कर्ज में 81 प्रतिशत हिस्से वाले 40 से अधिक बैंकों ने आधार दर को 7.25 - 8.00 प्रतिशत के दायरे में रखा है।

### सारणी: बीपीएलआर का दायरा और बैंक समूह की आधार दरें

बैंक समूह	बीपीएलआर दायरा (13 अक्टूबर 2009 को)	आधार दर दायरा (13 अक्टूबर 2009 को)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.75-13.50	7.50-8.50
निजी क्षेत्र के बैंक	12.75-17.50	7.00-9.00
विदेशी बैंक	10.50-16.00	5.50-9.00

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (2010), *बेंचमार्क मूल आधार दर पर बने कार्य दल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती)।

मोहंती, दीपक (2010), “भारत में उधार दरों का परिप्रेक्ष्य” विषय पर बैंकर्स क्लब, कोलकाता में दिया गया भाषण, *आरबीआइ बुलेटिन*, जुलाई।

के अनुसार निवल लाभ के रूप में परिभाषित) गिरावट दर्ज हुई, जो 2009-10 में बड़े पैमाने पर बैंकों के लाभों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है (चार्ट IV.9)<sup>7</sup>। इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), जिसमें इक्विटी की प्रत्येक इकाई से लाभ सृजित

करने में बैंकिंग क्षेत्र की सक्षमता परिलक्षित होती है, में भी 2009-10 में गिरावट दिखाई दी (सारणी IV.11)।

4.26 बैंक समूह स्तर पर, 2009-10 में आरओई और आरओई में आयी गिरावट आई जो विदेशी बैंकों के लिए सबसे

<sup>7</sup> चार्ट IV.9 में दिए गए निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिफल के आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों को लेते हुए निकाले गए हैं (वर्तमान और पूर्व वर्ष के औसत)। इसलिए, हो सकता है कि ये आंकड़े संबंधित वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाएं। कुल और बैंक समूह/बैंक स्तर पर इन परिवर्तियों की सुसंगत समय श्रृंखला को *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों* के विभिन्न विगत मुद्दों से लिया जा सकता है।

**सारणी IV.10: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार**

(प्रतिशत)

बैंक समूह / वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधियों पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-4)
<b>1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>							
<b>2008-09</b>	<b>6.26</b>	<b>3.04</b>	<b>6.04</b>	<b>10.08</b>	<b>6.95</b>	<b>9.11</b>	<b>3.07</b>
<b>2009-10</b>	<b>5.68</b>	<b>1.37</b>	<b>5.34</b>	<b>9.10</b>	<b>6.72</b>	<b>8.36</b>	<b>3.02</b>
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*							
2008-09	6.31	2.76	6.09	10.17	7.05	9.22	3.14
2009-10	5.64	1.42	5.35	9.18	6.88	8.48	3.13
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
2008-09	6.17	3.47	5.94	9.89	6.77	8.90	2.95
2009-10	5.75	1.28	5.32	8.92	6.41	8.13	2.81
<b>2 निजी क्षेत्र के बैंक</b>							
<b>2008-09</b>	<b>6.60</b>	<b>3.56</b>	<b>6.18</b>	<b>11.41</b>	<b>6.93</b>	<b>9.85</b>	<b>3.67</b>
<b>2009-10</b>	<b>5.36</b>	<b>1.95</b>	<b>4.83</b>	<b>9.89</b>	<b>6.25</b>	<b>8.60</b>	<b>3.77</b>
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
2008-09	6.73	4.44	6.67	11.82	6.57	10.01	3.34
2009-10	6.27	1.94	6.13	10.95	6.18	9.25	3.12
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
2008-09	6.56	3.52	6.04	11.29	7.03	9.80	3.77
2009-10	5.01	1.96	4.42	9.56	6.28	8.40	3.99
<b>3 विदेशी बैंक</b>							
<b>2008-09</b>	<b>4.58</b>	<b>4.07</b>	<b>4.46</b>	<b>12.61</b>	<b>7.63</b>	<b>10.55</b>	<b>6.10</b>
<b>2009-10</b>	<b>3.20</b>	<b>1.58</b>	<b>2.82</b>	<b>9.99</b>	<b>6.39</b>	<b>8.30</b>	<b>5.49</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>							
<b>2008-09</b>	<b>6.24</b>	<b>3.37</b>	<b>5.96</b>	<b>10.50</b>	<b>7.01</b>	<b>9.36</b>	<b>3.40</b>
<b>2009-10</b>	<b>5.49</b>	<b>1.57</b>	<b>5.09</b>	<b>9.29</b>	<b>6.59</b>	<b>8.41</b>	<b>3.31</b>

- टिप्पणी :** 1) जमा की लागत = जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष की जमा राशियों का औसत।  
 2) उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के उधारों का औसत।  
 3) निधियों की लागत = (जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष की जमा राशियों + उधारों का औसत)।  
 4) अग्रिमों पर प्रतिफल = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों का औसत।  
 5) निवेशों पर प्रतिफल = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के निवेशों का औसत।  
 6) निधियों पर प्रतिफल = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत।  
 7) \* - आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

**स्रोत:** संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

**सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार**

(प्रतिशत)

बैंक समूह / वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
<b>1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>1.02</b>	<b>0.97</b>	<b>17.94</b>	<b>17.47</b>
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.03	1.00	18.05	18.30
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	1.02	0.91	17.74	15.92
<b>2 निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>1.13</b>	<b>1.28</b>	<b>11.38</b>	<b>11.94</b>
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.15	0.95	14.69	12.29
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.12	1.38	10.69	11.87
<b>3 विदेशी बैंक</b>	<b>1.99</b>	<b>1.26</b>	<b>13.75</b>	<b>7.35</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>1.13</b>	<b>1.05</b>	<b>15.44</b>	<b>14.31</b>

- टिप्पणी:** 1) आस्तियों पर प्रतिफल = निवल प्रतिफल / औसत कुल आस्तियां।  
 2) इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ / औसत कुल इक्विटी।  
 3) \* राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

**स्रोत:** संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

अधिक थी। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के नए बैंकों के मामले में, लाभप्रदता के इन दोनों संकेतकों ने वर्ष 2009-10 में वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.11)।

4.27 बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता का तीसरा प्रमुख संकेतक अर्थात् अंतर, जिसे निधियों के प्रतिलाभ और लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया, में भी समग्र स्तर पर वर्ष 2009-10 में लगभग 0.10 प्रतिशत अंकों की गिरावट भी दिखी। बैंक समूह स्तर पर इस अंतर में गिरावट विदेशी बैंकों के लिए पुनः काफी आश्चर्यजनक थी (सारणी IV.10)।

**4. सुदृढ़ता संकेतक**

4.28 बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता का कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। संकट के पश्चात्,



बढ़े हुए बासेल II ढांचे<sup>8</sup> के अंतर्गत विभिन्न देशों में विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपाए किये गये हैं। जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), अनर्जक आस्तियों और लीवरेज अनुपात के तीन संकेतकों का प्रयोग करते हुए, इस खंड में 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता का विश्लेषण किया गया है।

### जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात

4.29 जैसा कि 2008-09 की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट के दबावों का सामना किया और वह कारक, जिसने सबसे बड़े वैश्विक वित्तीय संकटों में से एक का सामना होते हुए भी बैंकिंग प्रणाली के सामान्य क्रियाकलाप को सुगम बनाये रखा, सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता थी। बासेल I ढांचे के अंतर्गत भारतीय बैंकों के सीआरएआर में, जो 2007 से निरंतर बढ़ रहा था, संकट वर्ष के दौरान मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। मार्च 2010 के अंत में, सीआरएआर और बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.12)<sup>9</sup>।

#### सारणी IV.12: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार (मार्च के अंत में)

बैंक समूह	बासेल I		बासेल II	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>12.3</b>	<b>12.1</b>	<b>13.5</b>	<b>13.3</b>
राष्ट्रीयकृत बैंक *	12.1	12.1	13.2	13.2
भारतीय स्टेट बैंक समूह	12.7	12.1	14.0	13.5
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>15.0</b>	<b>16.7</b>	<b>15.2</b>	<b>17.4</b>
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	14.3	13.8	14.8	14.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.1	17.3	15.3	18.0
<b>विदेशी बैंक</b>	<b>15.0</b>	<b>18.1</b>	<b>14.3</b>	<b>17.3</b>
<b>अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>13.2</b>	<b>13.6</b>	<b>14.0</b>	<b>14.5</b>

टिप्पणी: \*: आइडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।  
 स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट विवरणियों पर आधारित।

4.30 चूंकि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत के बाहर कार्यरत भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासेल II ढांचे की ओर अंतरण किया, यह भी आवश्यक हो गया है कि इस ढांचे अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता स्थिति पर दृष्टि डाली जाए। बासेल II के अंतर्गत, मार्च 2009 के अंत में भारतीय बैंकों का सीआरएआर 14.0 प्रतिशत था, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात से अधिक था। इसका तात्पर्य है कि भारतीय बैंकों ने बदले हुए ढांचे के अंतर्गत बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा किया। मार्च 2009 और 2010 के बीच, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर में लगभग 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जो नये ढांचे के अंतर्गत उनकी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने की बात परिलक्षित करती है।

4.31 मूल सीआरएआर, जो चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों को परिलक्षित करता है, सामान्यतया किसी बैंक की वित्तीय क्षमता का मूल माप होता है। भारतीय बैंकों के मामले में, मूल पूंजी (टीयर I पूंजी द्वारा मापित), मार्च 2010 के अंत में कुल पूंजी का लगभग 70 प्रतिशत थी। बासेल I और बासेल II ढांचे के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का मूल सीआरएआर अनुपात मार्च 2010 के अंत में क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत था, जो पुनः रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत से काफी अधिक था, इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मूल पूंजी क्षमता रेखांकित होती है (सारणी IV.13)।

#### सारणी IV.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता (मार्च के अंत में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2009	2010	2009	2010
क. पूंजी निधियां (i+ii)	4,88,563	5,72,582	4,87,826	5,67,381
i) टीयर I पूंजी	3,31,422	3,97,665	3,33,810	3,95,100
ii) टीयर II पूंजी	1,57,141	1,74,916	1,54,016	1,72,281
ख. जोखिम भारित आस्तियां	37,04,372	42,16,565	34,88,303	39,01,396
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	13.2	13.6	14.0	14.5
जिसमें से: टीयर I	9.0	9.4	9.6	10.1
टीयर II	4.2	4.1	4.4	4.4

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट विवरणियों पर आधारित।

<sup>8</sup> बढ़े हुए बासेल II ढांचे पर ब्यौरों के लिए अध्ययन I देखें।

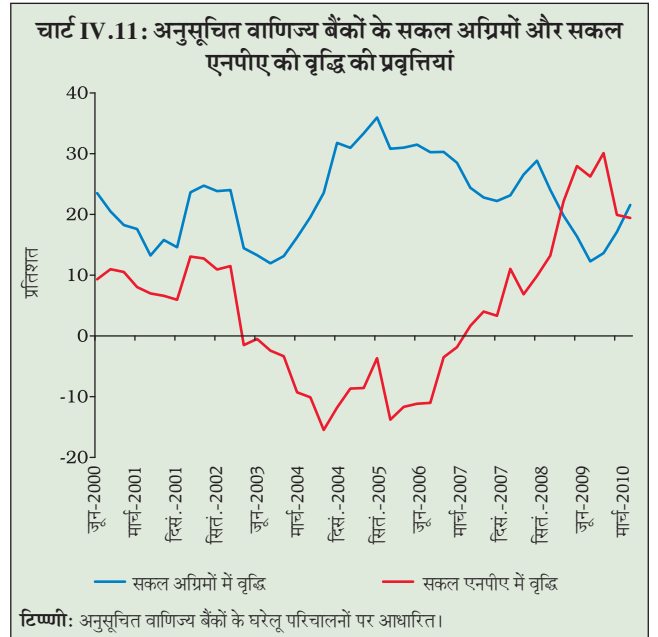
<sup>9</sup> इस खंड में सीआरएआर का विश्लेषण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियों के आंकड़ों पर आधारित है।

4.32 बैंक समूह स्तर पर, प्रत्येक बैंक समूह ने बासेल I और बासेल II दोनों ढांचों के अंतर्गत, औसतन, 12 प्रतिशत के ऊपर सीआरएआर सूचित की (सारणी IV.12)। दोनों ढांचों के अंतर्गत, विदेशी बैंकों के लिए सीआरएआर का स्तर सर्वाधिक था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित स्तर से लगभग 4-6 प्रतिशत अंक ऊपर था। विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2009-10 के बीच सीआरएआर (बासेल I और बासेल II के अंतर्गत) में वृद्धि सूचित की। इसके विपरीत, एसबीआइ समूह के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट आई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस अवधि के दौरान पूंजी पर्याप्तता के संबंध में अपनी स्थिति को बरकरार रखा।

### अनर्जक आस्तियां

4.33 जबकि भारतीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता सुदृढ़ बनी रही, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बैंकों के दूसरे महत्वपूर्ण सुदृढ़ संकेतक से संबंधित कुछ चिंताएं उभरीं। भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सामान्यरूप से निरंतर सुधार दिखा जैसाकि 1999 से सकल और निवल एनपीए अनुपात के गिरते स्तर से स्पष्ट है। मार्च 1999 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 14.6 प्रतिशत था जो मार्च 2008 के अंत में लगातार गिरकर 2.25 प्रतिशत हो गया। संकट वर्ष 2008-09 के दौरान, भारतीय बैंकों का सकल एनपीए अनुपात अपरिवर्तित बना रहा। फिर भी, 2009-10 के दौरान सकल एनपीए अनुपात बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.14)। प्रावधानों को घटाने के पश्चात, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल एनपीए अनुपात मार्च 2009 के अंत के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 1.12 प्रतिशत हो गया।

4.34 यह उल्लेखनीय है कि भारतीय बैंकों की एनपीए में वृद्धि व्यापक रूप से कर्ज वृद्धि के संबंध में विलंबित चक्रीय पैटर्न के पश्चात रही है (चार्ट V.11)। जून 2000 से सकल अग्रिम और



सकल एनपीए की वृद्धि दरों को लेते हुए, आनुभविक विश्लेषण दर्शाता है कि एनपीए वृद्धि दो वर्ष<sup>10</sup> के अंतराल में कर्ज वृद्धि के बाद होती है। कर्ज वृद्धि के सह गुणांक धनात्मक और दूसरे चरण से आगे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे जिससे परिलक्षित होता है कि कर्ज वृद्धि एक अंतराल में एनपीए में वृद्धि में तब्दील हो गई। यह बैंकिंग प्रणाली के सहचक्रीय व्यवहार को रेखांकित करती है, जिसमें उच्च कर्ज वृद्धि अवधि के दौरान आस्ति गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ सकता है और इसका परिणाम बाद के वर्षों में बैंकों के लिए अनर्जक आस्तियों का निर्माण होता है।

4.35 बैंक समूह स्तर पर, मार्च 2010 के अंत में विदेशी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सर्वाधिक था इसके पश्चात निजी क्षेत्र के बैंकों का था। दूसरी तरफ, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए यह सबसे कम था। 2009 और 2010 के बीच सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों में देखी जा सकती है। इस अवधि के दौरान सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि विदेशी बैंकों के लिए दृष्टिगोचर है (सारणी V.14)।

<sup>10</sup> समकालिक कर्ज वृद्धि और तीन वर्ष तक के अंतराल की कर्ज वृद्धि के लिए आकलन किया गया। महत्वपूर्ण सहगुणांक को दर्शाते हुए रिग्रेशन नीचे दिया गया है:

$$\text{एनपीए वृद्धि} = \alpha + 0.62 \text{ कर्ज वृद्धि}_{-2} + 1.41 \text{ कर्ज वृद्धि}_{-3}$$

(1.9)\*                      (5.8)\*\*

\* 5 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।

\*\* 1 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।

सारणी IV.14: अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>सकल एनपीए</b>								
2008-09 के लिए अंतिम शेष	44,957	26,543	18,413	16,926	3,072	13,854	6,444	68,328
2009-10 के लिए प्रारंभिक शेष	44,957	26,543	18,413	16,889	3,072	13,817	6,437	68,283
2009-10 के दौरान जोड़	44,818	29,701	15,116	11,651	2,833	8,817	9,205	65,674
2009-10 के लिए वसूली	26,946	18,966	7,980	6,498	1,686	4,811	5,513	38,957
2009-10 के लिए बढ़ा खाता डाले गए	2,902	884	2,017	4,402	597	3,805	2,948	10,253
2009-10 के लिए अंतिम शेष	59,926	36,395	23,532	17,639	3,622	14,017	7,180	84,747
<b>सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए</b>								
2008-09	1.97	1.73	2.46	2.89	2.36	3.05	3.80	2.25
2009-10	2.19	1.95	2.70	2.74	2.32	2.87	4.29	2.39
<b>निवल एनपीए</b>								
2008-09 के लिए अंतिम शेष	21,155	10,286	10,869	7,412	1,159	6,252	2,996	31,564
2009-10 के लिए अंतिम शेष	29,644	16,813	12,831	6,506	1,271	5,234	2,975	39,126
<b>निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए</b>								
2008-09	0.94	0.68	1.47	1.29	0.90	1.40	1.81	1.05
2009-10	1.10	0.91	1.50	1.03	0.83	1.09	1.82	1.12

**टिप्पणी:** 1) 2008-09 का अंतिम शेष निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के 2009-10 के प्रारंभिक शेष से नहीं मिलता है क्योंकि इन बैंकों में से कुछ ने आरबीआइ के परिपत्र > डीबीओडी सं.बीपी. बीसी.46/21.04.048/2009-10> दिनांकित 24 सितंबर 2009 के अनुसार पूर्व वर्ष के एनपीए के अंतिम शेष से ब्याज उचत घटाकर एनपीए के प्रारंभिक शेष को सूचित किया है।

2) \*: आइडीबीआई बैंक लि. सहित।

**स्रोत:** संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

4.36 एनपीए अनुपात में वृद्धि के अलावा, 2009 और 2010 के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए के संवितरण में भी गिरावट आई। यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की हानि वाली और संदिग्ध आस्तियों के प्रतिशत में वृद्धि से स्पष्ट है, जो एनपीए के मामले में सबसे नीचे है (सारणी IV.15: चार्ट IV.12)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में एनपीए के संवितरण का अंतरण संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के पक्ष में अधिक था।

4.37 एनपीए के सेक्टरल संवितरण ने 2009 और 2010 के बीच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए के बढ़ते अनुपात को दर्शाया (सारणी IV.16)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए, जो 2008 तक देशी बैंकों के कुल एनपीए के आधे से थोड़ा अधिक था, में 2009 में सीधी गिरावट दिखी जिसके लिए मुख्य रूप से 2008 की कृषि कर्ज माफी और कर्ज राहत योजना उत्तरदायी थी। 2009 और 2010 के बीच, सामान्य रूप में और

विशेष रूप से लघु उद्योगों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए का हिस्सा घरेलू बैंकों के मामले में बढ़ा, यह आंशिक रूप से वित्तीय संकट और उसके पश्चात हुई आर्थिक मंदी के प्रभाव को दर्शाता है। मार्च 2010 के अंत में, कुल एनपीए में प्राथमिकता प्राप्त एनपीए का प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 53.8 प्रतिशत था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 27.6 प्रतिशत था [परिशिष्ट सारणी IV.2 (अ-इ)]।

4.38 बैंकों के सेक्टरल एनपीए अनुपात में भी 2009 और 2010 के बीच प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिखी; लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात में वृद्धि गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक थी (चार्ट IV.13)।

4.39 यह उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग, जिसमें अन्य के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति और

**सारणी IV.15: उधार संबंधी आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूह-वार**  
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

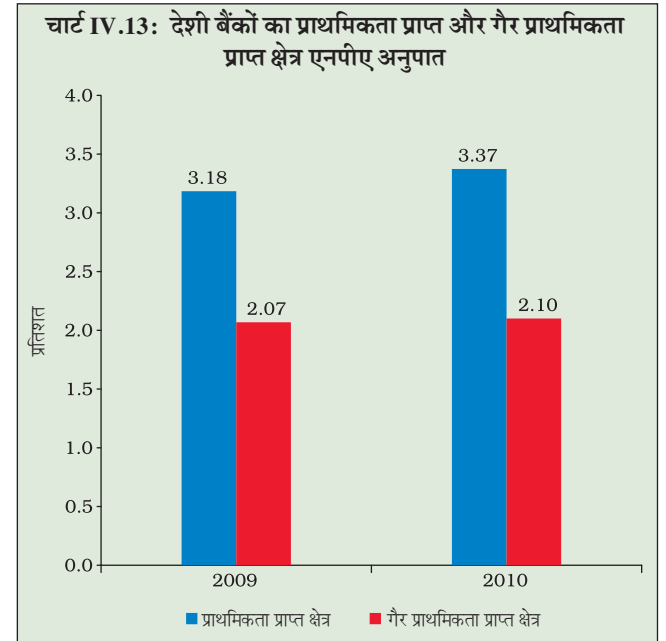
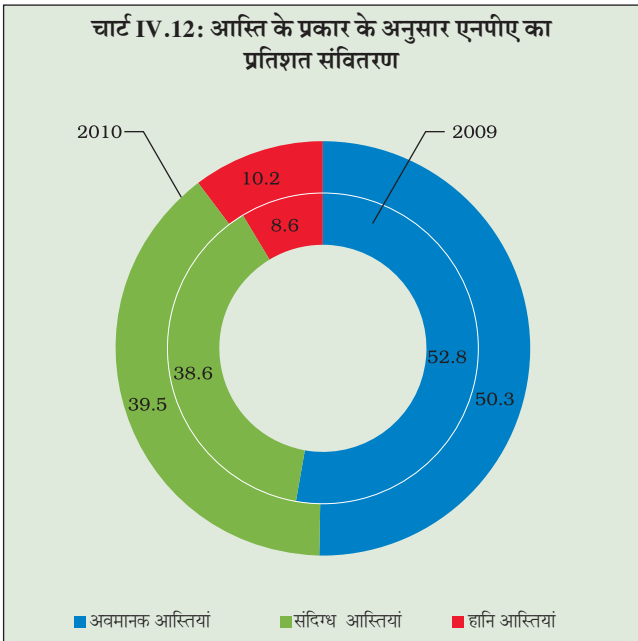
बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अव-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>2009</b>	<b>22,37,556</b>	<b>97.99</b>	<b>20,603</b>	<b>0.90</b>	<b>21,019</b>	<b>0.92</b>	<b>4,296</b>	<b>0.19</b>
	<b>2010</b>	<b>26,73,534</b>	<b>97.81</b>	<b>28,791</b>	<b>1.05</b>	<b>25,383</b>	<b>0.93</b>	<b>5,750</b>	<b>0.21</b>
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक**	2009	15,08,798	98.25	11,086	0.72	13,306	0.87	2,412	0.16
	2010	18,27,061	98.05	18,520	0.99	15,034	0.81	2,841	0.15
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2009	7,28,758	97.44	9,517	1.27	7,713	1.03	1,884	0.25
	2010	8,46,473	97.30	10,271	1.18	10,349	1.19	2,909	0.33
<b>2 निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>2009</b>	<b>5,68,093</b>	<b>97.10</b>	<b>10,592</b>	<b>1.81</b>	<b>5,035</b>	<b>0.86</b>	<b>1,345</b>	<b>0.23</b>
	<b>2010</b>	<b>6,26,472</b>	<b>97.27</b>	<b>8,842</b>	<b>1.37</b>	<b>6,590</b>	<b>1.02</b>	<b>2,166</b>	<b>0.34</b>
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2009	1,27,280	97.64	1,334	1.02	1,327	1.02	411	0.32
	2010	1,52,745	97.69	1,395	0.89	1,637	1.05	580	0.37
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	2009	4,40,813	96.94	9,258	2.04	3,708	0.82	934	0.21
	2010	4,73,727	97.13	7,447	1.53	4,953	1.02	1,586	0.33
<b>3 विदेशी बैंक</b>	<b>2009</b>	<b>1,62,422</b>	<b>95.70</b>	<b>5,874</b>	<b>3.46</b>	<b>1,004</b>	<b>0.59</b>	<b>416</b>	<b>0.25</b>
	<b>2010</b>	<b>1,60,311</b>	<b>95.74</b>	<b>4,929</b>	<b>2.94</b>	<b>1,440</b>	<b>0.86</b>	<b>758</b>	<b>0.45</b>
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	<b>2009</b>	<b>29,68,070</b>	<b>97.69</b>	<b>37,069</b>	<b>1.22</b>	<b>27,058</b>	<b>0.89</b>	<b>6,056</b>	<b>0.20</b>
	<b>2010</b>	<b>34,60,318</b>	<b>97.61</b>	<b>42,561</b>	<b>1.20</b>	<b>33,412</b>	<b>0.94</b>	<b>8,674</b>	<b>0.24</b>

**टिप्पणी:** 1) पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।  
2) \* : सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।  
3) \*\*: आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

**स्रोत:** संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणी (बीएसए)।

जनजाति (एससी/एसटी) शामिल है, में हाल के वर्षों में एनपीए अनुपात में निरंतर गिरावट दिखी है। यह रुझान इस तर्क को सत्यापित करता है कि कमजोर वर्ग वास्तव में अन्य

वर्गों की तुलना में कम उधार-पात्र नहीं हैं और यह वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तर्क को मजबूत करता है। मार्च 2010 के अंत में, कमजोर वर्ग के लिए एनपीए

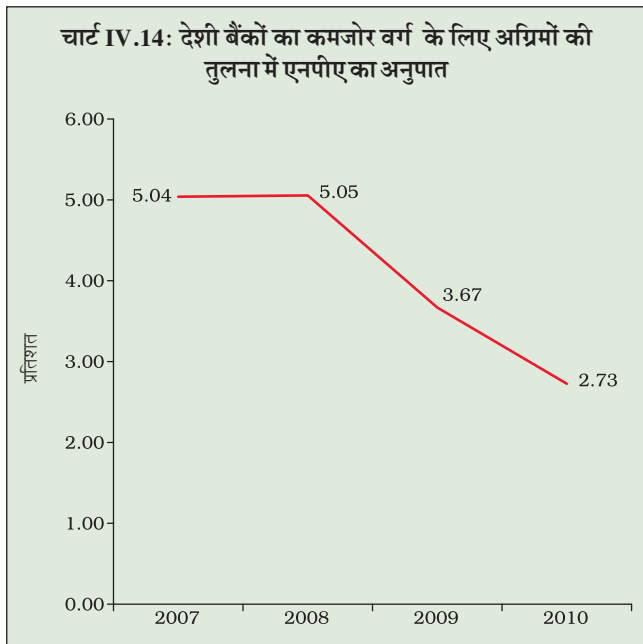


**सारणी IV.16: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए\***  
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से, कृषि		जिसमें से, लघु उद्योग		जिसमें से, अन्य		सार्वजनिक क्षेत्र		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>														
<b>2009</b>	<b>24,318</b>	<b>55.2</b>	<b>5,708</b>	<b>13.0</b>	<b>6,984</b>	<b>15.9</b>	<b>11,626</b>	<b>26.4</b>	<b>474</b>	<b>1.1</b>	<b>19,251</b>	<b>43.7</b>	<b>44,042</b>	<b>100.0</b>
<b>2010</b>	<b>30,848</b>	<b>53.8</b>	<b>8,330</b>	<b>14.5</b>	<b>11,537</b>	<b>20.1</b>	<b>10,981</b>	<b>19.2</b>	<b>524</b>	<b>0.9</b>	<b>25,929</b>	<b>45.3</b>	<b>57,301</b>	<b>100.0</b>
राष्ट्रीयकृत बैंक**														
2009	15,871	60.6	3,707	14.2	4,958	18.9	7,206	27.5	297	1.1	10,001	38.2	26,169	100.0
2010	19,908	56.1	5,741	16.2	8,668	24.4	5,499	15.5	280	0.8	15,283	43.1	35,470	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2009	8,447	47.3	2,001	11.2	2,026	11.3	4,420	24.7	177	1.0	9,250	51.8	17,874	100.0
2010	10,940	50.1	2,589	11.9	2,869	13.1	5,482	25.1	244	1.1	10,646	48.8	21,831	100.0
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>														
<b>2009</b>	<b>3,641</b>	<b>21.6</b>	<b>1,441</b>	<b>8.5</b>	<b>666</b>	<b>3.9</b>	<b>1,533</b>	<b>9.1</b>	<b>75</b>	<b>0.4</b>	<b>13,172</b>	<b>78.0</b>	<b>16,888</b>	<b>100.0</b>
<b>2010</b>	<b>4,792</b>	<b>27.6</b>	<b>2,023</b>	<b>11.6</b>	<b>1,139</b>	<b>6.6</b>	<b>1,630</b>	<b>9.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,592</b>	<b>72.4</b>	<b>17,384</b>	<b>100.0</b>
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2009	1,234	40.2	263	8.6	303	9.9	667	21.7	-	-	1,839	59.8	3,072	100.0
2010	1,613	44.7	269	7.4	475	13.2	869	24.1	-	-	1,999	55.3	3,612	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2009	2,407	17.4	1,178	8.5	363	2.6	866	6.3	75	0.5	11,334	82.0	13,815	100.0
2010	3,179	23.1	1,754	12.7	664	4.8	760	5.5	-	-	10,594	76.9	13,772	100.0
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>														
<b>2009</b>	<b>27,958</b>	<b>45.9</b>	<b>7,149</b>	<b>11.7</b>	<b>7,650</b>	<b>12.6</b>	<b>13,159</b>	<b>21.6</b>	<b>549</b>	<b>0.9</b>	<b>32,423</b>	<b>53.2</b>	<b>60,930</b>	<b>100.0</b>
<b>2010</b>	<b>35,640</b>	<b>47.7</b>	<b>10,353</b>	<b>13.9</b>	<b>12,676</b>	<b>17.0</b>	<b>12,611</b>	<b>16.9</b>	<b>524</b>	<b>0.7</b>	<b>38,522</b>	<b>51.6</b>	<b>74,685</b>	<b>100.0</b>

**टिप्पणी:** 1) \* : विदेश बैंक शामिल नहीं।  
2) - : शून्य / नगण्य  
3) राशि-राशि; प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।  
4) \*\* आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।  
**स्रोत:** बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।



अनुपात देशी बैंकों के लिए 2.73 प्रतिशत था जो गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात की तुलना में थोड़ा अधिक था (चार्ट V.14)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर वर्ग के लिए एनपीए अनुपात मार्च 2010 के अंत में निजी क्षेत्र के बैंकों के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 3.0 प्रतिशत अधिक था [परिशिष्ट सारणी IV.3(अ-आ)]।

4.40 विविध चैनलों के बीच, वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सरफेसाई) अधिनियम 2002 के अंतर्गत वसूल की गयी एनपीए की राशि 2009-10 में वसूल की गयी एनपीए की कुल राशि की आधी थी। इस प्रकार सरफेसाई अधिनियम एनपीए की वसूली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन रहा है। हाल के वर्षों में इस चैनल के अंतर्गत संलिप्त एनपीए की कुल राशि के प्रतिशत के रूप में सरफेसाई अधिनियम के अंतर्गत वसूली गयी एनपीए की राशि में निरंतर

**सारणी IV.17: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए**

(राशि करोड़ रुपये में)

वसूली चैनल	2008-09				2009-10			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	5,48,308	4,023	96	2.4	7,78,833	7,235	112	1.5
ii) डीआरटी	2,004	4,130	3,348	81.1	6,019	9,797	3,133	32.0
iii) सरफे साई अधिनियम	61,760*	12,067	3,982	33.0	78,366*	14,249	4,269	30.0

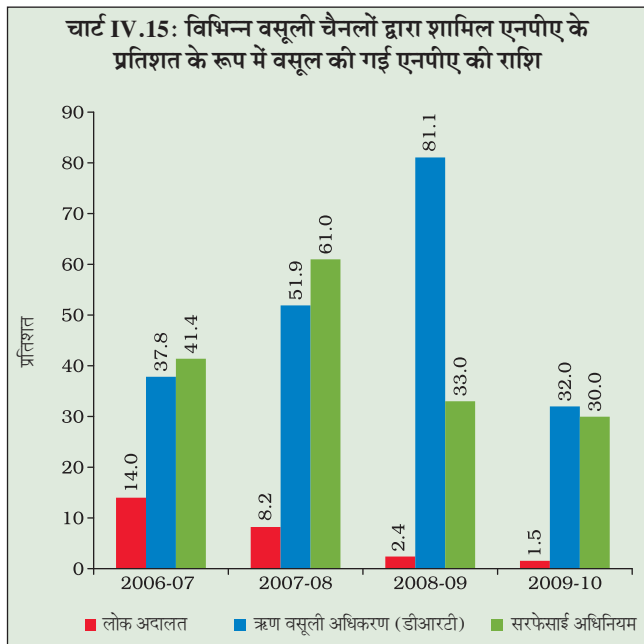
**टिप्पणी:** 1) \*: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई उस राशि से तात्पर्य है जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।  
2) #: भेजी गई सूचनाओं की संख्या

गिरावट हुई है, इस रुझान को 2008-09 और 2009-10 के बीच भी देखा जा सकता है (सारणी IV.17; चार्ट IV.15)।

4.41 जून 2010 के अंत में, भारत में 13 पंजीकृत प्रतिभूतिकरण / पुनःसंरचना कंपनियों (एससी/आरसी) थीं। जून 2010 के अंत में, इन कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि में बैंकों द्वारा सबसे बड़ी राशि का अंशदान किया गया। हाल के वर्षों में प्रतिभूतिकृत आस्तियों के कुल मूल्यों में बैंकों के प्रतिशत हिस्से में निरंतर गिरावट आई है, जबकि एससी / आरसी और पात्र संस्थागत क्रेता (क्यूआइबी) दोनों के हिस्से में वृद्धि हुई है (सारणी IV.18; चार्ट IV.16)। इसे आंशिक तौर पर पांच वर्ष की निर्धारित अवधि (इसे 21 अप्रैल 2010 से आठ वर्ष तक

के लिए बढ़ाया गया) के अंतर्गत एससी / आरसी द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के वसूल न होने की प्रवृत्ति से समझा जा सकता है। इस प्रवृत्ति से संभवतः एससी/आरसी की प्रतिभूति प्राप्तियों में अंशदान करने में वाणिज्यिक बैंकों की रुचि कम हुई है। चूंकि वसूल न की गयी प्रतिभूति प्राप्तियां एससी / आरसी की बहियों में बनी रहीं, उनके हिस्से में वृद्धि दिखनी जारी रही, जबकि वाणिज्यिक बैंकों के हिस्से में गिरावट आई।

4.42 2009-10 में एनपीए में वृद्धि बैंकों द्वारा प्रावधानन की बढ़ी हुई राशि में परिलक्षित हुई। इस वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की एनपीए प्रावधानन की राशि 22.4 प्रतिशत बढ़ी। अनुमानित हानियों को पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करने की चिंता को देखते हुए, अक्टूबर 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक ने



**सारणी IV.18: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियां**

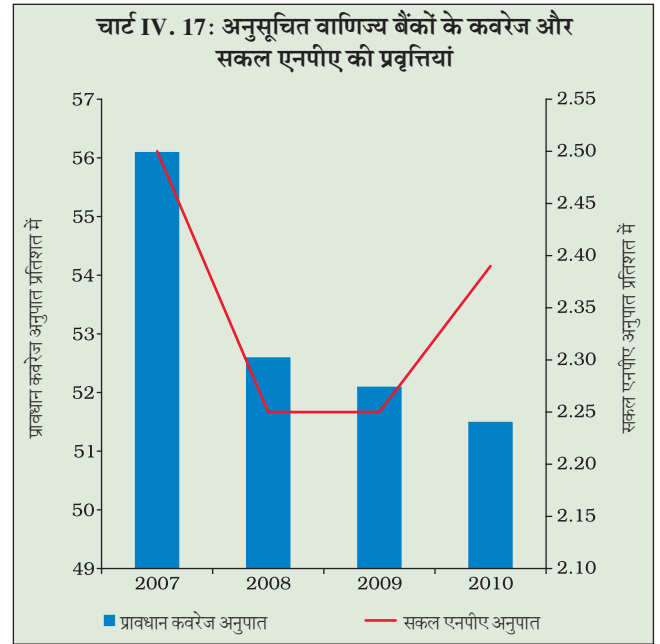
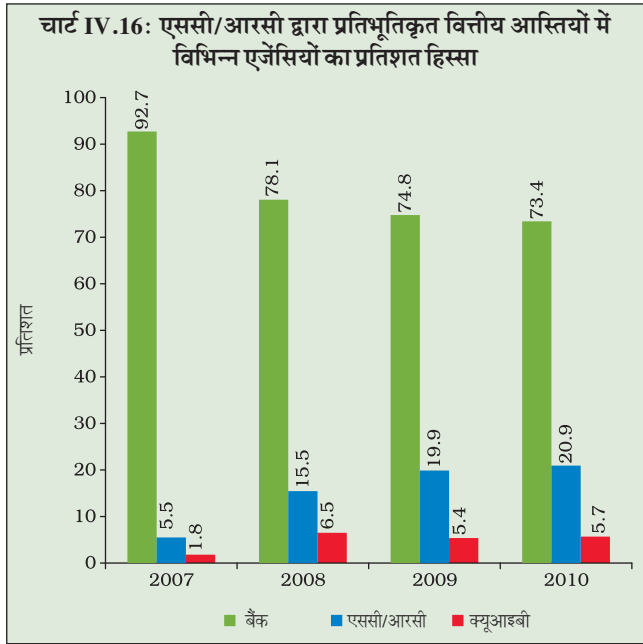
(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009	2010
1	2	3
1 अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	51,542	62,217
2 जारी प्रतिभूति रसीदें	12,801	14,050
3 के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(क) बैंक	9,570	10,314
(ख) एससी/आरसी	2,544	2,940
(ग) एफआइआइ	-	-
(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	687	797
4 पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	2,792	4,556

**टिप्पणी:** 1) शून्य / नगण्य।  
2) आंकड़े जून अंत से संबंधित हैं।

**स्रोत :** एससी / आरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।





अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने एनपीए की तुलना में प्रावधानन (एनपीए और चल प्रावधानों के विपरीत विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करते हुए) अनुपात को 70 प्रतिशत से कम न होने दें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि वे सितंबर 2010 से पहले प्रावधानन मानदंड को पूरा कर लें। 2009 और 2010 के बीच, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए की तुलना में प्रावधानन का कवरेज अनुपात मामूली रूप से घटकर 52.1 प्रतिशत से 51.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.17)। कवरेज अनुपात में गिरावट मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में देखी जा सकती है (सारणी IV.19)। यह अनुपात 2009 और 2010 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए काफी अधिक अर्थात् 8 प्रतिशत अंक गिरा। इस गिरावट के विपरीत, यह अनुपात निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लगभग 7 प्रतिशत अंक तथा विदेशी बैंकों के लिए लगभग 5 प्रतिशत अंक बढ़ा- मार्च 2010 के अंत में बैंक समूह एनपीए अनुपात सर्वाधिक बढ़ा।

### लीवरेज अनुपात

4.43 वित्तीय संकट के फलस्वरूप, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनीं बासेल समिति सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़े हुए बासेल II ढांचे के निर्माण पर बैंकिंग प्रणाली<sup>1</sup> की निगरानी के लिए एक गैर-जोखिम आधारित माप की आवश्यकता के बारे में चर्चाएं की गई हैं। यह तर्क दिया गया है कि ऐसे माप मौजूदा जोखिम आधारित मापों के संपूरक बन सकते हैं और प्रणाली में लिवरेज के निर्माण पर एक सीमा लगाकर अतिरिक्त रक्षोपाय शुरू कर सकते हैं। अमरीका जैसे देश एक साधारण माप का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुल समायोजित आस्तियों<sup>12</sup> की तुलना में टियर I पूंजी अनुपात का प्रयोग करके सर्वाधिक दृष्टिगोचर तुलनपत्र लीवरेज का पता लगाया जा सके। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक समान परिभाषा का प्रयोग करते हुए मार्च 2010<sup>13</sup> के अंत में लीवरेज अनुपात 6.6 प्रतिशत था। लिवरेज अनुपात में 2008 और 2009 के बीच एक मामूली गिरावट को

<sup>11</sup> हल्सटर में लिवरेज अनुपात पर विश्व बैंक द्वारा जारी संक्षिप्त नीति में भी उल्लिखित (2009), दि लिवरेज रेशियो - ए न्यू बाइंडिंग लिमिट ऑन बैंक्स <rru.worldbank.org>।

<sup>12</sup> टियर I पूंजी से तात्पर्य इक्विटी और आरक्षित निधियों से अमूर्त आस्तियां घटाना है, जबकि कुल समायोजित आस्तियों से तात्पर्य कुल आस्तियों से अमूर्त आस्तियां घटाना है, देखें हल्सटर (2009)।

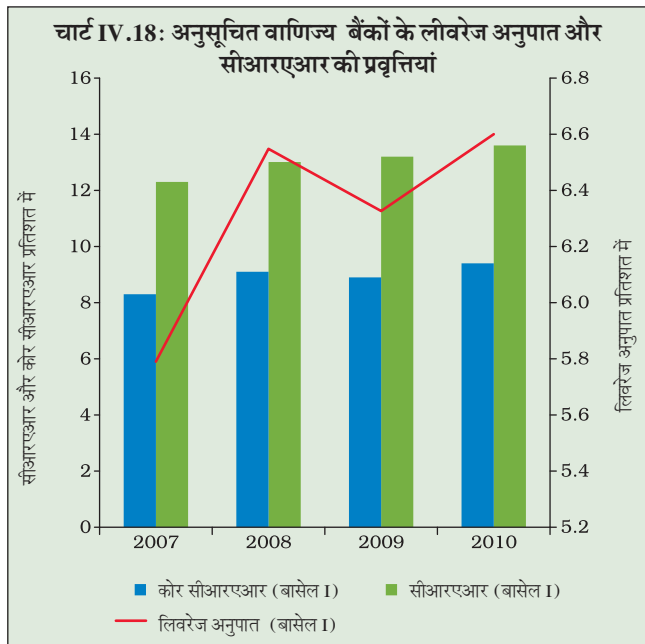
<sup>13</sup> यहां पर लिवरेज अनुपात को, बैंकिंग प्रणाली की कुल तुलनपत्र आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बासेल I ढांचे के अंतर्गत, टियर I पूंजी के रूप में सूचित किया गया है।

**सारणी IV.19: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार**

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>एनपीए के लिए प्रावधान</b>								
मार्च 2009 के अंत में	<b>22,658</b>	15,171	7,487	<b>9,391</b>	1,826	7,564	<b>3,448</b>	<b>35,498</b>
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	<b>18,037</b>	11,518	6,519	<b>10,393</b>	1,246	9,147	<b>3,576</b>	<b>32,007</b>
घटाएँ: बट्टा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अतिरिक्त का प्रतिलेखन	<b>12,293</b>	8,881	3,411	<b>8,782</b>	852	7,929	<b>2,810</b>	<b>23,886</b>
मार्च 2010 के अंत में	<b>28,402</b>	17,808	10,594	<b>11,002</b>	2,220	8,782	<b>4,214</b>	<b>43,619</b>
<b>ज्ञापन:</b>								
<b>सकल एनपीए</b>	<b>59,926</b>	36,395	23,532	<b>17,639</b>	3,622	14,017	<b>7,180</b>	<b>84,747</b>
सकल एनपीए (प्रतिशत) की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात								
मार्च 2009 के अंत में	<b>50.5</b>	57.2	40.8	<b>55.7</b>	59.4	54.9	<b>53.8</b>	<b>52.1</b>
मार्च 2010 के अंत में	<b>47.4</b>	48.9	45.0	<b>62.4</b>	61.3	62.7	<b>58.7</b>	<b>51.5</b>
<b>टिप्पणी :</b> *: आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।								
<b>स्रोत:</b> संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।								

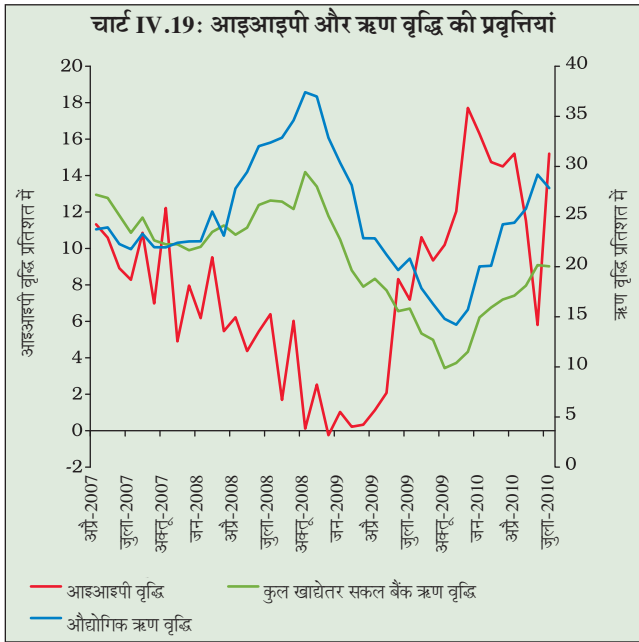
छोड़कर हाल के वर्षों में वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में गैर जोखिम आधारित लिवरेज अनुपात और जोखिम आधारित सीआरएआर दोनों तथा मूल सीआरएआर में निरंतर वृद्धि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती सुदृढ़ता की ओर संकेत करती है (चार्ट IV.18)।



**5. बैंक कर्ज का सेक्टर-वार संवितरण**

4.44 बैंक कर्ज का सेक्टर-वार संवितरण आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक कर्ज के योगदान तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को समझाता है। तदनुसार, यह खंड 2009-10 में बैंक कर्ज के सेक्टर-वार संवितरण की सामान्य प्रवृत्तियों और संबद्ध मामलों पर प्रकाश डालता है इसके पश्चात प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज और खुदरा कर्ज की प्रवृत्तियों तथा कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति कर्ज पर विस्तृत चर्चा की गई है।

4.45 जैसाकि खंड 2 में चर्चा की गई है, 2009-10 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक कर्ज में मंदी दिखी जो हाल में देखी गई प्रवृत्तियों की निरंतरता को दर्शाती है। फिर भी, सामान्य रूप से बैंक कर्ज में और विशेष रूप से औद्योगिक कर्ज की वृद्धि में तेजी के चिह्न दिखे इसके पश्चात वास्तविक क्षेत्र में रिकवरी के । जैसा कि चार्ट IV.19 में दर्शाया गया है, वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिविधि के प्रतिनिधि के रूप में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में वृद्धि, जो बैंकों के कंपनी क्षेत्र उधारों को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी, में जून 2009 से रिकवरी के चिह्न दिखे, लेकिन इसमें समेकन केवल अक्टूबर



**सारणी IV.20: सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन : प्रवाह**  
(वर्ष के दौरान घट-बढ़)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2008-09		2009-10	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5
<b>1. कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां</b>	<b>63,313</b>	<b>23.0</b>	<b>76,758</b>	<b>22.7</b>
<b>2. उद्योग</b>	<b>1,96,046</b>	<b>22.8</b>	<b>2,55,424</b>	<b>24.2</b>
<b>3. व्यक्तिगत ऋण</b>	<b>40,861</b>	<b>7.8</b>	<b>23,546</b>	<b>4.8</b>
जिसमें से: आवास	19,242	7.4	21,620	7.7
<b>4. सेवाएं</b>	<b>96,803</b>	<b>17.6</b>	<b>76,394</b>	<b>12.3</b>
जिसमें से:				
(i) थोक व्यापार (खाद्य खरीद को छोड़कर)	11,676	20.9	19,506	28.9
(ii) स्थावर संपदा उधार	29,072	45.9	-363	-0.4
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	19,897	25.2	19,068	19.3
<b>कुल गैर खाद्य सकल बैंक कर्ज (1 से 4)</b>	<b>3,97,021</b>	<b>18.0</b>	<b>4,35,122</b>	<b>16.7</b>

**टिप्पणी:** 1) डेटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं।

2) स्थावर संपदा ऋणों में गिरावट सितंबर 2009 से प्रभावी परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण है, जैसा कि पाद टिप्पणी सं.15 में दिया गया है।

**स्रोत:** सेक्टरोल एंड इंडस्ट्रियल डिप्लायमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट रिटर्न (मासिक)।

2009 के पश्चात आया जब इसने दोहरे अंक क्षेत्र में प्रवेश किया। यह वह अवधि थी जब औद्योगिक कर्ज और बैंक कर्ज में वृद्धि कुल मिलाकर बढ़नी शुरू हुई। अप्रैल 2006 से आगे के औद्योगिक कर्ज और उत्पादन के मासिक आंकड़ों को लेते हुए, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित औद्योगिक कर्ज की नमनीयता  $2.08^{14}$  थी।

4.46 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 2009-10 के दौरान खाद्येतर बैंक कर्ज के प्रमुख प्रेरक उद्योग और कृषि क्षेत्र थे। वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक क्षेत्र की कर्ज में काफी कमी आई (सारणी IV.20)<sup>15</sup>।

4.47 हाल के वर्षों में यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि औद्योगिक कर्ज से कुल बैंक कर्ज में वृद्धि के प्रति योगदान को मजबूत किया जाए। 2006-07 और 2009-10 के बीच, कुल बैंक कर्ज में औद्योगिक कर्ज का प्रतिशत योगदान निरंतर बढ़कर 37.1 प्रतिशत से 58.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.20) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के प्रति कर्ज के योगदान की भी बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। दूसरी तरफ, वैयक्तिक कर्ज, जो 2000 के

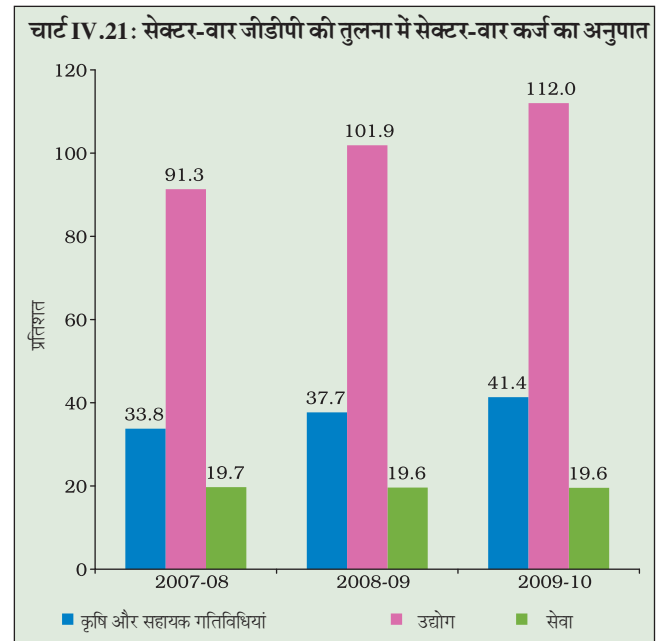
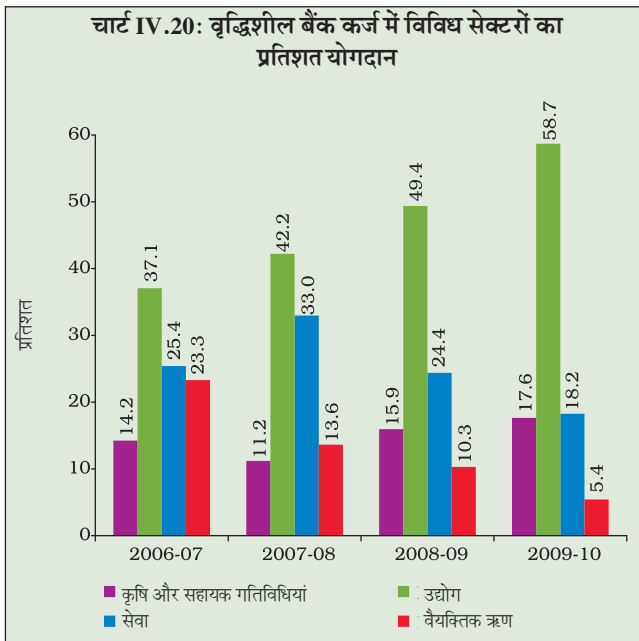
<sup>14</sup> इस कार्य के लिए प्रयुक्त रिग्रेसन नीचे दिया गया है:

$$\text{एलएन(औद्योगिक कर्ज)} = 2.01 + 2.08 \text{ एलएन(औद्योगिक उत्पादन)} \\ (1.40) (8.17)^*$$

\* 1 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।

$$\text{आर}^2 = 0.6.50$$

<sup>15</sup> सेवा क्षेत्र कर्ज में कमी की पीछे के कारणों में से एक था सितंबर 2009 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति कर्ज में काफी अधिक कमी। इन गतिविधियों में, अन्यो के बीच, शामिल था: (i) अपनी कारोबार गतिविधियों को चलाने के प्रयोजन के लिए स्थावर संपदा अर्जित करने हेतु उद्यमियों के प्रति एक्सपोजर, जिसको उन कारोबार गतिविधियों द्वारा सृजित नकदी प्रवाहों के द्वारा पूरा किया जाएगा; (ii) विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंपनी को दिए गए उधार, जो स्थावर संपदा गतिविधि से संबद्ध नहीं है; (iii) भविष्य में किराया प्राप्त राशियों की जमानत पर दिए गए उधार; (iv) ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाली निर्माण कंपनियों को दी गई कर्ज सुविधा; (v) अधिगृहण का वित्तीयन / निजी स्वामित्व वाले कार्यालय / कंपनी परिसरों का पुनरोद्धार; (vi) इकाइयों को अधिगृहीत करने / एसईजेड की औद्योगिक इकाइयों के प्रति एक्सपोजर; (vii) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए अग्रिम।



मध्य में उच्च कर्ज वृद्धि चरण के दौरान प्रमुख प्रेरक थे, में उनके प्रतिशत योगदान में गिरावट दिखी। कुल बैंक कर्ज की वृद्धि में सेवा क्षेत्र के योगदान में भी गिरावट दिखी।

4.48 2009-10 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए सेक्टरल जीडीपी के प्रति कर्ज अनुपात सर्वाधिक (112 प्रतिशत) था इसके पश्चात कृषि (और संबद्ध गतिविधियां) (41.4 प्रतिशत) तथा इसके बाद सेवा (19.6 प्रतिशत) का था (चार्ट IV.21)। हाल के वर्षों के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए अनुपात का बढ़ता रुझान दिख रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र<sup>16</sup> के लिए यह लगभग स्थिर है।

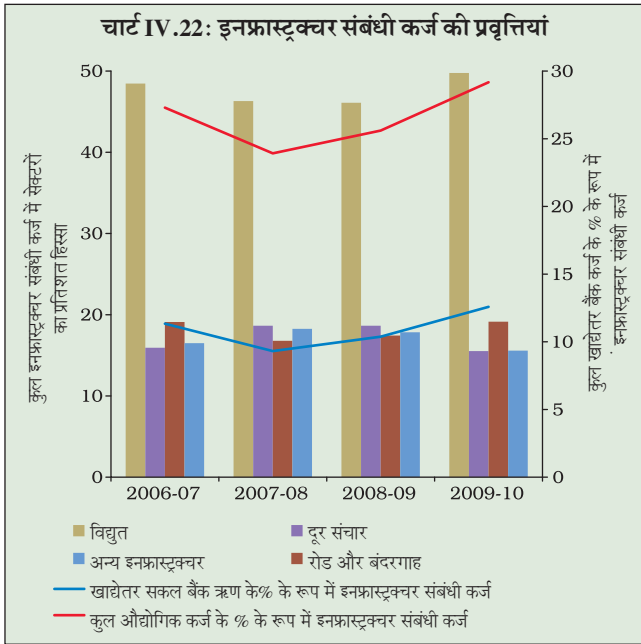
4.49 आर्थिक वृद्धि के लिए आधारभूत संरचना विकास की महत्ता को देखते हुए, आधारभूत संरचनागत वित्तीयन सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। तदनुसार, बैंकों को अनेकों विनियामक उपाय और रियायतें प्रदान की गई हैं जैसे टेकआउट फाइनेंसिंग, शिथिल किए गए आस्ति वर्गीकरण मानदंड और आधारभूत

संरचनागत उधार के लिए बढ़ायी गयी एक्सपोजर सीमा। आधारभूत संरचनागत वित्तीयन आंशिक रूप से ऐसे नीतिगत प्रयासों के कारण हाल के वर्षों में बैंक के कर्ज पोर्टफोलियो में एक बढ़ता घटक रहा है। कुल खाद्येतर सकल बैंक कर्ज और कुल औद्योगिक कर्ज के प्रतिशत के रूप में आधारभूत संरचनागत कर्ज में 2007-08 से निरंतर वृद्धि दिखी है। 2009-10 में आधारभूत संरचनागत वित्त की सबसे बड़ी घटक बिजली रही है जो बैंकों के कुल आधारभूत संरचनागत कर्ज की लगभग आधी है (चार्ट IV.22)।

### प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को कर्ज

4.50 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भारत में बैंक कर्ज सुपुर्दगी के एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। 2009 और 2010 के बीच, देशी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से कृषि कर्ज में वृद्धि के कारण हुई। 2009-10 में देशी बैंकों के कृषि कर्ज में वृद्धि 22.6 प्रतिशत

<sup>16</sup> वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधन प्रदान करने में बैंकेतर स्रोतों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, बैंक कर्ज किसी क्षेत्र के प्रति कुल कर्ज उपलब्धता का केवल एक आंशिक चित्र प्रस्तुत कर सकता है। देखें तिमाही समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की सारणी IV.9, वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधन प्रदान करने में बैंक और बैंकेतर स्रोत के प्रतिशत हिस्से के लिए पहली तिमाही- 2010-11।



थी। लेकिन, 2009-10 में विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज में अपने देशी प्रतिपक्षियों की तुलना में काफी कम अर्थात् 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

4.51 मार्च 2010 के अंत में, देशी (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) तथा विदेशी बैंकों ने क्रमशः 40 और 32 प्रतिशत के अपने समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों से अधिक की पूर्ति की (सारणी IV.21 और IV.22)। लेकिन, 2010 में वियोजित स्तर पर, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से तीन और निजी क्षेत्र के 22 बैंकों में से 2 समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा, 27 विदेशी बैंकों में से तीन भी समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके (परिशिष्ट सारणी IV.4 (अ-इ) और IV.5(अ-इ))।

4.52 कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्य (18 प्रतिशत) को पूरा करने में देशी बैंकों के निष्पादन से संबंधित कुछ चिंताएं थीं। कुल स्तर पर, मार्च 2010 के अंत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों बैंक कृषि के लिए 18 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के नीचे थे। वियोजित स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के आधे से अधिक बैंक (27 में से 15) निजी क्षेत्र के ठीक आधे बैंक (22 में से 11) कृषि उप-लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। निजी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में निष्पादन

**सारणी IV.21: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)**

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2009	2010अ	2009	2010अ
1	2	3	4	5
<b>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम#</b>	<b>7,24,150</b>	<b>8,64,564</b>	<b>1,87,849</b>	<b>2,15,552</b>
	<b>(42.7)</b>	<b>(41.6)</b>	<b>(46.2)</b>	<b>(45.9)</b>
जिसमें से				
कृषि	2,99,415	3,70,730	76,102	89,769
	(17.6)	(17.1)	(18.7)	(15.6)
जिसमें से				
सूक्ष्म और लघु उद्यम	1,91,408	2,78,398	46,656	64,534
	(11.3)	(13.2)	(11.8)	(13.7)

टिप्पणी : 1) अ : अनंतिम

- # : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोफ्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल हैं।
- ^ : अप्रत्यक्ष कृषि के प्रतिशत के आकलन के लिए एएनबीसी के 4.5 प्रतिशत को हिसाब में लिया गया है।
- कोष्ठक के आंकड़े निवल बैंक ऋण / समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) / तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के कर्ज के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की तुलना में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सापेक्षिक रूप से कमजोर था, जबकि निजी क्षेत्र के अधिकांश नए बैंक कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्य को पूरा कर सके। इसके

**सारणी IV.22: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2009		2010अ	
	राशि	एएनबीसी/सीईओ बीएसई की तुलना में प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/सीईओ बीएसई की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
<b>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #</b>	<b>55,415</b>	<b>34.2</b>	<b>60,290</b>	<b>35.0</b>
जिसमें से				
निर्यात ऋण	31,511	19.4	35,466	20.6
जिसमें से				
सूक्ष्म, लघु और उद्यम	18,063	11.2	21,080	12.2

टिप्पणी: 1) अ: अनंतिम:

- # : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रो क्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल हैं।
- \* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर नए दिशा निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखा गया है।
- एएनबीसी/सीईओबीएसई - समायोजित निवल बैंक ऋण / तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के बराबर कर्ज राशि, जो भी अधिक हो।

अलावा, निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंक (22 में से 15) निर्बल वर्ग के अंतर्गत 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। निर्यात और सूक्ष्म, छोटे तथा मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत उप-लक्ष्यों को पूरा करने में विदेशी बैंकों का निष्पादन काफी अधिक अच्छा था, साथ ही 2010 में अधिकांश विदेशी बैंक इन लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सके।

### खुदरा कर्ज

4.53 बैंकों के वैयक्तिक कर्ज पोर्टफोलियो सहित खुदरा कर्ज में 2004-05 और 2005-06 के बीच वृद्धि में तेजी दिखी लेकिन, बाद के वर्षों में इसमें गिरावट दिखी (चार्ट IV.23)। 2009-10 में खुदरा कर्ज वृद्धि में केवल मामूली वृद्धि दिखी (सारणी IV.23)।

4.54 2008-09 और 2009-10 बीच खुदरा कर्ज वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी के लिए आवास उधार खंड, जो भारतीय बैंकों के कुल खुदरा कर्ज का अकेले सबसे बड़ा हिस्सा था, को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया। आवास उधार वृद्धि में तेजी आंशिक रूप से 2009-10 के अधिकांश भाग के दौरान जारी कम ब्याज दरों के कारण थी, ऐसा इस तथ्य के बावजूद था कि संपत्ति के मूल्यों, जिनमें संकट के ठीक पश्चात 2008-09 में करेक्शन आया, में 2009-10 के दौरान तेजी दिखी (देखें आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट- 2009-10 के पेज 53 का चार्ट II.43)।

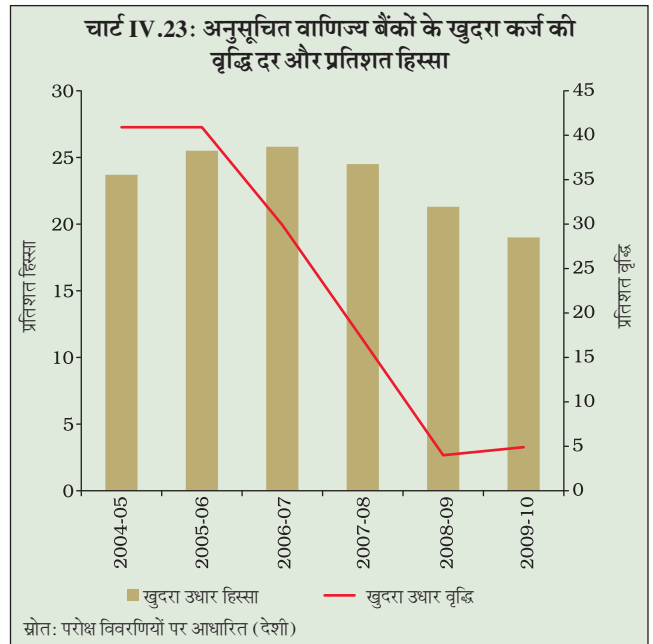
### सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा उधार पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1. आवास उधार	2,63,235	3,15,862	4.1	20.0
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5,431	3,032	13.1	-44.2
3. क्रेडिट कार्ड प्राप्ति	29,941	21,565	9.1	-28.0
4. ऑटो उधार	83,915	78,346	-4.6	-6.6
5. अन्य व्यक्तिगत उधार	2,11,294	2,03,947	6.9	-3.5
<b>कुल खुदरा उधार (1 से 5)</b>	<b>5,93,816</b>	<b>6,22,752</b>	<b>4.0</b>	<b>4.9</b>
	<b>(21.3)</b>	<b>(19.0)</b>		

**टिप्पणी:** कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिमों में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की परोक्ष विवरणियों (देशी) में दिए गए अनुसार है।

**स्रोत:** परोक्ष विवरणी पर आधारित (घरेलू)।



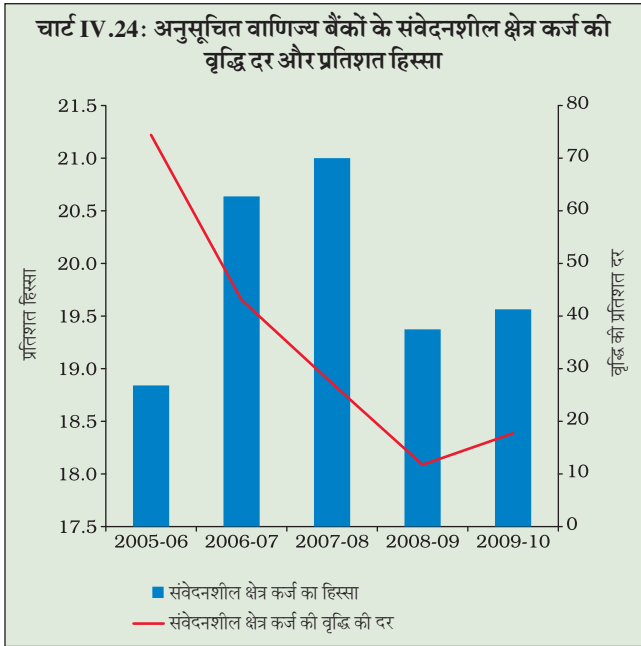
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, वाहन कर्ज और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों जैसे अन्य खुदरा खंड में 2009-10 में, ऋणात्मक वृद्धि दिखी। अधिकांश खुदरा क्षेत्र के दर-संवेदनशील होने के चलते, भविष्य में इन क्षेत्रों के प्रति कर्ज उभरते ब्याज दर वातावरण से प्रभावित होगा।

### संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कर्ज

4.55 संबंधित आस्ति/उत्पाद बाजार में कीमत उतार-चढ़ाव के कारण पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य बाजार को बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिए संवेदनशील माना गया है। मार्च 2010 के अंत में इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कर्ज कुल मिलाकर कुल बैंक कर्ज का 19.6 प्रतिशत था जबकि स्थावर संपदा क्षेत्र का हिस्सा वैयक्तिक रूप से 16.6 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

4.56 2009-10 में हल्की वृद्धि को छोड़कर हाल के वर्षों में वृद्धि दर और संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कर्ज के हिस्से दोनों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है (चार्ट IV.24)। तथापि, संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कर्ज के हिस्से में गिरावट मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कारण थी (परिशिष्ट सारणी IV.6)। विदेशी जिनका अन्य बैंक समूह की तुलना में संवेदनशील क्षेत्र के प्रति काफी अधिक एक्सपोजर था, में उनके कुल कर्ज के





प्रतिशत के रूप में इन क्षेत्रों को दिए गए कर्ज के हिस्से में वृद्धि दिखी।

## 6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

4.57 पूंजी बाजार बैंकों को अपने पूंजी आधार को मजबूत करने और बैंकों के शेयरों के लिए ट्रेडिंग धरातल प्रदान करने हेतु उन्हें संसाधन जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है। इसलिए, एक उदारकृत और प्रतियोगी वातावरण में, पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालन उनके बैंकिंग कारोबार की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं। इस खंड में प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालनों पर प्रकाश डाला गया है।

### सारणी IV.24: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		कुल योग
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)
2008-09	-	-	-	-	-	-	-
2009-10	325	-	313	-	638	-	638

- : शून्य / नगण्य।

## प्राथमिक बाजार में बैंकों के परिचालन

4.58 2008-09 के दौरान परहेज के पश्चात, 2009-10 में बैंकों ने संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार का सहारा लेना शुरू किया। प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण में आया यह पुनर्जीवन पिछले वर्ष के दौरान दिखी चलनिधि तंगियों को आसान करने, द्वितीयक बाजार में अच्छे कारोबार और कंपनियों द्वारा बेहतर निवेश की मांग का परिणाम था (सारणी IV.24)।

4.59 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक रिकवरी की धीमी गति से संबंधित चिंताओं और यूरोपीय सरकारी कर्ज संकट के अभ्युदय को देखते हुए, वैश्विक पूंजी बाजार से देशी बैंकों द्वारा संसाधन के संग्रहण में पिछले वर्ष की तरह 2009-10 में पुनर्वापसी के कोई बड़े चिह्न नहीं दिखे (सारणी IV.25)। 2009-10 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जीडीआर के माध्यम से केवल 843 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गये।

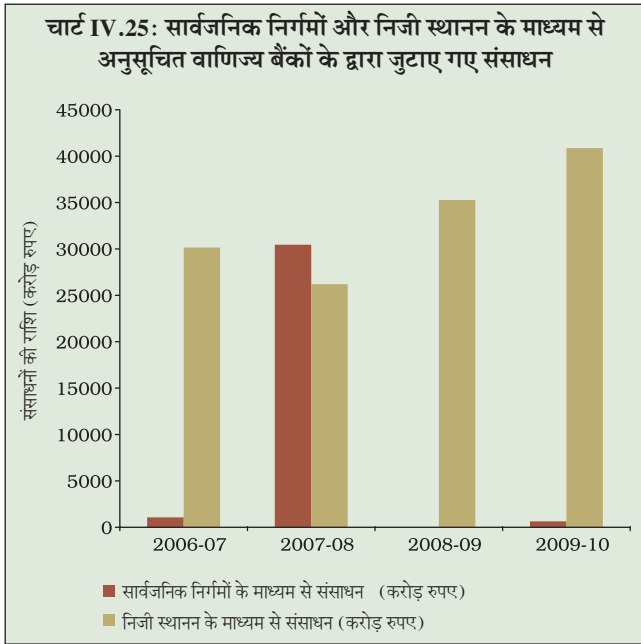
4.60 संसाधनों को जुटाने में व्यापक रूप से एक दूसरे के स्थानापन्न के रूप में कार्य करने वाले निजी स्थानन और सार्वजनिक निर्गमों को देखते हुए, 2008-09 में, जब देशी पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से संसाधनों का कोई संग्रहण नहीं

### सारणी IV.25: यूरो निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09	2009-10
1	2	3
<b>यूरो निर्गम</b>	<b>4,788</b>	<b>15,967</b>
(i) एडीआर	-	<b>7,763</b>
जिसमें से, वित्तीय संस्थाएं	-	-
जिसमें से, बैंक	-	-
क) निजी	-	-
ख सार्वजनिक	-	-
(ii) जीडीआर	<b>4,788</b>	<b>8,204</b>
जिसमें से, वित्तीय संस्थाएं	-	-
जिसमें से, बैंक	-	843
क) निजी	-	843
ख सार्वजनिक	-	-
(iii) एफसीसीबी	<b>उ.न.</b>	<b>उ.न.</b>

**टिप्पणी :** 1) उ.न. : उपलब्ध नहीं.  
2) - : शून्य / नगण्य  
3) एफसीसीबी - विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड  
4) एडीआर/जीडीआर: अमरीकी / वैश्विक निक्षेपगार रसीदें ।



हुआ था, निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों के संसाधन संग्रहण में 34.6 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दिखाई (चार्ट IV.25)। बैंकों ने 2009-10 में निजी स्थानन के माध्यम से निधियां जुटाना जारी रखा लेकिन वृद्धि घटकर 15.8 प्रतिशत हो गई। 2009-10 से निजी स्थानन के माध्यम से संसाधनों के संग्रहण में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों को उत्तरदायी माना गया (सारणी IV.26)।

### द्वितीयक बाजार में बैंकिंग शेयरों का निष्पादन

4.61 देशी शेयर बाजार, जिसमें वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव के कारण 2008-09 में काफी अधिक हानियां हुई थीं, में 2009-10

**सारणी IV.26: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन**

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2008-09		2009-10	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	13	6,967	18	17,101
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	52	28,304	63	23,762
<b>कुल</b>	<b>65</b>	<b>35,271</b>	<b>81</b>	<b>40,863</b>

स्रोत: मर्चेन्ट बैंकर और वित्तीय संस्था।

में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 80.5 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो व्यापक रूप से देशी आर्थिक रिकवरी और एफआइआइ प्रवाह की शुरुआत को दर्शाती है। यद्यपि दुर्बल कर्ज संकट और संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र के देशों की स्थिति संबंधी अनिश्चितता ने 2010 की शुरुआत में शेयर बाजार भाव को प्रभावित किया, पूरे वर्ष के दौरान शेयर मूल्यों में सामान्य उर्ध्वगामी चढ़ाव दिखा जब बीएसई सेंसेक्स मध्य सितंबर 2010 में संकट के पूर्व स्तर पर पहुंच गया।

4.62 2009-10 के दौरान बीएसई बैंकेक्स (बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाला) ने बीएसई सेंसेक्स की तुलना में काफी अधिक मुनाफा अर्जित किया जो बैंक शेयरों में अच्छे कारोबार को परिलक्षित करता है (सारणी IV.27)। जबकि प्रतिफल काफी अधिक थे, बीएसई बैंकेक्स की स्थिरता भी, जो इन शेयरों में ट्रेडिंग के जोखिम को दर्शाती है, 2009-10 में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी।

4.63 समग्र रुझान के अनुरूप, 2009-10 में सभी 39 सूचीबद्ध बैंकों ने मुनाफा दर्ज किया। बैंक शेयरों के मूल्य में उर्ध्वगामी चढ़ाव सभी बैंक शेयरों के मूल्य / अर्जन (पी/ई) अनुपात की वृद्धि में भी दिखा। लेकिन, निजी क्षेत्र के उनके

**सारणी IV.27: जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, कारोबार और बैंकों के स्टॉकों का पूंजीकरण**

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11#
1	2	3	4	5
<b>1. प्रतिफल*</b>				
बीएसई बैंकेक्स	18.0	-41.8	137.2	31.9
बीएसई सेंसेक्स	19.7	-37.9	80.5	14.8
<b>2. अस्थिरता@</b>				
बीएसई बैंकेक्स	13.8	23.8	16.5	6.0
बीएसई सेंसेक्स	12.0	24.2	11.9	10.6
<b>3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा</b>	<b>6.6</b>	<b>12.3</b>	<b>10.0</b>	<b>9.8</b>
<b>4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा **</b>	<b>7.2</b>	<b>7.7</b>	<b>8.7</b>	<b>12.7</b>

टिप्पणी : 1) \* :अंक दर अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ़।  
 2) @ : घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।  
 3) \*\* : अवधि के अंत में।  
 4) # : अप्रैल - अक्टूबर 15, 2010।  
 स्रोत: ब्लूमबर्ग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।

प्रतिपक्षियों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के मामले में पीई अनुपात में वृद्धि काफी तीव्रतर थी (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.64 2007-08 और 2008-09 के बीच कुल पूंजी बाजार कारोबार में उनका हिस्सा लगभग दो गुना होने के पश्चात, बैंक के शेयरों में 2009-10 और 2010-11 में भी (अप्रैल और 15 अक्टूबर के बीच) कुल कारोबार में उनके हिस्से में गिरावट दिखी (सारणी IV.27)। दूसरी तरफ, कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों के हिस्से में 2007-08 से वृद्धि दर्ज हुई।

### 7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप

4.65 यद्यपि, 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से ऊपर बनी रही, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक (21 में से 11) सीमा के काफी निकट थे (सारणी IV.28; परिशिष्ट सारणी IV.8)। इसने पुनर्पूँजीकरण के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निरंतर कर्ज सृजन सुनिश्चित किया जा सके यदि सरकारी शेयरधारिता के 51 प्रतिशत की वैधानिक सीमा को बनाए<sup>17</sup> रखना है।

#### सारणी IV.28: निजी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

शेयर धारिता की श्रेणी	कुल निजी-शेयर धारिता	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	1	2	10
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	3	4	11
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	2	7	-
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	4	7	-
40 से अधिक और 49 प्रतिशत तक	11	1	-

**टिप्पणी:** 1) - शून्य / नगण्य  
2) 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआई बैंक लिमिटेड।

#### सारणी IV.29: विदेशी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक

शेयर होल्डिंग की श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्रके नए बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
1	2	3	4
शून्य	1	-	2
10 प्रतिशत तक	9	-	3
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	11	-	1
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	-	1	4
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	-	1	3
40 से अधिक और 50 प्रतिशत तक	-	2	1
50 से अधिक और 60 प्रतिशत तक	-	1	-
60 से अधिक और 70 प्रतिशत तक	-	2	1

**टिप्पणी:** 1) - शून्य/नगण्य।

2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

4.66 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, विदेशी शेयरधारिता का प्रतिशत केवल 20 प्रतिशत था। फिर भी, निजी क्षेत्र के नये बैंकों में विदेशी शेयरधारिता की सीमा काफी अधिक थी; इस बैंक समूह के सात में से तीन बैंकों की विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी IV.29)।

### 8. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

4.67 सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के क्षेत्र की गतिविधियां बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि और समावेशिता को सुदृढ़ता से समर्थन करती हैं इस प्रकार ये समावेशी आर्थिक वृद्धि को सुगम बनाती हैं। आइटी न केवल बैंक-एंड प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत करके बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी कार्यक्षमता को बढ़ाती है, यह फ्रंट-एंड परिचालनों में सुधार करती है और ग्राहकों के लिए

<sup>17</sup> 2009-10 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण और संबद्ध मुद्दों पर चर्चा के लिए अध्याय I देखें।

लेन-देन की लागत कम करने में मदद करती है। यह बैंकिंग क्षेत्र और छोटे ग्राहकों के लिए सस्ते, आसान और तीव्र छोटे-छोटे खुदरा लेन-देन करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को लाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

4.68 सर्वाधिक मौलिक तरीका जिसमें प्रौद्योगिकी ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के चेहरे को बदल दिया है कम्प्यूटरीकरण रहा है। जबकि निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक इस मामले में आगे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से अपने परिचालनों को अद्यतन करने के लिए निवेश कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में से, मार्च 2010 के अंत में 97.8 प्रतिशत पूरी तरह से कम्प्यूटराज्ड थीं (सारणी IV.30; परिशिष्ट IV.9)। एसबीआई समूह की सभी शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत थीं।

4.69 सितंबर 1999 से मार्च 2010 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 'कम्प्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास' पर संचित व्यय 22,052 करोड़ रुपए था (परिशिष्ट सारणी IV.10)। वार्षिक आधार पर, 2009-10 में, 'कम्प्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास' पर व्यय में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.70 बैंक शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण से करीबी से जुड़ी प्रौद्योगिकीय गतिविधि में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया जाना है। खुदरा तथा कारपोरेट बैंकिंग कार्यकलापों

**सारणी IV.30: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण**  
(मार्च के अंत में)

(कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत)

श्रेणी	2009	2010
1	2	3
<b>पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)</b>	<b>95.0</b>	<b>97.8</b>
i) कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत शाखाएं	79.4	90.0
ii) पहले से कम्प्यूटरीकृत शाखाएं #	15.6	7.8
<b>आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत शाखाएं</b>	<b>5.0</b>	<b>2.2</b>
# : कोर बैंकिंग समाधान के तहत आने वाली शाखाओं के अलावा।		

का समर्थन करके सीबीएस बैंकों को एक ही स्थान से निरंतर आधार पर ग्राहक-केंद्रित कई सारी सेवाएं प्रदान करने में सहायता पहुंचाता है और इस प्रकार वित्तीय सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सब कुछ मिलने वाली "एक दुकान" की धारणा को वास्तविक रूप दे दिया है। 2009-10 की महत्वपूर्ण गतिविधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीबीएस को लागू करने के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होना है। मार्च 2009 के अंत में ऐसी शाखाओं का प्रतिशत 79.4 था जो मार्च 2010 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.30)। इन सब के बीच में भी भारतीय स्टेट बैंक समूह की सीबीएस शाखाओं का प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में काफी अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

4.71 जबकि सामान्य रूप से कम्प्यूटरीकरण तथा विशेष रूप से सीबीएस के कार्यान्वयन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सीबीएस से आगे के उन क्षेत्रों की ओर देखना महत्वपूर्ण होगा जिन्हें इस प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर ग्राहकों को न केवल बेहतर तथा दक्षतापूर्ण सेवाएं दी जा सकती है बल्कि सूचनाओं का प्रभावी ढंग से सृजन तथा प्रबंधन किया जा सकता है। कार्मिकों द्वारा बिना हस्तक्षेप के सूचना प्रबंधन के दूसरे पक्ष के संबंध में बैंकों से रिज़र्व बैंक में स्वचलित तरीके से आंकड़ों की प्राप्ति की एक प्रणाली के बारे में विचार किया जा रहा है; इस प्रणाली से मिलनेवाले लाभ के बारे में बॉक्स IV.3 में चर्चा की गयी है।

4.72 तीसरा प्रौद्योगिकीय विकास जिसने बैंकिंग सेवाओं के वितरण की प्रणाली में क्रांति ला दी है वह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)। एटीएम, विशेष रूप से शाखा से भिन्न स्थानों पर स्थित एटीएम, ग्राहकों को कभी भी नकदी के आहरण की सुविधा उपलब्ध कराकर बैंक शाखाओं के स्थानापन्न स्थल के रूप में कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में एटीएम की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 2009-10 में इनकी संख्याओं में 37.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। महत्वपूर्ण रूप से, वर्ष के दौरान 44.6 प्रतिशत पर ऑफ-साइट एटीएम की संख्याओं में वृद्धि अपेक्षाकृत ऊंची रही है। मार्च 2010 के अंत में, कुल एटीएम की तुलना में ऑफ साइट एटीएम का प्रतिशत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 45.7 प्रतिशत था (सारणी IV.31; चार्ट IV.26; परिशिष्ट सारणी IV.11)।

### बॉक्स IV.3: बैंकिंग क्षेत्र में स्वचलित डेटा प्रवाह: प्रभावी डेटा संचारण और प्रबंधन का भविष्य

संसार भर में केन्द्रीय बैंक और विभिन्न विनियामक निकाय विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर होते हैं, ये सूचनाएं उनको कुशल तरीके से अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को करने में मदद करती हैं। इससे उन्हें समुचित नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। सूचनाओं में वे डेटा शामिल होने चाहिए जिन्हें अखंडता, विश्वसनीयता और सटीकता के सिद्धांतों के आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए। ये सूचनाएं व्यवस्थित रूप से और सार्थक रूप से डेटा से निकाली गयी होती हैं। इसलिए यह सुसंगत है कि डेटा और सूचनाएं विनियामकों तक न केवल समय पर पहुंचे बल्कि वे त्रुटियों और गड़बड़ियों से भी मुक्त हों। इसलिए आवश्यकता है कि प्रोसेसिंग के साथ गुणवत्ता डेटा का मिलान सुनिश्चित किया जाए और समयबद्ध रूप से उचित स्तर तक उनका प्रवाह हो।

स्वचलित डेटा प्रवाह (एडीएफ) की अवधारणा इस अपेक्षा को पूरा करती है जिसमें डेटा का अंतरण अबाध रूप से होस्ट प्रणाली से प्राप्तकर्ता प्रणाली तक होता है, इससे पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल, सुसंगत और भरोसेमंद बन जाती है। साथ ही, एक बड़े 'स्पिन-ऑफ' लाभ के लिए, स्वचलित डेटा प्रवाह की प्रणाली 'होस्ट' स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी सुचारु बनाती है इस प्रकार यह सक्षम एमआइएस उपकरण के रूप में कार्य करती है और उत्तम डेटा प्रबंधन व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है।

आइटी बैंकों को न केवल अपने ग्राहकों को कम मूल्य पर सुदृढ़ और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है बल्कि सूचनाओं को प्रभावी तरीके से सृजित करने और उनके प्रबंधन का भी कार्य करती है।

बैंकों द्वारा समय पर सुसंगत आंकड़ों को प्रस्तुत करना रिजर्व बैंक के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों से रिजर्व बैंक को स्वचलित तरीके से डेटा प्रवाह न केवल समय उनकी पर उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रभावी निर्णय समर्थनकारी प्रणाली बनाने के लिए एक बेहतर सूचना वातावरण भी प्रदान करेगा। ग्राहकों और लेन-देनों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा अब बैंकों के पास उपलब्ध है, जिनका समुचित विश्लेषण के माध्यम से लाभपूर्वक उपयोग, कारोबार नीति को अनुकूल बनाने, विविधीकृत आंतरिक और बाह्य एमआइएस अपेक्षाओं को पूरा करने तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के उद्देश्य के साथ, किया जा सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों का कम्प्यूटरीकरण काफी ऊंचाई तक पहुंच जाने के साथ (सीबीएस को अपनाने के बाद भी), यह संभव हो गया है कि आइटी संसाधनों के लाभों का उपयोग करके डेटा प्रवाह और सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जाए। एडीएफ की प्रणाली से इन लाभों का फायदा उठाने और अगले उच्चतर स्तर तक बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच सूचना के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

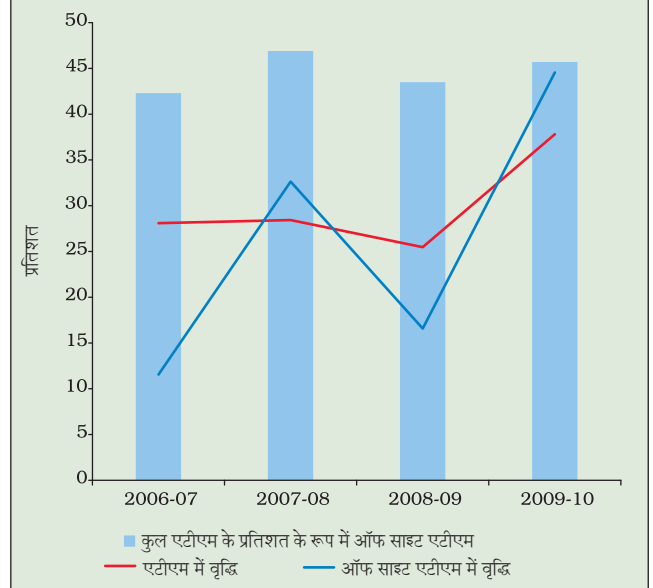
4.73 सकल देशी उत्पाद की तुलना में सकल इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के मूल्य के अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है जो हाल की वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अपनाने के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है (चार्ट IV.27)। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के विभिन्न प्रकारों के बीच ईएफटी-एनईएफटी -

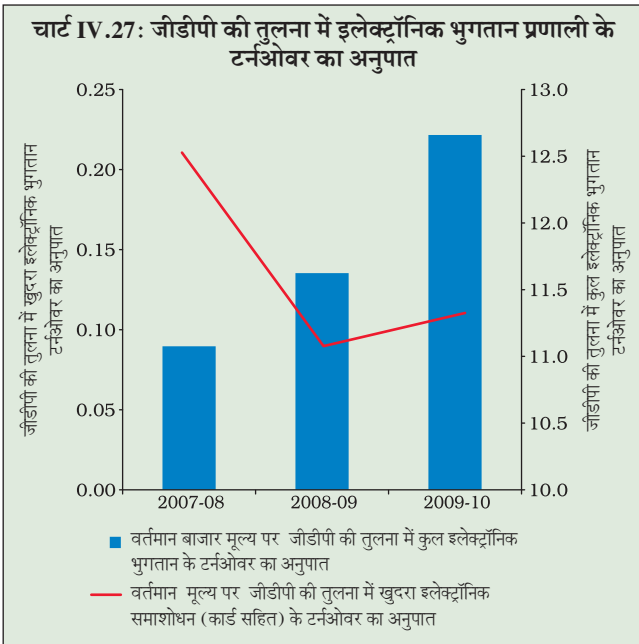
का केंद्रीकृत वर्सन खुदरा भुगतानों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है जबकि बड़ी राशि के भुगतानों को निपटारे के माध्यम के रूप में आरटीजीएस में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि

### सारणी IV.31: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या (मार्च 2010 को समाप्त)

बैंक समूह	ऑन - साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या	कुल एटीएम के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट एटीएम
1	2	3	4	5
<b>1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>23,797</b>	<b>16,883</b>	<b>40,680</b>	<b>41.5</b>
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक	12,655	7,047	19,702	35.8
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	11,142	9,836	20,978	46.9
<b>2 निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>8,603</b>	<b>9,844</b>	<b>18,447</b>	<b>53.4</b>
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2,266	1,124	3,390	33.2
2.1 निजी क्षेत्र के नए बैंक	6,337	8,720	15,057	57.9
<b>3 विदेशी बैंक</b>	<b>279</b>	<b>747</b>	<b>1,026</b>	<b>72.8</b>
<b>सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक</b>	<b>32,679</b>	<b>27,474</b>	<b>60,153</b>	<b>45.7</b>

चार्ट IV.26: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या में वृद्धि



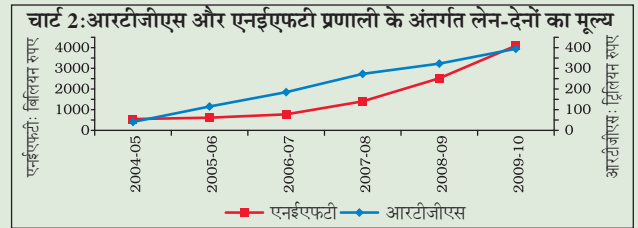


हुई है। एनईएफटी तथा आटीजीएस दोनों की गतिविधियों में समानता तथा अंतर के बारे में बॉक्स IV.4 में जानकारी दी गयी है।

4.74 आगे चलकर बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनका समाधान किया जाना है। ये मुद्दे एमआइएस को व्यवस्थित करने के उपाय के रूप में बैंक ऑफिस में और सुधार लाने, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग को सुदृढ़ करने, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तथा आइटी अभिशासन से जुड़े हैं। बैंक ऑफिस में प्रौद्योगिकीय विकास होने से बैंकों के संसाधनों को अधिक मात्रा में बैंक ऑफिस से निकालकर फ्रंट ऑफिस में लगाने में सुविधा होगी जिससे उनकी सेवाओं को ग्राहक केंद्रित बनाने तथा वित्तीय विस्तार तथा वित्तीय समावेशन को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

**बॉक्स IV.4: आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली : परिचालनों के पैमाने का एक तुलनात्मक विश्लेषण**

रिजर्व बैंक ने विभिन्न खुदरा और उच्च मूल्य लेन-देनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को सुकर बनाने हेतु कई उपाय किये हैं। आरटीजीएस एक उच्च मूल्य भुगतान प्रणाली है जो 1,00,000 रुपए और अधिक के ग्राहक और अंतर-बैंक लेन-देनों को प्रोसेस करती है जबकि एनईएफटी अनिवार्य रूप से एक खुदरा प्रणाली है। जबकि आरटीजीएस एक तत्काल सकल निपटान व्यवस्था है, एनईएफटी एक निकट-तत्काल प्रणाली है जिसमें निपटान घंटों के अंतराल पर किये जाते हैं।



आरटीजीएस और एनईएफटी में 70,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध है जिसमें संबंधित प्रणाली में 119 सदस्य और 99 बैंक भाग ले रहे हैं।

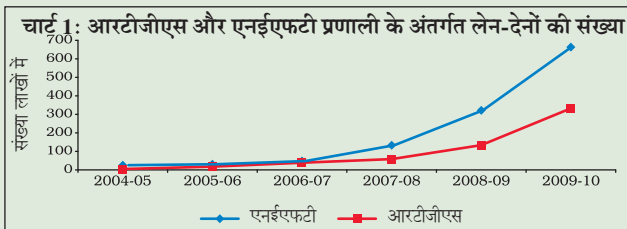
**बैंक समूह-वार विश्लेषण**

दोनों प्रणालियों के माध्यम से किये गये लेन-देनों की संख्या में वर्षों के दौरान भारी वृद्धि हुई है (चार्ट 1 और चार्ट 2)। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आरटीजीएस एनएफटी की तुलना में बड़े मूल्य के भुगतान वाली प्रणाली है, आरटीजीएस में किये गये लेन-देनों का मूल्य बहुत अधिक होता है। तथापि, दोनों प्रणालियों के लेन-देनों के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति से पता चलता है कि एनईएफटी में किये गये लेन-देनों में राशि 2007-08 से कई गुना बढ़ी है, जबकि आरटीजीएस में सापेक्षिक रूप से स्थिर वृद्धि हुई है।

आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों के 2008-09 और 2009-10 के बैंक समूह-वार डेटा दर्शाते हैं कि प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंक प्रमुख सहभागी हैं और उनका हिस्सा कुल लेन-देनों के एक-तिहाई से अधिक है। एसबीआइ समूह का हिस्सा आरटीजीएस प्रणाली में कुल लेन-देनों का 22 प्रतिशत है लेकिन, एनईएफटी में उनकी उपस्थिति केवल 10 प्रतिशत है (सारणी नीचे)। इसके अलावा, आरटीजीएस प्रणाली में लेन-देनों की संख्या और मूल्य कुछ सहभागियों के बीच संकेद्रित है। दस बड़े खिलाड़ी अर्थात एसबीआइ, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक और सिटी बैंक का हिस्सा मार्च 2010 के अंत में लेन-देनों की कुल संख्या और उनकी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक था।

**सारणी: आरटीजीएस और एनईएफटी में लेन-देनों की बैंक समूह-वार संख्या**  
(लेन-देनों की संख्या मिलियन में)

बैंक समूह	आरटीजीएस		एनईएफटी	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
एसबीआइ समूह	3.3	7.4	2.7	6.7
राष्ट्रीयकृत बैंक	3.5	9.0	2.2	7.7
विदेशी बैंक	2.2	5.3	12.4	21.6
निजी क्षेत्र के बैंक	4.2	11.3	14.4	29.3
अन्य	0.1	0.3	0.03	0.2



**टिप्पणी:** अन्य में एनईएफटी के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, आरबीआइ और शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं तथा आरटीजीएस के अंतर्गत इन तीन संस्थाओं के अलावा सेबी नियंत्रित संस्थाएं और डीआइसीजीसी शामिल हैं।



## 9. ग्राहक सेवाएं

4.75 बैंकों को ग्राहक-अनुकूल बनाना रिजर्व बैंक के कार्यों में उच्च प्राथमिकता रखता है। तदनुसार, वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने तथा ग्राहकों से जुड़ी बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के संबंध में कई उपाय किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण का एक फोरम उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्राहक सेवाओं की गति तथा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 2006 में एक संपूर्ण ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की।

4.76 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के 15 कार्यालयों में, जो कि बैंकिंग से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण का एक फोरम है, 2009-10 में 79,266 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से अधिकांश तीन प्रमुख महानगरों-मुंबई, नयी दिल्ली तथा चेन्नै से प्राप्त हुई थीं। 2009-10 में प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग आधी शिकायतें (34,830 शिकायतें जो कुल शिकायतों का 43.9 प्रतिशत है) इन तीन महानगरों की थीं। यह उल्लेखनीय है कि भारत के लगभग सभी कार्यालयों में शिकायतों की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है जो शिकायत निवारण संबंधी उपायों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता को दर्शाती है, परंतु इन तीन महानगरों के कार्यालयों में शिकायतों की संख्या में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.32)।

4.77 विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के हिस्से में हाल के वर्षों में जो वृद्धि हुई थी उसमें 2009-10 में गिरावट आयी है। 2009-10 में, विदेशी बैंकों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल को प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी आयी है। इसके विपरीत, 2009-10 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या में 26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.33)। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या में गिरावट आने से 2009 तथा 2010 के बीच इन बैंक समूहों के विरुद्ध शिकायतों में गिरावट आयी जबकि सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, विशेष रूप से स्टेट बैंक समूह के विरुद्ध शिकायतों के हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट IV.28)। 2009-10 में, स्टेट बैंक

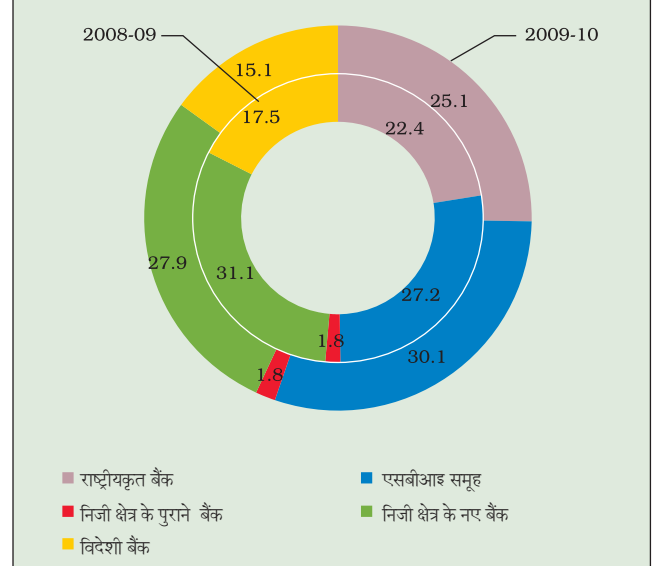
सारणी IV.32: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या	
	2008-09	2009-10
अहमदाबाद	3,732	4,149
बंगलुरु	3,255	3,854
भोपाल	3,375	3,873
भुवनेश्वर	1,159	1,219
चंडीगढ़	2,634	3,234
चेन्नै	10,381	12,727
गुवाहाटी	455	528
हैदराबाद	3,961	5,622
जयपुर	3,688	4,560
कानपुर	7,776	7,832
कोलकाता	3,671	5,326
मुंबई	9,631	10,058
नई दिल्ली	10,473	12,045
पटना	2,110	1,707
तिरु वनंतपुरम	2,816	2,532
<b>कुल</b>	<b>69,117</b>	<b>79,266</b>

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

समूह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त कुल शिकायतों की एक-तिहाई से थोड़ी कम थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रति शाखा शिकायतों की संख्या 0.71 (एसबीआइ समूह के लिए 1.3) थी, जो

चार्ट IV.28: शिकायतों की कुल संख्या में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा



**सारणी IV.33: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली बैंक समूह-वार शिकायतें - 2009-10**

शिकायत की प्रकृति	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीय कृत बैंक	एसबीआइ समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	शहरी सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (9+10)
जमा खाते	1,946	988	958	1,165	68	1,097	454	3,565	116	3,681
प्रेषण	3,358	1,639	1,719	1,873	76	1,797	268	5,499	209	5,708
क्रेडिट/डेबिट एटीएम कार्ड	9,550	3,250	6,300	4,725	126	4,599	4,258	18,533	277	18,810
उधार / अग्रिम	4,109	2,322	1,787	1,652	319	1,333	395	6,156	456	6,612
बिना पूर्व नोटिस के प्रभार	1,939	1,027	912	2,009	130	1,879	729	4,677	87	4,764
पेंशन	4,577	1,294	3,283	67	2	65	65	4,709	122	4,831
प्रतिबद्धताओं संबंधी विफलता	6,407	3,582	2,825	3,369	286	3,083	1,134	10,910	659	11,569
प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	657	351	306	669	59	610	228	1,554	55	1,609
नोट और सिक्के	92	48	44	41	4	37	20	153	5	158
अन्य	7,838	3,747	4,091	6,582	289	6,293	3,808	18,228	612	18,840
विषय के बाहर	1,451	844	607	401	35	366	91	1,943	741	2,684
<b>कुल शिकायतें</b>	<b>41,924</b>	<b>19,092</b>	<b>22,832</b>	<b>22,553</b>	<b>1,394</b>	<b>21,159</b>	<b>11,450</b>	<b>75,927</b>	<b>3,339</b>	<b>79,266</b>
	(26.5)	(27.5)	(25.7)	(2.6)	(18.4)	(1.7)	(-2.1)	(13.6)	(45.6)	(14.7)

**टिप्पणी :** कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

**स्रोत:** बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

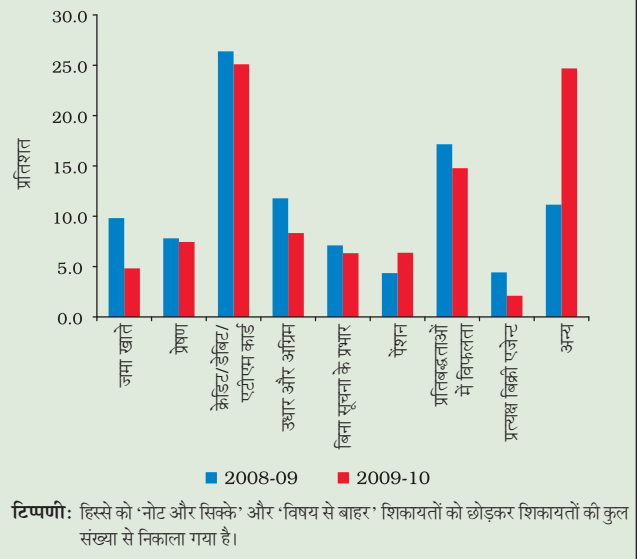
2009-10 में क्रमशः निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के लिए 2.3 तथा 37.8 की तदनुसूची संख्या से काफी कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

4.78 यद्यपि, बैंकिंग लोकपाल को प्राप्त होने वाली शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्डों से संबंधित हुआ करती थीं लेकिन 2009-10 में ऐसी शिकायतों की संख्या में गिरावट आयी। इसी प्रकार, बैंकों के कोर बैंकिंग कारोबार विशेष रूप से जमाराशि तथा उधार से संबंधित शिकायतों में वर्ष के दौरान गिरावट आयी (चार्ट IV.29)। 2009-10 में कार्ड संबंधी शिकायतों में आयी गिरावट को विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों के विरुद्ध शिकायतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इन बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में कार्ड संबंधी शिकायतें अधिक होती थीं।

## 10. वित्तीय समावेशन

4.79 समावेशी वृद्धि संबंधी चिंताओं को प्रभावी रूप से दूर करने में वित्तीय समावेशन की भूमिका को देखते हुए रिजर्व

**चार्ट IV.29: प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत हिस्सा**



बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को एक मिशन के रूप में लिया है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में वित्तीय विस्तार तथा वित्तीय सघनता के कम स्तर को देखते हुए वित्तीय समावेशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व बैंक के हाल

के आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय विस्तार के क्षेत्र में ओईसीडी के देशों की तुलना में भारत का स्थान नीचे है (सारणी IV.34)। एशिया के चुनिंदा समकक्ष देश समूहों की तुलना में बैंक शाखाओं तक पहुंच की दृष्टि से यह अंतर उतना नहीं है, परंतु एटीएम तक पहुंच की दृष्टि से यह अंतर काफी है। इसके अलावा, जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज अनुपात के अनुसार तुलना करने पर भारत के बैंकिंग क्षेत्र का आकार तथा विस्तार भी एशिया के अन्य समकक्ष देशों की तुलना में काफी कम है<sup>18</sup>। ये प्रवृत्तियां आने वाले वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत को रेखांकित करती हैं।

4.80 भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन को किफायती वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों अर्थात् औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक भुगतान तथा प्रेषण सुविधाओं, बचतों, उधार तथा बीमा सेवाओं तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। 2000 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारतीय नीतिगत दृष्टिकोण का फोकस व्यक्ति तथा परिवार के स्तर पर समावेशन सुनिश्चित करना रहा है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी एक नो-फ्रिल खाता योजना (पूर्वशर्त रहित, न्यूनतम शेषराशि का कम स्तर) की शुरुआत की जो जन-साधारण को सरल वित्तीय बचत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनके प्रवेश का माध्यम बन सकती है। मार्च 2010 के अंत में बैंकिंग प्रणाली द्वारा 5.06 करोड़ नो-फ्रिल खाते खोले गए। जहां नो-फ्रिल खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई वहीं बैंकिंग प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी सामने आयी कि इन खातों को किस प्रकार परिचालनरत रखा जाए क्योंकि गरीब लोगों द्वारा बचत न कर पाने एवं इन खातों में राशि जमा न कर पाने के कारण काफी ऐसे खाते अपरिचालित रूप में पाए गए। इन खातों को परिचालनरत रखने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे खातों पर छोटी राशि का ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराएं; मार्च 2010 तक बैंकों द्वारा 27.54 करोड़ रुपए की राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

**सारणी IV.34: वित्तीय पहुंच और गहनता के संकेतक, भारत की एशिया के चुनिंदा समकक्ष समूह देशों और ओईसीडी देशों के साथ तुलना**

देश / समूह	वित्तीय पहुंच		वित्तीय बाजार आकार और गहनता
	प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर शाखाओं की संख्या	प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर एटीएम की संख्या	
भारत	6.33 <sup>^^</sup>	1.63 <sup>^^</sup>	33.30 <sup>^^</sup>
<b>एशियाई समकक्ष समूह देश (दायरा)<sup>#</sup></b>	<b>1.33-20</b>	<b>3.80-17.05</b>	<b>23.00-126.60</b>
<i>जिसमें से,</i>			
चीन	1.33 <sup>^</sup>	3.80 <sup>^</sup>	111.80
इंडोनेशिया	3.73	4.84 <sup>@</sup>	23.00
मलेशिया	8.26	16.44 <sup>^</sup>	126.60
थाईलैंड	7.37	17.05 <sup>**</sup>	90.50
<b>ओईसीडी देश (दायरा)<sup>#</sup></b>	<b>23-45</b>	<b>57-158</b>	<b>47.80-160.48</b>
<i>जिसमें से,</i>			
ऑस्ट्रेलिया	24	115	109.73
कनाडा	28	158	75.65
जापान	45	136	97.90
ब्रिटेन	23	97	160.48
अमरीका	26	134	47.84

टिप्पणी : 1) डाटा 2005 से संबंधित है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

2) \* : इस संकेतक को क्विंटिल सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009) द्वारा बाजार संकेतक को मापने के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि, पारंपरिक रूप से, जीडीपी की तुलना में निजी ऋण वित्तीय बाजारों के आकार और गहराई को दर्शाता है; देखें 'मीजरिंग बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट', नोट 1, विश्व बैंक। जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र पर बैंकिंग क्षेत्र के दावों के रूप में परिभाषित किया गया है।

3) ^ : 2003 डेटा

4) @ : 2000 डेटा

5) \*\* : 2004 डेटा

6) # : क्विंटिल सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009) द्वारा विश्व बैंक अध्ययन में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत उच्चतम और न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार एशियन पियर ग्रुप और ओईसीडी देश को दायरा दिया गया है। केवल चयनित देशों से संबंधित आंकड़े उपर्युक्त सारणी में अलग से दर्शाए गए हैं।

7) ^^ : भारत के लिए प्रति 1,00,000 व्यक्तियों के लिए शाखाओं और एटीएम की संख्या वर्षों के दौरान बढ़ी है; संबंधित संख्या 2010 में 7.13 और 5.07 थी। इसके अलावा, भारत के लिए जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज का अनुपात भी बढ़ा और वह मार्च 2010 के अंत में 56.1 प्रतिशत रहा।

स्रोत: क्विंटिल सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009), *गैटिंग फाइनेंस इन साउथ एशिया 2009-इंडिकेटर्स एंड एनेलिसिस ऑफ दि कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर*, विश्व बैंक।

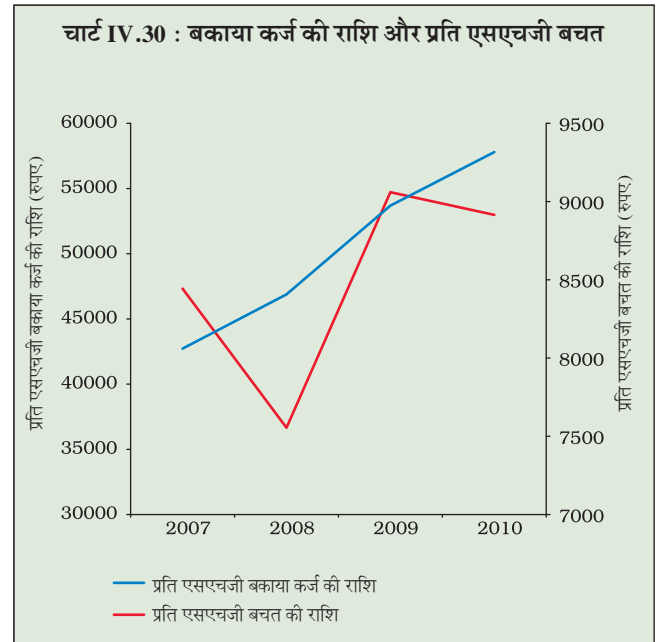
<sup>18</sup> क्विंटिल सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009), *गैटिंग फाइनेंस इन साउथ एशिया 2009 - इंडिकेटर्स एंड एनेलिसिस ऑफ दि कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर*, विश्व बैंक।

4.81 सूक्ष्म वित्त भारत में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। सूक्ष्म वित्त को ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बचत, कर्ज तथा कम राशि की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराने के एक ऐसे माध्यम के रूप में किया गया है जो उन्हें अपनी आय एवं जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम (एसबीएलपी) ने, जिसे 1992 में एक प्रयोगिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, वर्षों के दौरान काफी प्रगति की है। 2009-10 में 1.59 मिलियन नए स्वयं सहायता समूहों को बैंक कर्ज से जोड़ा गया तथा इन्हें 14,453 करोड़ रुपए का कर्ज (पुनर्बार दिए गए कर्ज सहित) दिया गया। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत में 6.95 मिलियन स्वयं सहायता समूहों के पास बैंकों में बचत बैंक खाते थे (सारणी IV.35)। 2009-10 में औसतन प्रति स्वयं सहायता समूह की बचत राशि 8,915 रुपए थी जबकि उनके कर्ज की राशि 57,795 रुपए थी। हाल के वर्षों में जहां प्रति स्वयं सहायता समूह की बकाया कर्ज की राशि में लगातार वृद्धि हुई वहीं प्रति स्वयं सहायता समूह की जमा राशि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही (सारणी IV.30)।

#### सारणी IV.35: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति (मार्च को समाप्त)

मद	स्वयं-सहायता समूह			
	संख्या (मिलियन में)		राशि (करोड़ रुपए)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.61	1.59	12,254	14,453
बैंकों के पास बकाया उधार	(0.26)	(0.27)	(2,015)	(2,198)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.22	4.85	22,680	28,038
बैंकों के पास बचतें	(0.98)	(1.25)	(5,862)	(6,251)
बैंकों के पास बचतें	6.12	6.95	5,546	6,199
	(1.51)	(1.69)	(1,563)	(1,293)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं			
	संख्या		राशि करोड़ (रुपए)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	581	691	3,732	8,063
बैंकों के पास बकाया उधार	1,915	1,513	5,009	10,148
बैंकों के पास बचतें	-	-	-	-

**टिप्पणी:** 1) कोष्ठक के आंकड़े स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज्जगार योजना (एसजीएसवाय) के अंतर्गत आनेवाले एसएचजी संबंधी ब्योरे दर्शाते हैं।  
2) \* : बैंक ऋण लेने वाली सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की वास्तविक संख्या एक से अधिक बैंकों से ऋण का लाभ उठानेवाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कारण कम होगी।  
**स्रोत:** नाबार्ड।



4.82 एसबीएलपी के साथ-साथ, अन्यो के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), एनबीएफसी जैसी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआइ) भारत में सूक्ष्म वित्त के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में उभरकर आईं। 2009-10 में बैंकों ने 691 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कर्ज दिए जिसकी राशि 8,063 करोड़ रुपए थी। 2009-10 में एमएफआइ-संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हुई वृद्धि संख्या तथा राशि दोनों की दृष्टि से एसएचजी-बैंक संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हुई तदनुसूची वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

## 11. बैंकिंग सेवाओं का स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण

4.83 बैंकिंग के स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं इन सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी मिलती है जो वित्तीय विस्तार और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस खण्ड में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों एवं राज्यों/क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के वितरण की जानकारी दी गयी है। इसके अलावा, इसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एटीएम वितरण के बारे में भी जानकारी दी गयी है जो बैंकिंग सेवाओं का एक अन्य माध्यम है। अन्त में, इसमें भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन और विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन के बारे में चर्चा की गयी है।

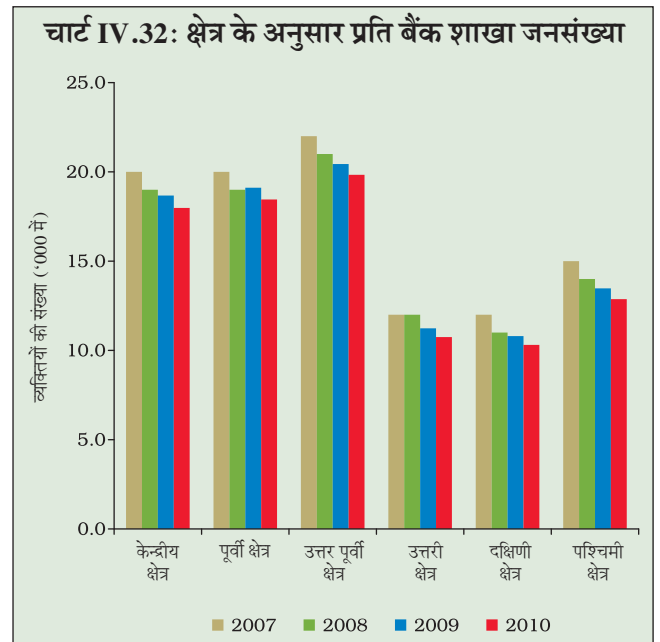
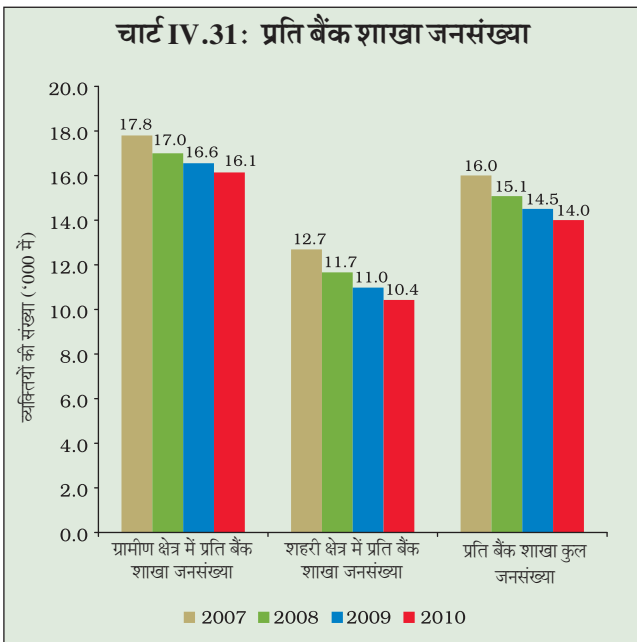
### बैंक शाखाओं का वितरण

4.84 प्रति बैंक शाखा के पीछे औसत जनसंख्या का आंकड़ा बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का एक सामान्य संकेतक होता है। इस संकेतक के आधार पर हाल के वर्षों में भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार निरंतर आधार पर हुआ है (चार्ट IV.31)। तथापि, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दर काफी कम रही है।<sup>19</sup> यह बात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा के पीछे औसत जनसंख्या की दर में हुई गिरावट की तुलना से स्पष्ट होती है।

4.85 क्षेत्रीय स्तर पर, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के स्तर में उल्लेखनीय अंतर था। एक तरफ, मार्च 2010 के अंत में जहां उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या 10,000 से 14,000 के बीच थी। वहीं मध्य, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का स्तर काफी उच्चतर अर्थात् 18,000 से 19,000 के दायरे में था। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में प्रति बैंक शाखा के पीछे जनसंख्या के आंकड़ों में गिरावट

हुई है जो सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते विस्तार को दर्शाता है (चार्ट IV.32)<sup>20</sup>।

4.86 दिसम्बर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाया गया जिसके जरिए रिपोर्टिंग के अधीन प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना देशी अनुसूचित वाणिज्य देशी बैंकों को टियर 3 से 6 के केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र) में शाखाएं खोलने की छूट दी गयी। टियर 3 से 6 तक के केंद्रों में जुलाई 2009 तथा जून 2010 के बीच खोली गयी नयी बैंक शाखाओं की संख्या की पिछले वर्ष की संख्या के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस नीतिगत परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। 2009-10 के दौरान टियर 3 से 6 तक के केंद्रों में 1,513 बैंक शाखाएं खोली गयीं जो 2008-09 में खोली गयी 1,481 बैंक शाखाओं से अधिक है जो नयी बैंक शाखाओं में हुई 2.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (सारणी IV.36)।



<sup>19</sup> यहां 'ग्रामीण' क्षेत्र से तात्पर्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों से है जबकि 'शहरी और महानगरीय केन्द्र' दोनों से है।

<sup>20</sup> राज्य स्तरीय आंकड़ों के लिए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी देखें।

**सारणी IV.36: टियर 3-6 केन्द्रों में खोली गई नई शाखाओं की संख्या**

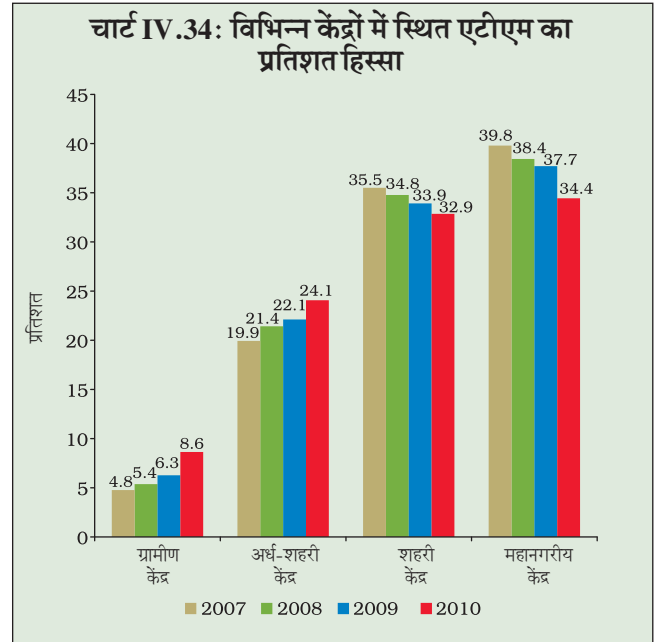
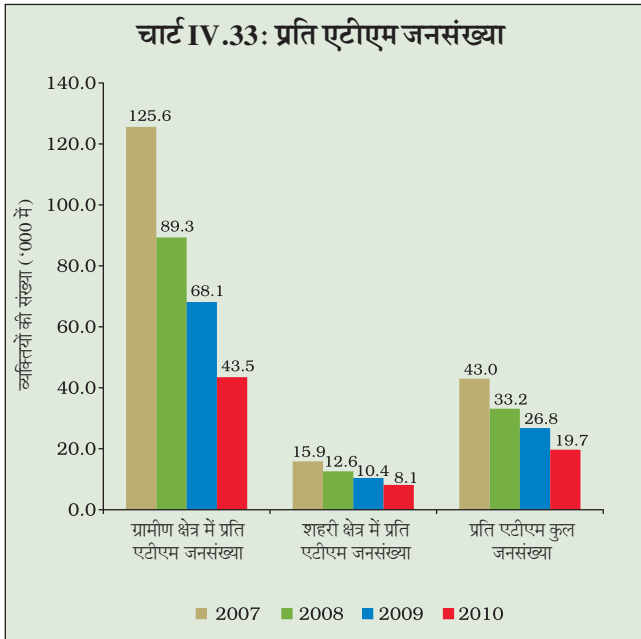
मद	2008-09	2009-10अ
टियर 3-6 केन्द्रों में खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या	1,481	1,513
	(-)	(2.2)

**टिप्पणी:** 1) कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।  
2) डाटा प्रत्येक वर्ष के लिए जुलाई-जून से संबंधित है।  
3) अ - अनंतिम।

**स्रोत:** बैंकों की मास्टर ऑफिस फ़ाइल।

**एटीएम का वितरण**

4.87 बैंक शाखाओं की तरह हाल की वर्षों में एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई जो कि प्रति एटीएम के पीछे जनसंख्या के आंकड़ों में हुई गिरावट से स्पष्ट है (चार्ट IV.33)। जहां ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में एटीएम की सघनता अधिक है वहीं हाल की वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है (सारणी IV.34; सारणी IV.37)।<sup>21</sup> मार्च 2009 के अंत में देश के एटीएम की कुल संख्या का 28.4 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में था जो मार्च 2010 के अंत में बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.34)।



ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या में हुई वृद्धि में एक प्रमुख हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की बढ़ती संख्या को एक एटीएम के पीछे जनसंख्या के आंकड़े में आयी निरंतर गिरावट से भी देखा जा सकता है (चार्ट IV.33)।

**सारणी IV.37: विभिन्न केन्द्रों में स्थित एटीएम की संख्या**

बैंक समूह	(मार्च 2010 के अंत में)				
	ग्रामीण केन्द्र	अर्ध-शहरी केन्द्र	शहरी केन्द्र	महा-नगरीय केन्द्र	सभी केन्द्र
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>4,289</b>	<b>10,968</b>	<b>13,451</b>	<b>11,972</b>	<b>40,680</b>
	(10.5)	(27.0)	(33.1)	(29.4)	(100.0)
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,669	4,325	6,726	6,982	19,702
	(8.5)	(22.0)	(34.1)	(35.4)	(100.0)
स्टेट बैंक समूह	2,620	6,643	6,725	4,990	20,978
	(12.5)	(31.7)	(32.1)	(23.8)	(100.0)
<b>निजी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>901</b>	<b>3,499</b>	<b>6,124</b>	<b>7,923</b>	<b>18,447</b>
	(4.9)	(19.0)	(33.2)	(43.0)	(100.0)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	265	1,019	1,215	891	3,390
	(7.8)	(30.1)	(35.8)	(26.3)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	636	2,480	4,909	7,032	15,057
	(4.2)	(16.5)	(32.6)	(46.7)	(100.0)
<b>विदेशी बैंक</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>188</b>	<b>821</b>	<b>1,026</b>
	(0.6)	(1.1)	(18.3)	(80.0)	(100.0)
<b>कुल</b>	<b>5,196</b>	<b>14,478</b>	<b>19,763</b>	<b>20,716</b>	<b>60,153</b>
	(8.6)	(24.1)	(32.9)	(34.4)	(100.0)

**टिप्पणी:** कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

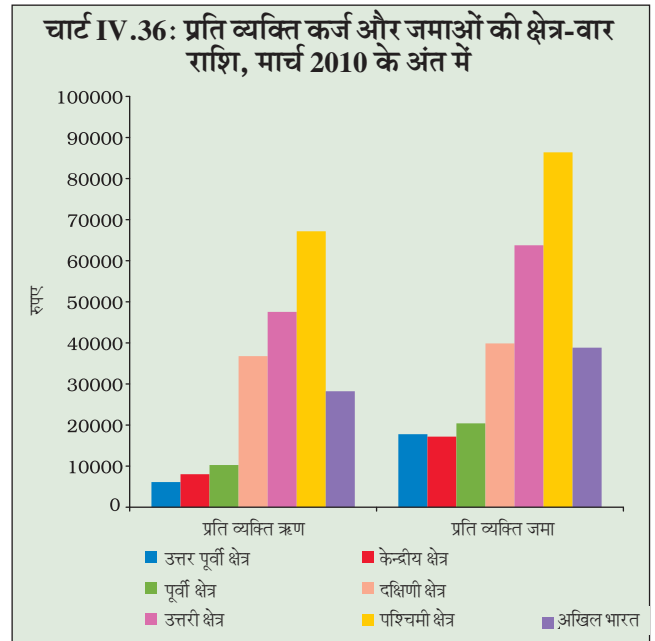
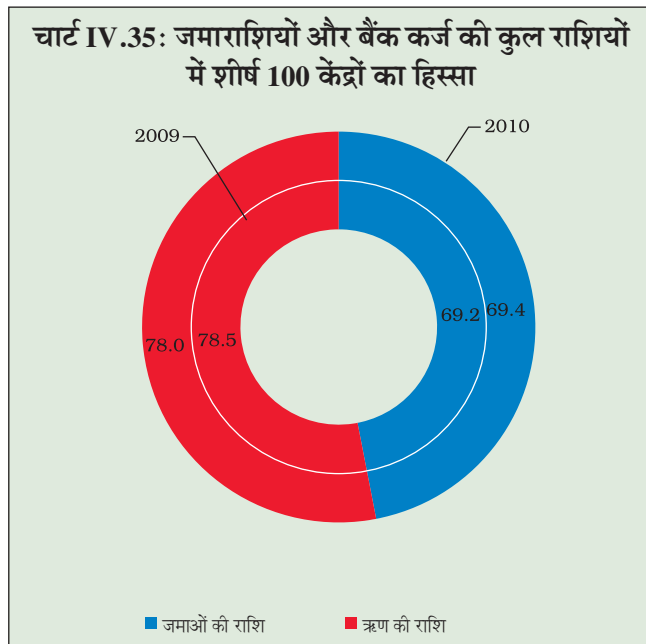
<sup>21</sup> यहां ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य ग्रामीण और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्रों से है जबकि शहरी क्षेत्रसे तात्पर्य शहरी और महानगरीय केन्द्र दोनों से है।



### बैंक कर्ज तथा जमाराशियों का वितरण

4.88 बैंक कर्ज का स्थानिक वितरण शीर्ष के 100 केंद्रों में कर्ज के भारी संकेंद्रण को दर्शाता है। मार्च 2010 के अंत में, शीर्ष के 100 केंद्रों में भारत में कुल बैंक कर्ज का 78.0 प्रतिशत संकेंद्रित था जो मार्च 2009 के अंत के प्रतिशत से मामूली कम है (सारणी IV.35)। तथापि, शीर्ष के 100 केंद्रों के पास मार्च 2010 के अंत में जुटाई गयी कुल जमाराशि का 69.4 प्रतिशत जमाराशि थी<sup>22</sup>।

4.89 क्षेत्रीय स्तर पर भी बैंक कर्ज देश के पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में संकेंद्रित था (चार्ट IV.36)। मार्च 2010 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की तुलना में लगभग 11 गुने तथा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में लगभग छह से आठ गुने अधिक थी। प्रति व्यक्ति जमाराशि के मामले में यह अंतर कम था; पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जमाराशि उत्तर-पूर्वी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में लगभग चार से पांच गुने अधिक थी। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत में दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में कर्ज-जमा अनुपात पूर्वी, मध्य तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.13)।



### विदेशी बैंकों का भारत में परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

4.90 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा उनकी शाखाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। जून 2009 के अंत के 32 बैंक की तुलना में भारत में सितम्बर 2010 के अंत में 34 विदेशी बैंक (24 देशों के) कार्यरत थे। शाखाओं की कुल संख्या भी 2009 के 293 से बढ़कर 2010 में 315 हो गयी। इसके अलावा, 2010 में 45 विदेशी बैंकों ने प्रतिनिधि कार्यालय के जरिए भारत में परिचालन किया जबकि 2009 में यह संख्या 43 थी। विदेशी बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास बैंक शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिसके बाद एचएसबीसी लिमिटेड, सिटीबैंक तथा रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. का स्थान था।

4.91 जुलाई 2009 और सितंबर 2010 के बीच चार विद्यमान विदेशी बैंकों को सात बैंक शाखाएं तथा तीन नए विदेशी बैंक अर्थात् स्वेरबैंक (रूस), एएनजेड बैंक (आस्ट्रेलिया) तथा क्रेडिट स्विस् एजी (स्विटजरलैंड) प्रत्येक को भारत में एक-एक बैंक

<sup>22</sup> राज्य स्तरीय विस्तृत आंकड़ों के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि और कर्ज संबंधी तिमाही सांख्यिकी देखें।

खोलने की अनुमति दी गई। भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए दो विदेशी बैंकों अर्थात् सीआरएमबी बैंक (मलेशिया) और एलए कैसिया (स्पेन) प्रत्येक को भी अनुमति दी गई।

4.92 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी उपस्थिति में विस्तार करना जारी रखा। जुलाई 2009 तथा सितम्बर 2010 के बीच भारतीय बैंकों ने सात शाखाएं, एक अनुषंगी कार्यालय तथा पांच प्रतिनिधि कार्यालय खोले। सितम्बर 2010 के अंत में 22 भारतीय बैंकों ने (सरकारी क्षेत्र के 16 तथा निजी क्षेत्र के 6 बैंक) 233 विदेशी कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से परिचालन किए (सारणी IV.38)। बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं थीं, वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने 2009-10 के दौरान चार नयी बैंक शाखाएं

खोलकर अपने शाखा नेटवर्क में विस्तार करके विदेशी बैंकिंग प्रणाली में अपनी उपस्थिति में निरंतर वृद्धि की।

4.93 भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की तुलना में सामान्यतः अधिक रही क्योंकि हाल के वर्षों में पूर्व में वृद्धि बाद वाले की तुलना में अधिक रही है (चार्ट IV.37)।

## 12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.94 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का गठन सहकारी तथा वाणिज्य बैंकों की अच्छी विशेषताओं को जोड़कर एक ऐसी क्षेत्रीय दृष्टिकोण वाली संस्था के रूप में किया गया था जो ग्रामीण

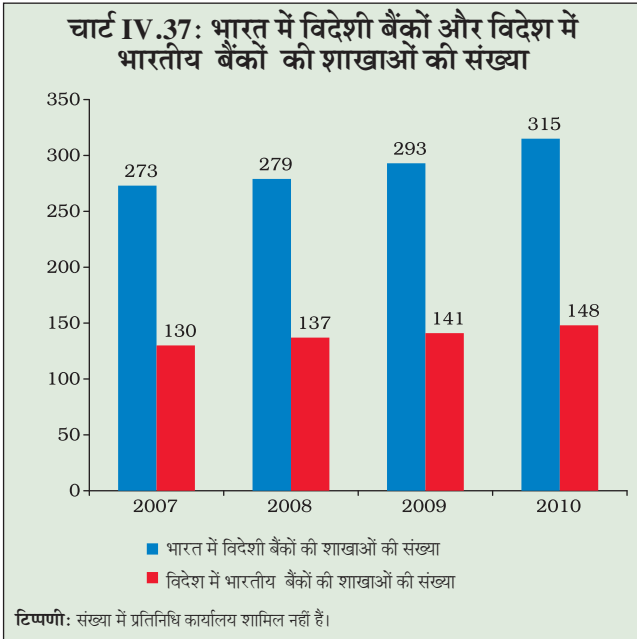
सारणी IV.38: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(वास्तविक रूप से परिचालन)

क्रम सं. बैंक का नाम	शाखा		सहायक बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>I. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक</b>	<b>130</b>	<b>137</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>189</b>	<b>203</b>
1 इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
2 आंध्र बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	46	46	8	9	3	3	1	1	58	59
4 बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	3	5	5	1	1	33	33
5 केनरा बैंक	3	4	-	-	-	1	-	-	3	5
6 कॉर्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
7 इंडियन बैंक	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
8 इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	3	4	-	-	10	11
9 आइडीबीआई बैंक लिमिटेड	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10 पंजाब नेशनल बैंक	3	4	1	2	4	4	1	1	9	11
11 भारतीय स्टेट बैंक	38	42	5	5	8	8	4	4	55	59
12 सिंडिकेट बैंक	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
13 यूको बैंक	4	4	-	-	2	2	-	-	6	6
14 यूनियन बैंक	1	1	-	-	3	5	-	-	4	6
15 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
16 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
<b>II. निजी क्षेत्र के नए बैंक</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
17 ऐक्सिस बैंक	3	3	-	-	2	2	-	-	5	5
18 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1	1	-	-	2	2	-	-	3	3
19 आइसीआईएल बैंक लिमिटेड	7	7	3	3	8	8	-	-	18	18
20 इंडसइंड बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
21 फेडरल बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
22 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
<b>कुल</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>219</b>	<b>233</b>

टिप्पणी: 1) - शून्य

2) डाटा सितंबर समाप्ति से संबंधित है।



जन के उपेक्षित लोगों तक कर्ज सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। इस प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श संस्था के रूप में देखा जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र सुधारों को लागू करने के बाद इन संस्थाओं को परिचालनगत स्वतंत्रता देने तथा उनकी कमजोर होती वित्तीय हालत में सुधार करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित नीतिगत ढांचे में कई परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन मुख्यतः इन संस्थाओं पर विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को लागू करने के साथ-साथ इनके पुनर्गठन तथा समामेलन, इनके पुनःपूँजीकरण के रूप में दिखायी दिए।

4.95 2009-10 में, आरआरबी के समेकित तुलनपत्र में पिछले वर्ष के 16.5 प्रतिशत की तुलना में 22.2 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दिखी। देयता पक्ष में, जमाओं ने आरआरबी के तुलनपत्र में वृद्धि को आगे बढ़ाया जबकि आस्ति पक्ष में, वृद्धि मुख्य रूप से निवेश के कारण थी। यह उल्लेखनीय है कि 2009-10 में आरआरबी का कर्ज जमा अनुपात 57.6 प्रतिशत था जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम था।

4.96 82 आरआरबी में से, 79 आरआरबी 2009-10 में लाभ में थे, यह लाभ पिछले वर्ष के 93.0 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष के दौरान बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गया जो लाभ कमाने वाले आरआरबी के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है। कुल मिलाकर,

सभी आरआरबी ने एक साथ 1,884 करोड़ रुपए का निवल लाभ सूचित किया जो 2009-10 में 41.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। परिणाम के रूप में, आरआरबी के आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में 2008-09 के 1.0 प्रतिशत से 2009-10 में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (सारणी IV.40)। इस प्रकार, 2009-10 में आरआरबी का आरओए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में सापेक्षिक रूप से अधिक था।

4.97 वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने की उनकी भूमिका के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जो सामान्यतया आरआरबी के कुल अग्रियों का एक बड़ा हिस्सा होता है, का 2009-10 में उनके कुल अग्रियों का लगभग 82 प्रतिशत का हिस्सा था। मार्च 2010 के अंत में उनके कुल कर्ज में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 82

#### सारणी IV.39: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2009	2010अ	
<b>शेयर पूंजी</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	-
<b>आरक्षित निधियां</b>	<b>6,754</b>	<b>8,065</b>	<b>19.4</b>
<b>शेयर पूंजी जमा</b>	<b>3,959</b>	<b>3,985</b>	<b>0.7</b>
<b>जमाराशियां</b>	<b>1,20,189</b>	<b>1,45,035</b>	<b>20.7</b>
चालू	6,432	8,065	25.4
बचत	63,675	75,906	19.2
अवधि	50,082	61,064	21.9
<b>से उधार</b>	<b>12,735</b>	<b>18,770</b>	<b>47.4</b>
नाबार्ड	8,690	12,521	44.1
प्रायोजक बैंक	3,931	6,165	56.8
अन्य	114	84	-26.3
<b>अन्य देयताएं</b>	<b>6,820</b>	<b>8,041</b>	<b>17.9</b>
<b>कुल देनदारियां / आस्तियां</b>	<b>1,50,654</b>	<b>1,84,093</b>	<b>22.2</b>
<b>नकदी</b>	<b>1,587</b>	<b>1,784</b>	<b>12.4</b>
<b>आरबीआइ के पास शेष</b>	<b>5,882</b>	<b>8,145</b>	<b>38.5</b>
<b>अन्य बैंक शेष</b>	<b>31,865</b>	<b>39,102</b>	<b>22.7</b>
<b>निवेश</b>	<b>37,984</b>	<b>47,289</b>	<b>24.5</b>
<b>ऋण और अग्रिम (निवल)</b>	<b>65,609</b>	<b>79,157</b>	<b>20.6</b>
<b>अचल आस्तियां</b>	<b>278</b>	<b>379</b>	<b>36.3</b>
<b>अन्य आस्तियां#</b>	<b>7,449</b>	<b>8,237</b>	<b>10.6</b>
ऋण -जमा अनुपात	54.6	54.6	-
निवेश -जमा अनुपात	58.1	59.5	-
(ऋण + निवेश)			
जमा अनुपात	112.7	114.1	-
<b>टिप्पणी:</b> 1) अ : अर्न्तम । 2) # : इसमें संचित घाटा शामिल है।			
<b>स्रोत:</b> नाबार्ड			

**सारणी IV.40 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09 (86)	2009-10अ (82)	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
<b>क.</b>	<b>आय (i+ii)</b>	<b>11,388</b>	<b>13,835</b>	<b>21.5</b>
i	ब्याज आय	10,579	12,945	22.4
ii	अन्य आय	810	890	9.9
<b>ख.</b>	<b>खर्च (i+ii+iii)</b>	<b>10,053</b>	<b>11,951</b>	<b>18.9</b>
i	खर्च किया गया ब्याज	6,100	7,375	20.9
ii	परिचालन व्यय जिसमें से: वेतन बिल	3,165 2,291	3,547 2,676	12.1 16.8
iii	प्रावधान और आकस्मिक व्यय	788	1,029	30.6
<b>ग.</b>	<b>लाभ</b>			
i	परिचालन लाभ	2,123	2,913	37.2
ii	निवल लाभ	1,335	1,884	-41.1
<b>ङ.</b>	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>1,50,654</b>	<b>1,84,093</b>	<b>22.2</b>
<b>च.</b>	<b>वित्तीय अनुपात #</b>			
i	परिचालन लाभ	1.5	1.7	-
ii	निवल लाभ	1.0	1.1	-
iii	आय (क+ख)	8.3	8.3	-
	(क) ब्याज आय	7.7	7.7	-
	(ख) अन्य आय	0.6	0.5	-
iv	व्यय (क+ख+ग)	7.3	7.1	-
	(क) खर्च किया गया ब्याज	4.4	4.4	-
	(ख) परिचालन व्यय जिसमें से: वेतन बिल	2.3 1.7	2.1 1.6	-
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.6	-
<b>टिप्पणी:</b> 1. अ: अनंतिम 2. वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों से संबंधित है। 3. कोष्ठक के आंकड़े आरआरबी की कुल संख्या दर्शाते हैं।				
<b>स्रोत:</b> नाबार्ड।				

प्रतिशत था (सारणी IV.41)। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए कर्ज के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी।

### 13. स्थानीय क्षेत्र बैंक

4.98 स्थानीय क्षेत्र बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना की शुरुआत 1996 में की गयी थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषीकृत स्थानीय फोकस के साथ दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थन हेतु कर्ज उपलब्धता की खाई को पाटना तथा

**सारणी IV.41 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कर्ज का प्रयोजन-वार वितरण**

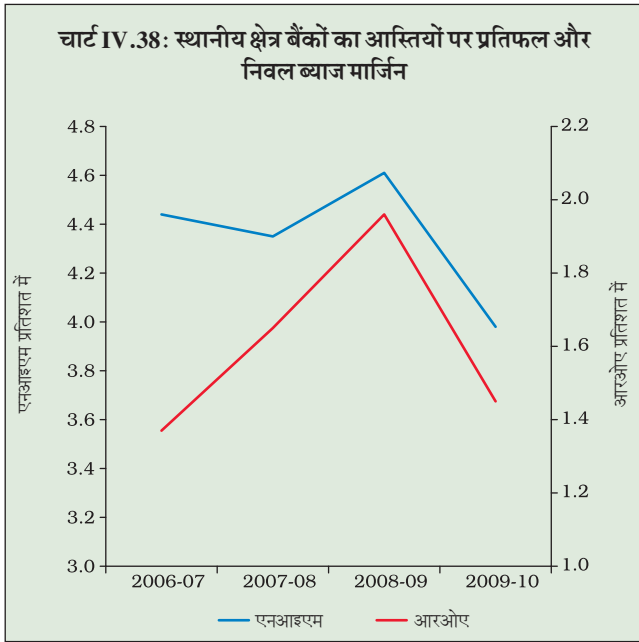
(राशि करोड़ रुपये में)

प्रयोजन	मार्च को समाप्त		
	2009	2010अ	
<b>I. कृषि (i से ii)</b>	<b>37,367</b>	<b>45,829</b>	
	(55.1)	(54.8)	
i	अल्पकालिक कर्ज (फसल कर्ज)	26,652	33,208
ii	मीयादी कर्ज (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	10,715	12,621
<b>II. कृषि से इतर (i से iv)</b>	<b>30,435</b>	<b>37,733</b>	
	(44.8)	(45.1)	
i	ग्रामीण कारीगर	772	857
ii	अन्य उद्योग	1,656	1,694
iii	खुदरा व्यापार	4,690	5,285
iv	अन्य प्रयोजन	23,317	29,897
<b>कुल (I+II)</b>	<b>67,802</b>	<b>83,562</b>	
<b>ज्ञापन म दें:</b>			
(क)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	56,555	68,660
(ख)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	11,247	14,902
(ग)	कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत शेयर	83.4	82.2
<b>टिप्पणी:</b> 1) अ: अनंतिम 2) कोष्ठक के आंकड़े कुल ऋण में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।			
<b>स्रोत:</b> नाबार्ड।			

संस्थागत कर्ज ढांचे को बढ़ाना था। यद्यपि, छह स्थानीय क्षेत्र बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, परंतु इस समय केवल चार स्थानीय क्षेत्र बैंक कार्यरत हैं। इस खण्ड में 2009-10 के दौरान स्थानीय क्षेत्र बैंकों के निष्पादन तथा इन संस्थाओं के परिचालन संबंधी प्रमुख मुद्दों की चर्चा की गयी है।

4.99 आरओए तथा एनआइएम द्वारा समग्र स्तर पर मापी जानेवाली स्थानीय क्षेत्र बैंकों की दक्षता एवं लाभप्रदता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में काफी ऊंची रही है (चार्ट IV.38)। 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तरह इनके आरओए तथा एनआइएम में गिरावट हुई जो इस वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान कम ब्याज दर के वातावरण को परिलक्षित करती है (सारणी IV.42)।

4.100 उच्च दक्षता के बावजूद, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के परिचालन के संबंध में चिंता के कई मुद्दे थे। पहला, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के बैंक-स्तरीय आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि एक स्थानीय क्षेत्र बैंक नामतः कैपिटल लोकल एरिया बैंक में मार्च 2010 के अंत में कारोबार का उल्लेखनीय संकेन्द्रण था, जिसके पास स्थानीय क्षेत्र बैंकों की कुल आस्तियों का 68.8 प्रतिशत समग्र बैंकिंग



कारोबार का 69.1 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी IV.43)। दूसरा, जैसा कि स्थानीय क्षेत्र बैंकों के कार्यकलापों की समीक्षा करने वाले 2002 के समूह द्वारा उल्लेख किया गया है, इन संस्थाओं का पूंजी आधार सीमित था, अतः ये अप्रत्याशित हानियों को सहन कर पाने की स्थिति में नहीं थे। अतः, समूह ने उनकी 25 करोड़ रुपए निवल मालियत में वृद्धि करने की सिफारिश की थी। तथापि, कैपिटल लोकल एरिया बैंक को छोड़कर अन्य स्थानीय क्षेत्र बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मार्च 2010 के अंत में जहां कैपिटल लोकल एरिया बैंक की निवल मालियत 45.9

**सारणी IV.42: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए)

ब्यौरे	2008-09	2009-10	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
<b>क आय (i+ii)</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	14.3
i) ब्याज आय	75	86	14.3
ii) अन्य आय	16	18	14.2
<b>ख व्यय (i+ii+iii)</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	19.1
i) खर्च किया गया ब्याज	42	51	22.8
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8	8	1.1
iii) परिचालन व्यय	27	32	18.6
जिसमें से: वेतन बिल	12	14	14.9
<b>ग लाभ</b>			
i) परिचालन लाभ/हानि	<b>22</b>	<b>20</b>	-7.1
ii) निवल लाभ/हानि	<b>14</b>	<b>13</b>	-11.5
<b>घ अंतर (निवल ब्याज आय)</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>3.7</b>
<b>ङ कुल आस्तियां</b>	<b>787</b>	<b>946</b>	<b>20.2</b>
<b>च वित्तीय अनुपात</b>			
i) परिचालन लागत	3.0	2.4	-
ii) निवल लाभ	2.0	1.4	-
iii) आय	12.6	12.0	-
iv) ब्याज आय	10.4	9.9	-
v) अन्य आय	2.2	2.1	-
vi) व्यय	10.6	10.5	-
vii) खर्च किया गया ब्याज	5.8	5.9	-
viii) परिचालन व्यय	3.8	3.7	-
ix) वेतन बिल	1.7	1.6	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.1	0.9	-
xi) अंतर (निवल ब्याज आय)	4.6	4.0	-

**टिप्पणी:** 'च' के अंतर्गत सभी अनुपात कुल औसत आस्तियों से संबंधित हैं।

**स्रोत:** ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (घरेलू)।

करोड़ रुपए थी वहीं कोस्टल लोकल एरिया बैंक की निवल मालियत 18.7 करोड़ रुपए थी तथा उसके बाद सुभद्रा लोकल एरिया बैंक

**सारणी IV.43: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफाइल**

(मार्च को समाप्त)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक	आस्ति		जमाराशि		सफल अग्रिम	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	549 (69.8)	651 (68.8)	461 (74.8)	532 (72.2)	296 (67.4)	347 (65.0)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	100 (12.7)	127 (13.4)	73 (11.9)	101 (13.7)	57 (13.0)	84 (15.7)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	99 (12.6)	120 (12.7)	56 (9.1)	75 (10.2)	64 (14.6)	78 (14.6)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	39 (5.0)	48 (5.1)	27 (4.4)	29 (3.9)	23 (5.2)	25 (4.7)
<b>सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक</b>	<b>787</b> <b>(100.0)</b>	<b>946</b> <b>(100.0)</b>	<b>616</b> <b>(100.0)</b>	<b>737</b> <b>(100.0)</b>	<b>439</b> <b>(100.0)</b>	<b>534</b> <b>(100.0)</b>

**टिप्पणी:** कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

**स्रोत:** परोक्ष विवरणियों पर आधारित (देशी)।

(17.4 करोड़ रुपए) तथा कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक (12.9 करोड़ रुपए) का क्रम था।

## 14. निष्कर्ष

4.101 2009-10 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलन-पत्र की वृद्धि में गिरावट के संकेत दिखने लगे जो वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत होने के वर्ष 2008-09 के दौरान जमाराशियों तथा बैंक कर्ज की वृद्धि दर में गिरावट आने की वजह से थी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक कर्ज की वृद्धि दर में गिरावट आई जो संकट के बाद की आर्थिक गिरावट को दर्शाती है। तथापि, अंतर-वर्षीय आधार पर नवंबर 2009 से बैंक कर्ज में बेहतरी के संकेत दिखने लगे क्योंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गतिशीलता में तेजी आने लगी थी।

4.102 2009-10 में बैंक जमाराशियों से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक सीएएसए के प्रतिशत में वृद्धि होना है। जहां तक निवेश का संबंध है, 2009-10 में गैर एसएलआर निवेशों में बेहतरी आई जिसमें वित्तीय संकट के बाद धीमापन आ गया था। 2009-10 में गैर-एसएलआर निवेशों की वृद्धि में मुख्यतः म्यूच्युअल फंडों ने योगदान दिया।

4.103 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय तथा व्यय दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आने की वजह से बैंकों की लाभप्रदता की वृद्धि दर में भी गिरावट देखी गई। 2009-10 में आरओए, आरओई, निवल ब्याज मार्जिन तथा स्प्रेड (निधियों के प्रतिलाभ तथा लागत का अंतर) सहित लाभप्रदता के प्रत्येक संकेतक में समेकित स्तर पर गिरावट देखी गई।

4.104 लाभप्रदता में गिरावट आने के अलावा, 2009-10 की उभरती चिंता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता के संबंध में थी। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में समग्र स्तर पर लगभग 0.14 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जिसमें प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दोनों की अनर्जक आस्तियों का योगदान था। इसके अलावा, अनर्जक आस्तियों में वृद्धि संदिग्ध तथा हानि वाली आस्तियों की वजह से हुई थी जो बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता के गिरते स्तर को दर्शाती है।

4.105 जहां सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई, वहीं समग्र स्तर पर प्रावधानों के कवरेज अनुपात में गिरावट दर्ज हुई जो

अनर्जक आस्ति से जुड़ी हानियों को पूरा करने के लिए जरूरी कुशन की मात्रा में आई गिरावट को दर्शाती है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआएआर बासेल II ढांचे की ओर अग्रसर होने के बाद भी 2008-09 में निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत से काफी अधिक था, जिसमें 2009-10 में और वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लीवरेज अनुपात में भी निरंतर वृद्धि देखी गई जो बैंकिंग प्रणाली के आस्ति आधार की तुलना में मूल (टियर I) पूंजी में आई सुदृढ़ता को दर्शाती है।

4.106 जहां तक वित्तीय समावेशन का संबंध है, ओईसीडी तथा एशिया के कई अन्य समकक्ष देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तथापि, हाल के वर्षों में जो स्वागतयोग्य गतिविधियां हुई हैं उनमें एक बैंक शाखाओं और एटीएम (जैसा कि प्रति बैंक शाखा/एटीएम के पीछे जनसंख्या में आई गिरावट से स्पष्ट होता है) की संख्याओं में निरंतर वृद्धि होना है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखाओं तथा एटीएम की संख्या में वृद्धि की दर ग्रामीण भारत में अधिक रही है। सूक्ष्म वित्त, जो भारत में वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरकर आया है, में 2009-10 में और वृद्धि हुई विशेष रूप से एसएचजी बैंक लिकेज कार्यक्रम की तुलना में एमएफआइ लिकेज कार्यक्रम के अंतर्गत। देशी बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल रहे हैं परंतु 2009-10 में कृषि तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत रूप से पीछे रहे हैं।

4.107 जहां तक बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास का संबंध है, 2009-10 की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा किया जाना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान का लग जाना रहा है।

4.108 अंत में, निकट भविष्य में उभरते जोखिम तथा प्रतिलाभ में सामंजस्य बनाये रखने के लिए बैंकों को आस्ति की गुणवत्ता तथा विवेकपूर्ण प्रावधान पर उचित ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को समर्थन देना होगा। इसके अलावा, बैंकों को स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट निरपेक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इससे जनसंख्या के बृहद हिस्से को औपचारिक वित्त के दायरे में लाने तथा समता के साथ भावी आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।